प्रभात

अन्दर के पन्नों पर ...

★ एसजेडसी सचिव कॉमरेड कोसा का साक्षात्कार ... 4
★ फासीवादी 'जन जागरण' अभियान का उद्देश्य ... 12
★ शहीदों को श्रद्धांजली ... 20
★ लन्दन बम हमलों के लिए ब्लेइर गिरोह जिम्मेदार... 27
★ मधुबन के शौर्यपूर्ण हमले ... 28
★ भारत-अमेरिका फौजी समझौते को रद्द करो ... 29
★ पीएलजीए के सफल हमले ... 31
★ महंगाई बढ़ाने वाली वैट प्रणाली ... 32
★ छत्तीसगढ़ को लूट का चरागाह बनाने की साजिश ... 36

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

दण्डकारण्य में जनयुद्ध की 25वीं वर्षगांठ का विशेषांक

वर्ष - 18 **अंक - 3&4** **जुलाई-दिसम्बर 2005** **सहयोग राशि - 10 रुपए**

दण्डकारण्य में जनयुद्ध की 25वीं वर्षगांठ

क्रान्तिकारी जोशोखरोश के साथ मनाओ !

प्यारे क्रांतिकारी लोगो,

दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन के 25 बरस पूरे हो गए हैं. इन 25 बरसों में हमने कई अनुभव हासिल किए हैं. कई कठिनाइयों का सामना करते हुए, कुर्बानियों की राह में अपनों के बिछड़ जाने के दुख के आंसुओं को पोंछते हुए हम सब बहाव के खिलाफ तैरते आये हैं. इस दौरान आंदोलन में कई मोड़ आए हैं. राजनितिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सैनिक क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों के चलते जन राजसत्ता गठित होकर उसका विस्तार हो रहा है. यहां स्थापित हो रही जनता की वैकल्पिक राज्यव्यवस्था भारत की दबी-कुचली जन समुदायों के लिए आशा की किरण बन रही है. यह भारत के शोषक शासक वर्गों के दिलों में कंपकंपी पैदा कर रही है. तमाम देशवासियों से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व में आंदोलित होने की अपील करते हुए हम दण्डकारण्य में जनयुद्ध की 25वीं वर्षगांठ जोर-शोर से मनायेंगे. क्रांतिकारी जनयुद्ध का 25 बरस पूरा होना हमारे देश के इतिहास में ही अनोखी घटना है. यह इस बात को साबित करता है कि दीर्घकालीन जनयुद्ध पर आधारित हमारी क्रांतिकारी कार्यदिशा सही है.

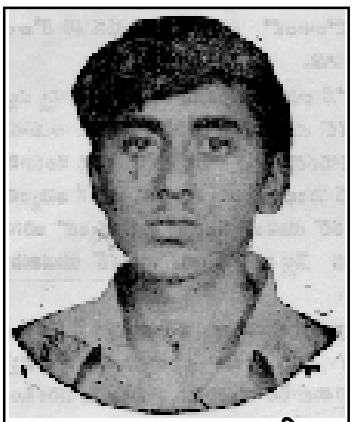

दण्डकारण्य का पहला शहीद
कॉमरेड पेद्दि शंकर

वह 2 नवम्बर 1980 का दिन था. महाराष्ट्र के गड़चिरोली जिले में उस दिन कामरेड पेद्दि शंकर का खून बहा. दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास के पन्नों पर अपने खून की स्याही से दस्तखत करने वाला पहला शहीद था वह. तब से लेकर आज तक इन 25 बरसों में 300 से ज्यादा कामरेड़ों ने दुश्मन के साथ लड़ते हुये अपनी अनमोल जानें कुर्बान कीं. इनमें केन्द्रीय स्तर के नेताओं से लेकर पार्टी कार्यकर्ता-नेता, जनमुक्ति छापामार सेना के योद्धाओं, कमाण्डरों,जन संगठनों के कार्यकर्ताओं-नेताओं एवं क्रांति के हमदर्दों तक शामिल हैं. इन तमाम योद्धाओं की कुर्बानियों का ही नतीजा है, आज की हमारी यह उपलब्धि. हमारी पार्टी के संस्थापक नेता द्वय कामरेड़ चारु मजुमदार और कामरेड़ कन्नाई चटर्जी की क्रांतिकारी स्फूर्ति एवं प्रेरणा से लैस होकर आखिरी सांस तक अमर शहीदों के अधूरे सपनों को पूरा करने की शपथ लेते हैं. देश में जनता की जनवादी क्रांति को सफल बनाकर समाजवाद की स्थापना के लिये संघर्ष करते हुए अंततः कम्युनिस्ट (साम्यवादी) समाज का निर्माण करने का एक बार और ऐलान करते हैं.

आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र के सरहदों में स्थित विशाल

2 से 31 दिसम्बर तक गांव-गांव में सभा-सम्मेलनों, रैलियों, मशाल जुलूसों व प्रदर्शनों का आयोजन कर क्रान्ति का संदेश जन-जन तक पहुंचाओ!

जंगली इलाका दण्डकारण्य कहलाता है. घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों,जीवनदियों, उपजाऊ जमीन एवं अकूत प्राकृतिक संपदाओं एवं संसाधनों से भरपूर धरातल है. पीढ़ियों से जारी शोषण और उत्पीड़न के बीच जिंदा लाशों की तरह जीवन-यापन करने वाले लाखों आदिवासियों की धरती है यह. यह भारत के क्रांतिकारी आन्दोलन के रणनीतिक महत्व के इलाकों में से एक है. जनयुद्ध के संचालन के लिए, जनसेना के निर्माण के लिए यह अनुकूल इलाका है. इसलिए मुक्तांचल के लक्ष्य के साथ क्रांतिकारी आंदोलन यहां फैल गया. तेलंगाना आंदोलन के लिए पृष्ठभाग के हिसाब से दण्डकारण्य में छापामार इलाके का गठन करने का निर्णय तत्कालीन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [पीपुल्सवार] ने अपने बारहवें आंध्रप्रदेश राज्य सम्मेलन में लिया था. अप्रैल-जुलाई 1980 के बीच 7 दस्तों ने (40 क्रांतिकारी) बस्तर, चंद्रपुर (वर्तमान गड़चिरोली), आदिलाबाद, पूर्वी एवं पश्चिम गोदावरी एवं करीमनगर-वरंगल जिलों के सरहदी जंगलों में कदम रखा था.

क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार को रोकने सभी राज्यों के पुलिस बलों ने दमनकारी कार्यवाहियों पर अमल करना शुरू किया. सरहदों पर पुलिस बलों को तैनात किया गया. देखते ही गोली मारने के आदेश दिये गए थे. सरकारी बंदूकों की पहरेदारी के बीच ही अपने दस्तों ने कामकाज को आगे बढ़ाया. आदिलाबाद से महाराष्ट्र में कदम बढ़ाने के दूसरे ही दिन कामरेड़ पेद्दि शंकर को शहादत हासिल हुई. क्रांतिकारियों के खिलाफ पुलिस नीचतापूर्ण दुष्प्रचार करने लगी. दस्तों को पैर जमाने से रोकने लिए ढेरों असफल प्रयास किए गए. लेकिन इन सबका प्रतिरोध करते हुऐ क्रांतिकारी आंदोलन दण्डकारण्य में मजबूती से खड़ा हुआ. इतना ही नहीं, बीते 25 बरसों में उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई और वह कई दिशाओं में फैल गया.

''जंगल पर आदिवासियों को ही सभी अधिकार'',''जोतने वालों को जमीन'',''जनता को जनवाद'', आदि नारों से जनता में काम शुरू किया गया. आदिवासी इतिहास के वीर योद्धा गेंदसिंग, बाबूराव सड़मेक, गुण्डादुर, अल्लूरी सीताराम राजू, कोमुरम भीम, आदि की संघर्षमय विरासत से लैस दण्डकारण्य की जनता ने फिर एक बार संघर्ष के लिए कमर कस ली. पल-पल परेशान करने वाले जंगलात अधिकारियों के खिलाफ पहला बिगुल बजाया. उनके अत्याचारों पर लगाम कस दी. जहां तक सम्भव हो, जगंल से उन्हें खदेड़ दिया. ''यह जंगल हमारा ही है'' - आदिवासियों ने यह ऐलान किया. वाजिब मजदूरी की मांग को लेकर जनता ने थापर जैसे बड़े पूंजीपतियों तथा तेन्दुपत्ता ठेकेदारों को झुका दिया.

गांवों में दुष्ट मुखियाओं द्वारा जारी बेगारी, जुल्म, ज्यादतियां तथा परंपराओं के नाम पर जारी उत्पीड़न, जुर्माना आदि से परेशान जनता ने लड़कर उनकी हुकूमत को ध्वस्त किया. पच्चीस बरसों की लड़ाई के फलस्वरूप दण्डकारण्य में आज एक भी भूमिहीन आदिवासी किसान नहीं है. राज्य हिंसा, यौन उत्पीड़न, परम्पराओं के नाम पर जारी हिंसा एवं जुल्म के खिलाफ महिलाओं ने संगठित होकर आंदोलन छेड़ दिए. इस तरह 80 के दशक में समूचे दण्डकारण्य में विभिन्न किस्म के जनसंघर्षों का ज्वार आया. इसके साथ ही सरकारी दमन बढ़ गया. इसे नाकाम करने के लिए राज्य का सामना करना अवश्यक हो गया था. इसलिए जनता ने सरकार के खिलाफ जनयुद्ध शुरू किया.

गांव-गांव में किसान संगठन अस्तित्व में आये. क्रांतिकारी आंदोलन ने पुरुषों को ही नहीं महिलाओं एवं बच्चों को भी संगठित किया. गावों में संगठनों का प्रभुत्व कायम हुआ. क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रारांभिक दिनों में जन सगंठनों ने खुलेआम काम काम किया. लेकिन बाद में बढ़ते दमन के दौर में इन्हें गुप्त रूप से काम करना पड़ा. दमन के दौरान कुछ जगहों पर जन संगठन ध्वस्त हो गए. लेकिन अस्थाई तौर पर. सन 1995 तक दण्डकारण्य के विभिन्न जन संगठनों में 60 हजार महिलाएं एवं पुरुष संगठित हुये थे. आज यह संख्या डेढ़ लाख पार कर गयी है. प्रांरभ में जन संगठन के कार्यकर्ता ही लाठियां लेकर सुरक्षा की जिम्मेदारियां निभाईं और सांमती मुख्याओं के हमले से संगठनों की रक्षा की. बाद में ग्राम रक्षा दल अस्तित्व में आये. अब जन मुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) के आधार बलों ने (मिलिशिया) जन संगठनों की सुरक्षा की जवाबदारी अपने हाथों में ले रखी है.

जनता पर जारी दुश्मन का फासीवादी दमन मध्ययुगीन बर्बरता को भुला देनेवाला है. बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, क्रूरतम यातनायें, फर्जी मुठभेड़ हत्याएं, लापता करना, महिलाओं पर सामूहिक अत्याचार, घरों को जलाना, सम्पति को नष्ट करना, जिला बदर की कार्यवाहियां, भयानक काले कानूनों के तहत फर्जी केस लगाकर बरसों तक जेलों में बंद करना, सख्त एवं कारावास की लम्बी सजाएं आदि आम बात हो गई हैं. बेवरटोला की चार महिलाओं तथा मंगेझरी के 13 ग्रामीणों को लापता किया गया है. इनके अलावा जीरमतराई, पल्ली, धर्मा, कोतरापाल आदि कई गावों में फर्जी मुठभेड़ों में हत्याएं की गईं, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किए गए. फिलहाल बस्तर में जारी 'जन जागरण' अभियान के तहत, जून से अक्टूबर 2005 तक पुलिस बलों व गुण्डों ने 100 से ज्यादा लोगों की हत्या की, 50 से ज्यादा गांवों को जला दिया, दर्जनों महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया तथा सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया.

इन 25 बरसों में दस्तों का प्रतिरोध जनमुक्ति छापामार सेना के कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियान के रूप में विकसित हुआ है. दस्तों, पलटनों, कम्पनियों में विकसित होते हुये जनमुक्ति सेना में तब्दील होने की दिशा में जनयुद्ध तेज हो रहा है. जन मिलिशिया साहसिक एवं अद्भुत हमले कर रहा है. विगत 25 सालों के जनयुद्ध में सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान हताहत हुए. दारागड्डा,आलमपल्ली, कोयनगुडा, तर्रेम, तिगनपल्ली, लोतुवागू, मानपूर, वाकुलवाही, दाराकोण्डा, गीदम, कोरापुट आदि कई हमलों ने दुश्मन को हिलाकर रख दिया. हाल ही, 3 सितम्बर 2005 को बीजापुर के निकट पोंजेर में पीएलजीए के हमले में सुरुंग-रोधी

प्रिय पाठको,

हमें खेद है कि अनिवार्य कारणों से हुए विलम्ब के चलते 'प्रभात' के दोनों अंक (जुलाई-सितम्बर 2005 और अक्टूबर-दिसम्बर 2005 के अंक) हमें एक साथ प्रकाशित करना पड़ रहा है. पिछले अंक के बाद से हुई देरी से पाठकों को असुविधा हुई होगी, इसके लिए हमें खेद है. पर हमें खुशी भी है कि इस दोहरे अंक को हम दण्डकारण्य के जनयुद्ध के 25 बरस पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेषांक के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं. आशा है पाठकगण इस विशेषांक का स्वागत करेंगे.

- सम्पादक मण्डल

वाहन ध्वस्त हो गया और 24 भाड़े के जवान मारे गए. अब तक दुश्मन से छीने गए सैकड़ों हथियारों से पीएलजीए मजबूत हुई.

क्रांति यानी राजसत्ता की समस्या है. राजसत्ता हासिल करने के लिये जनयुद्ध की जरूरत होती है. वर्तमान राजसत्ता शोषक वर्गों के हाथों में है. पुलिस, अर्ध सैनिक बलों के अलावा लाखों की सेना, कोर्ट कचहरी, जेल, थाने , विधायिका एवं नौकरशाही सब मिलकर उसकी रक्षा के लिए समर्पित हैं. यही राज यंत्र है. इस मजबूत राज्य यंत्र के खिलाफ पिछले 25 सालों से जनता लड़ रही है. यहां की जनता संसदीय चुनावों का पूरी तरह से बहिष्कार कर रही है. हजारों पुलिस बलों को उतारकर चुनाव प्रकिया को सफल बनाने के सरकार के प्रयासों को लोग असफल कर रहे हैं. शोषक वर्गों को अपने वोट (मत) देने से इनकार करते हुए वे अपने गावों में अपनी सरकारों को स्वंय चुन रहे हैं. यह प्रक्रिया विगत 10 सालों से जारी है. जनता के द्वारा चुनी जाने वाली जनताना सरकारें पूरी तरह जनता के प्रति जवाबदेह बनी हुई हैं.

महिलाओं को संगठित करने क्रांतिकारी आंदोलन ने गंभीर प्रयास किए. उन्हें बीते जमाने की परम्पराओं की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत दी. आर्थिक एवं यौन शोषण, पारिवारिक एवं राजकीय हिंसा के बीच पिसने के बजाय उन्हें हथियारबन्द होने का आहवान किया. महिला मुक्ति हासिल करने के लिये हथियारबन्द होना आवश्यक है –इस बात से उन्हें अवगत कराया. जनयुद्ध ने यह साबित किया कि हर किस्म के काम करने वाली महिलायें जनयुद्ध की वीर योद्धा भी बन सकती हैं.

विगत 25 बरसों से जनयुद्ध लगातार तेज हो रहा है एवं उसका विस्तार हो रहा है. आज बस्तर एवं गडचिरोली जिलों को मिलाकर दण्डकारण्य कह रहे हैं जोकि 5 डिवीजनों के आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है. वर्तमान दण्डकारण्य आंदोलन का मैदानी इलाकों में विस्तार को रोकने की दुश्मन ने ठान ले रखी है. क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार को रोकने का मतलब है हवा को हवालात में बंद करने कोशिश, जोकि असंभव है. हमारे देश में लम्बे समय से दो क्रांतिकारी धाराओं के रूप में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करते आ रही दो पार्टियां – भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) (पीपुल्सवार) और भारत का माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र का विगत साल 21 सितंबर को विलय हो गया है. और इसके फलस्वरूप भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन हुआ. इससे दण्डकारण्य का क्रांतिकारी आंदोलन पूरे देश के क्रांतिकारी आंदोलन का अभिन्न अंग बन गया है. पड़ोसी देश नेपाल में जारी जनयुद्ध लंबे–लंबे डग भरते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है. नेपाल से झारखंड, दण्डकारण्य से होते हुए आंध्र प्रदेश तक एक विशाल जंगली इलाके पर माओवादी जनयुद्ध की लालिमा छाने लगी है. जनयुद्ध का सिर्फ भौगलिक मायने में ही विस्तार नहीं हो रहा है बल्कि वह समाज के समूचे पीड़ित तबकों की जनता के बीच जा रहा है. मजदूर वर्ग, छात्र, बुद्धिजीवि और निम्न पूंजीवादी ताकतें आज जनयुद्ध के पक्ष में शामिल हो रही हैं.

विगत 25 वर्षों के दण्डकारण्य जनयुद्ध के नतीजे हमारे सामने हैं. साम्राज्यवाद एवं भारत के शासक वर्ग साल–दर–साल अंतहीन संकट में धंसते जा रहे हैं. दुनिया के लोगों का नंबर एक दुश्मन अमेरिकी साम्राज्यवाद अपने देश के अलावा दुनिया के अनेक देशों के लोगों की नफरत का शिकार हो रहा है. इराक, अफगानिस्तान जैसे देशों के लोगों के हमलों से उसे धक्के पे धक्का लग रहा है. आंतक के सहारे जन आंदोलनों को कुचलने की अपनी लाख कोशिशों के बावजूद वह असफल ही हो रहा है. उलटे जन आंदोलन और उग्र होते जा रहे हैं. हमारे देश में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा अमल में लाई जा रही साम्राज्यवाद परस्त आर्थिक नीतियों – उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के चलते लोग अकथनीय तकलीफों के शिकार हो रहे हैं. इसके खिलाफ वे संघर्ष कर रहे हैं. क्रांतिकारी परिस्थिति क्रांति के लिए काफी अनुकूल है. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की अगुवाई में लगातार फैलता जनयुद्ध पूंजीवादी व संशोधनवादी पार्टियों को पूरी तरह से नंगा कर रहा है.

आज की अद्भुत क्रांतिकारी परिस्थितियों का फायदा उठाकर जनयुद्ध के विजय–पथ पर तेजी से एवं लंबे–लम्बे डग भरते हुए आगे बढ़ेंगे. देश के कोने–कोने में छापामार युद्ध को तेज करेंगे. हमारा युद्ध कठिनाइयों से भरा है. लेकिन हम दृढ़ संकल्प के साथ इनका सामना करेंगे. हम ऐलान करेंगे कि यह सदी हमारी है. मजदूर, किसान, छात्र, युवा, महिला एवं बुद्धिजीवियो! आओ! जनयुद्ध में शामिल हो जाओ. दुश्मन की राजसत्ता को उखाड़ फेंको. इलाकेवार राजसत्ता पर कब्जा करो. दण्डकारण्य को मुक्तांचल में तब्दील करने के लक्ष्य से यहां जारी जनयुद्ध की हर संभव तरीके से मदद करो. जनयुद्ध पर शासक वर्गों के द्वारा जारी दमनकारी युद्ध की निंदा करो. आओ! जन संघर्षों के जरिए इस दुनिया को जीतेंगे! शोषक वर्गों को दफना देंगे ! गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, भूख, भय और हर किस्म के भेदभाव से मुक्त एक खुशहाल व जनवादी भारत का निर्माण करेंगे. ✶

(..... पेज 17 का शेष)

भूपालपट्टनम में कांग्रेसी नेता कोरम कन्नय्या, आदि कुछ बड़े नेताओं को भी जनता की मदद से पीएलजीए ने खत्म कर दिया. आत्मरक्षा की खातिर तथा अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जनता ने अनिवार्य रूप से कुछ गुण्डों को मार गिराया. इसे लेकर लुटेरे शासक वर्गों की तरफदारी करने वाले अखबार अब तक नक्सलियों के हाथों में 50–60 'आदिवासी' मारे जाने की खबरें छापकर हाय–तौबा मचा रहे हैं. दरअसल यह शासक वर्गों व पुलिस–प्रशासन की सोची–समझी साजिश है जिसके चलते कुछ गरीब और मासूम लोग भी डर या अन्य प्रलोभनों से 'सलवा जुडूम' गुण्डावाहिनी में शामिल हो रहे हैं. आज गांवों पर जितनी भयावहता के साथ हमले हो रहे हैं और जितनी पाशविकता के साथ लोगों की हत्या की जा रही है, उसके चलते जनता के सामने कुछ कट्टर गुण्डों का सफाया करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बच रहा है.

'जन जागरण' के नाम पर सरकार भ्रामक व झूठा प्रचार कर रही है. सचाई को दफनाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है. मारने या घर जलाने की धमकियां देकर कुछ लोगों को 'जन जागरण' में शामिल किया गया जो अब तथाकथित राहत शिविरों में रह रहे हैं. उनसे बेगारी करवाई जा रही है. उनके नाम पर आवंटित करोड़ों रुपए की धनराशि पुलिस–प्रशासन व नेता हड़पकर खा रहे हैं. अब 'राहत शिविरों' में रह रहे लोगों में भी असंतोष बढ़ रहा है. उधर कांग्रेस के अन्दर भी इस जुल्मी अभियान को लेकर घमासान बढ़ गया है. बहरहाल, जनता और उसकी अगुवाई कर रही पीएलजीए का व्यापक व जोरदार प्रतिरोध ही इस मध्ययुगीन पाशविक अभियान को पूरी तरह परास्त कर सकता है. लुटेरे शासक चाहे कितने भी दमन अभियान लाएं, जनता की ही विजय होगी – क्योंकि जनता ही इतिहास का निर्माता है. ✶

भाकपा (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव

कॉमरेड कोसा के साथ साक्षात्कार

(दण्डकारण्य में जनयुद्ध के 25 बरस पूरे होने के उपलक्ष्य में 'प्रभात' ने कॉमरेड कोसा के साथ बातचीत की. उन्होंने पिछले 25 बरसों से जारी जनयुद्ध के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली. आशा है इस बातचीत से पाठकगण को दण्डकारण्य आन्दोलन का संक्षिप्त परिचय मिलेगा. – सम्पादकमण्डल)

'प्रभात' : दण्डकारण्य में क्रान्तिकारी आन्दोलन की शुरूआत कब, कैसे और किस लक्ष्य से हुई?

कॉमरेड कोसा : आपातकाल के बाद 1977 में सम्पन्न लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी सरकार हार गई थी. जनता पार्टी सत्ता में आई थी. जनता पार्टी की सरकार ने मा–ले पार्टियों पर प्रतिबन्ध हटा दिया. जेलों में कैद क्रान्तिकारियों को रिहा कर दिया. तुरन्त ही हमारी पार्टी – यानी तत्कालीन भाकपा (मा–ले) की आन्ध्रप्रदेश राज्य कमेटी ने 'चलो गांवों की ओर' का नारा देकर छात्र–नौजवानों का किसानों में काम शुरू करने का आह्वान किया. उन्होंने गांवों में जाकर किसानों को उनकी समस्याओं पर गोलबन्द करना शुरू किया.

करीमनगर जिले के जगित्याल इलाके में जमींदारों के जुल्म और अत्याचारों से तंग आ चुके किसान बड़े पैमाने पर संघर्ष में कूद पड़े थे. उन्होंने जमींदारों को सड़कों पर खींच लाकर उनके जुल्म–अत्याचारों की सुनवाई कर उन्हें माकूल सजाएं दीं. उनकी सत्ता को ढहाकर किसानों ने संगठनों की सत्ता चलाना शुरू किया. लेकिन आन्ध्रप्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने तुरन्त ही किसानों के दमन की कार्रवाइयां शुरू कीं. जगित्याल और सिरसिल्ला तहसीलों को आशांत क्षेत्र घोषित किया था. हालांकि पार्टी का शुरू से ही रणनीतिक दृष्टिकोण रहा था. जगित्याल में उभरे किसान संघर्ष को जिले भर में तथा पड़ोस के वरंगल और आदिलाबाद जिलों में भी फैलाना शुरू किया. पिछले क्रान्तिकारी संघर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में नव जनवादी क्रान्ति को सफल बनाने के लक्ष्य के तहत करीमनगर–आदिलाबाद के किसान संघर्ष की रक्षा करने तथा उसे उच्च स्तर पर विकसित करने की रणनीति तैयार की गई. उसके तहत बगल में स्थित दण्डकारण्य के वनांचल में आन्दोलन का विस्तार करने का फैसला लिया गया. एक तरफ वहां के आदिवासियों को आन्दोलन में गोलबन्द करना, दूसरी ओर तब तक तेज हो चुके उत्तर तेलंगाना के करीमनगर, आदिलाबाद व वरंगल जिलों के आन्दोलन के लिए एक पृष्ठ इलाका तैयार करना इसका उद्देश्य था. इस तरह इस विशाल जंगली इलाके में गुरिल्ला युद्ध को तेज करते हुए आधार इलाके के लक्ष्य से गुरिल्ला जोन का निर्माण करने के परिप्रेक्ष्य से पार्टी ने 1980 में सात किसान छापामार दस्तों को दण्डकारण्य भेजा था.

'प्रभात' : आन्दोलन के शुरूआती दौर में आपने किन–किन चुनौतियों और समस्याओं का सामना किया?

कॉमरेड कोसा : शुरू में तो दस्तों का टिककर काम करना ही मुश्किल सा लग रहा था. तब तक पार्टी को जंगल में काम करने का कोई अनुभव नहीं था. दस्ते के ज्यादातर सदस्य छात्र जीवन से आए हुए थे जिन्हें जंगल में चलना, घूमना, खाना–पीना – ये सब नए–नए थे. दूसरी तरफ शुरू से ही सरकार और उसके पुलिस बलों के हमले भी होने लगे थे. खासकर बस्तर और गड़चिरोली (तब चन्द्रपुर जिला कहलाता था) जिलों में जनता को क्रान्तिकारी राजनीति से कोई पूर्व परिचय नहीं था. पुलिस–प्रशासन के द्वारा सुनियोजित रूप से शुरू किए गए दुष्प्रचार के प्रभाव से जनता दस्तों को देखते ही भाग जाती थी. वे यह प्रचार किया करते थे कि हम चोर हैं, डाकू हैं, गुण्डे हैं और महिलाओं को उठाकर ले जाएंगे, आदि–आदि. एक तरफ पुलिस के हमले जारी थे तो दूसरी तरफ जनता से सहयोग नहीं मिल रहा था. चूंकि जंगल के रास्तों से हम अनजान थे इसलिए इधर–उधर भटकते रहते थे. तभी, 2 नवम्बर 1980 को गड़चिरोली जिले के मोइबिनपेटा गांव में पुलिस ने दस्ते पर हमला किया जिसमें कॉमरेड पेद्दि शंकर की शहादत हुई. इस तरह कॉमरेड पेद्दि शंकर दण्डकारण्य का पहला शहीद बने. हालांकि इसके पहले भी पुलिस ने कई जगहों पर दस्ते का पीछा किया था, हमले की नाकाम कोशिशें की थीं. इन तमाम मुश्किलों के बीच ही हमारे सामने टिककर काम करने तथा आन्दोलन का निर्माण करने की चुनौतियां थीं. 'जनता ही इतिहास का निर्माता है' – इस स्फूर्ति से हमने जनता पर विश्वास रखा और इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया. जनता को भी सरकारी दुष्प्रचार से निर्मित भ्रम की स्थिति से बाहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा. वह जान गई कि सच क्या है और झूठ क्या है.

'प्रभात' : दण्डकारण्य आन्दोलन की शुरूआत के समय जनता की स्थिति कैसी थी?

कॉमरेड कोसा : यहां की जनता का जीवन कबीलाई तरीके की थी जोकि बहुत पिछड़ा हुआ था. आमतौर पर लोग जंगल पर निर्भर रहते हुए जिया करते थे. पर जनता को जंगल पर कोई अधिकार नहीं था. यह एक विरोधाभासी स्थिति थी. जंगल से कोई भी चीज लाने से वन विभाग वालों के जुल्म व शोषण का शिकार होना पड़ता था. मसलन, पत्ता तोड़ने, जलाऊ लकड़ी काटने, शिकार करने, घर बनाने, खेती करने – इन सभी के लिए लोगों को मारना–पीटना, जेलों में बन्द करना आम था. ऐसा एक भी परिवार नहीं रहा होगा जिसने वन विभाग वालों को जुर्माना नहीं भरा हो. दूसरी तरफ पुलिस वाले भी जनता पर जुल्म करते थे. शराब बनाने, जानवरों का शिकार करने और आपसी मारपीट के मामलों की थाने में शिकायत न करने के बहाने पुलिस लोगों को मारती थी, घूस वसूलती थी और झूठे केस लगाकर जेलों में ठूंस देती थी. और एक तरफ तरफ सेठ–साहुकार आदिवासियों को खुल्लमखुल्ला लूटा करते थे. जब आदिवासी महुआ, टोरा, साल बीज, झाड़ू, शहद आदि वनोपज इकट्ठे करके साहुकारों के यहां ले जाते हैं तो बहुत कम रेट लगाते थे, और जो वे बेचते थे बहुत ज्यादा भाव लगाकर बेचते थे.

दूसरी तरफ तेन्दुपत्ता ठेकेदार, पेपरमिल के मालिक और वन विभाग के अधिकारी लोगों को बहुत कम मजदूरी देकर ज्यादा काम करवाते थे.

महिलाओं का यौन शोषण बहुत ज्यादा होता था. पुरुष मजदूरों के साथ मारपीट एक आम विषय था. पटवारी भी जनता का शोषण करते थे. कुछ गांवों में पटेल, सरपंच, पुजारी, कोतवाल, आदि गांव के मुखिया उनसे सांठगांठ करते थे. उनकी लूटखसोट में शामिल हुआ करते थे.

कबीलाई मुखियाओं से उभरकर सत्ता के गलियारों तक पहुंच बनाने वाले नेता भी थे यहां. वे एक तरफ कबीलाई व्यवस्था को कायम रखते हुए ही दूसरी तरफ संसदीय राजनीति में शामिल होकर, खुद को आदिवासी नेता बताकर चुनाव जीतते थे. जनता का दोहरा शोषण करते थे वे. अहेरी (गड़चिरोली) का महाराजा विश्वेश्वरराव आत्रम, बस्तर में बोड्डा मांझी (महेन्द्र कर्मा का बाप) जैसे लोग रीति-रिवाजों की आड़ में जनता पर सिक्का जमाए हुए थे. बेगारी काम करवाते थे. छोटी-छोटी बातों पर जुर्माना वसूलते थे. यहां तक कि किसी व्यक्ति की शादी भी हुई तो उससे 'पट्टी' के नाम से पैसा वसूलते थे. अगर बात तलाक की हो तो और ज्यादा पैसा जुर्माने के रूप में वसूलते थे. ऐसे मांझी, मालगुजार, शेंड़िया, भूमिया गण आदिवासी रीति-रिवाजों की आड़ में आदिवासियों का घोर शोषण करते थे.

अंग्रेजी शासन के दौरान 1894 में भू-अर्जन अधिनियम तथा 1927 में भारतीय वन अधिनियम बने थे. इन कानूनों ने जंगल पर आदिवासियों के अधिकार को समाप्त किया था. उसके बाद से आदिवासी अपने ही जंगल में पराए होते आए हैं. 1947 में सत्ता हस्तांतरण के बाद भी इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि आदिवासियों का शोषण और भी बढ़ गया. यहां दण्डकारण्य के कई इलाकों में आदिवासी अपनी परम्परागत चलायमान खेती को छोड़कर स्थाई खेती अपनाने लगे थे. यह प्रक्रिया कई सालों से चल रही थी. लेकिन कठोर वन कानूनों के चलते उन्हें जमीन नहीं मिलती थी जिस पर वे खेती करते हुए जी सकें. उनके विकास के रास्ते में एक जबर्दस्त रुकावट आई हुई थी. वे मजबूर होकर खेतीबाड़ी छोड़कर मजदूरी काम अपनाने लगे थे. ऐसी कई मुश्किलों से यहां के आदिवासी परेशान थे. ऐसी स्थिति में हमने यहां कदम रखा.

'प्रभात' : आपने किन-किन मुद्दों पर जनता को गोलबन्द करना शुरू किया?

कॉमरेड कोसा : सबसे पहले तेन्दुपत्ता मजदूरी बढ़ाने के मुद्दे को लेकर जनता को गोलबन्द किया था. इस संघर्ष में जनता विजयी रही. इसके बाद जनता के दिल में पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ गया. उन्हें यकीन हो गया कि हम नक्सलवादी चोर-डाकू नहीं हैं. तबसे जनता ने अपनी कई समस्याएं दस्तों के सामने उठाना शुरू किया. खासतौर पर वन विभाग वालों के जुल्म, अत्याचार व शोषण से सम्बन्धित समस्याएं. मजदूरी कामों के दाम बढ़ाने जैसे मुद्दे भी सामने आए. इन सभी मुद्दों को उठाते हुए ही हमने जनता को संगठन में गोलबन्द करना शुरू किया. संगठन में गोलबन्द करते समय से ही जनता को सशस्त्र क्रान्ति के जरिए राजसत्ता छीनने सम्बन्धी राजनीति से अवगत कराना शुरू किया. जनता भी अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हुए अपने अनुभव से समझने लगी थी कि इन सारी समस्याओं के तार राजसत्ता के सवाल से जुड़ा हुआ है. जब जनता अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष शुरू करती है तो पुलिस उस पर टूट पड़ती. इससे जनता साफ तौर पर समझ जाती कि अपनी समस्याओं को हल करने के लिए पूरी राज्य मशीनरी के खिलाफ संघर्ष करना जरूरी है. इस प्रकार सरकार के खिलाफ संघर्ष बढ़ता गया.

'प्रभात' : आन्दोलन के इलाके का विस्तार कैसे हुआ? क्या-क्या बढ़लाव हुए?

कॉमरेड कोसा : उपरोक्त समस्याओं को लेकर जब जनता ने संघर्ष शुरू किया तो उसका प्रभाव आसपास के कई इलाकों में फैल गया. इससे नए इलाकों में आन्दोलन का विस्तार करने में सुविधा हुई. नए इलाकों में विस्तार को रोकने हेतु दुश्मन द्वारा की गई तमाम कोशिशों को नाकाम करने में हम समर्थ हुए. गड़चिरोली में दक्षिणी छोर पर स्थित सिरोंचा से शुरू कर दस सालों के अन्दर, यानी 1990 तक उत्तर में भण्डारा जिले के देवरी (जोकि अब गोंदिया जिले में है) तक और उससे भी आगे मध्यप्रदेश के बालाघाट-मण्डला जिलों तक आन्दोलन का विस्तार हुआ. यह लम्बाई में कम से कम 400 किलोमीटर का इलाका है. बस्तर में कोंटा से शुरू कर 1990 तक कोइलीबेड़ा तक आन्दोलन का विस्तार हुआ. अब इससे भी आगे विस्तार की प्रक्रिया जारी है. दक्षिण में अभी कटेकल्याण की तरफ हमारे दस्ते गए हुए हैं.

1990 तक दण्डकारण्य क्षेत्र आन्ध्र के आदिलाबाद, पूर्वी गोदावरी, और विशाखा जिलों, मध्यप्रदेश के बस्तर व राजनांदगांव (जो अब छत्तीसगढ़ में हैं) तथा बालाघाट जिलों, महाराष्ट्र के गड़चिरोली, चन्द्रपुर और भण्डारा जिलों तथा उड़ीसा के कोरापुट जिले से युक्त था. यह सारा इलाका 5 डिवीजनों में बंटा हुआ था. 1995 में क्रान्तिकारी आन्दोलन की रणनीतिक जरूरतों के मद्देनजर आन्ध्र के आदिलाबाद जिले को उत्तर तेलंगाना में तथा पूर्वी गोदावरी व विशाखा जिलों को आन्ध्रप्रदेश में मिलाने का निर्णय हुआ. 2000 में उड़ीसा का कलिमेला इलाका और बालाघाट-गोंदिया संयुक्त डिवीजन दण्डकारण्य से अलग हो गए. बालाघाट-गोंदिया इलाका अब एक अलग छापामार जोन के रूप में विकसित हुआ है, जबकि उड़ीसा का इलाका आन्ध्र-उड़ीसा बार्डर स्पेशल जोन में सम्मिलित हो गया जोकि एक और अलग छापामार जोन के रूप में उभरा है. फिलहाल दण्डकारण्य में छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र और महाराष्ट्र का गड़चिरोली जिला शामिल हैं और यह पूरा क्षेत्र पांच डिवीजनों में बंटा है- गड़चिरोली, उत्तर बस्तर, माड़, पश्चिम बस्तर और दक्षिण बस्तर.

'प्रभात' : शत्रु दमन किन-किन इलाकों में कैसे चला? उसका मुकाबला आप कैसे कर सके?

कॉमरेड कोसा : शुरू से ही दस्तों का सफाया करने की मंशा से दुश्मन ने पूरा जोर लगाया था. पुलिस के हमलों का पलटा जवाब देते हुए ही जनता को गोलबन्द कर उसे संघर्ष में उतारा गया. तबसे एक तरफ जनता पर और दूसरी तरफ गुरिल्ला दस्तों पर दमन तेज हुआ. दुश्मन ने जनता को गिरफ्तार करना, यातनाएं देकर जेलों में ठूंस देना, आदि तरीकों में दमनचक्र चलाते हुए दूसरी तरफ दस्तों पर हमले किए. जन विरोधी तत्वों को पुलिस मुखबिर बनाकर आन्दोलन का सफाया करने की कोशिशें तभी से जारी हैं. आन्दोलन पर राजनीतिक तौर पर हमला करने के लिए गांवों में जन विरोधी तत्वों व वर्ग दुश्मनों को इकट्ठे करके जन संगठनों में फूट डालने या सफाया करने की घिनौनी कोशिशें की गईं.

फरवरी 1984 में गड़चिरोली डिवीजन में आदिवासी किसानों ने अपने संगठन - एकेएसएस (आदिवासी किसान शेतमजदूर संगठन) का पहला अधिवेशन कमलापुर में आयोजित करने की कोशिश की तो

शरद पवार की महाराष्ट्र राज्य सरकार ने व्यापक पुलिस दमन चलाकर सैकड़ों लोगों व संगठन नेताओं को गिरफ्तार कर आयोजन को होने नहीं दिया. उसी समय गांवों में बड़े पैमाने पर दमनचक्र चलाया गया. खासकर अहेरी, सिरोंचा इलाकों में पुलिस ने संगठन नेताओं को पकड़कर उन्हें जीप से बांधकर दौड़ाया. उस दौर में अहेरी इलाके में हर गांव में लोगों की पिटाई की गई. बस्तर डिवीजन में भी शुरू से ही पुलिस दमन जारी था. गांव के दुष्ट मुखियाओं और वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने सांठगांठ कर दस्तों का सफाया करवाने की साजिश की. जहां से भी दस्ते की खबर मिलती तो वे पुलिस को दिया करते थे. पार्टी ने आत्मरक्षा के दावपेंच अपनाकर जनाधार को बढ़ाते हुए जनता को जन संघर्षों में बड़े पैमाने पर उतारकर आन्दोलन को मजबूत बनाने की कोशिश की. दुश्मन के हर हमले में जनता शुरूआती दिक्कतें झेलने के बावजूद संभल गई. वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और भी दृढ़ता के साथ संघर्ष में कूद पड़े.

1984 के पहले इक्के-दुक्के गांवों में जनता ने पुलिस का मुकाबला करते हुए उससे दो-दो हाथ भी किए थे. फिर 1985 से लेकर 1990 तक पुलिसिया हमलों का जनता ने कई गांवों में पलटकर जवाब दिया. एम्मेलकस्सा, गुरजा, टव्वेटोला, बंडारुपल्ली, जिम्मलगट्टा, आदि कई गांवों में निहत्थे लोगों ने अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुलिस वालों की पिटाई की थी. उनके जुल्मों व अत्याचारों पर लगाम कस दी. 1990 में सुरसुंडी गांव में रैली निकाल रही निहत्थी जनता पर वहां के राजा की शह पर पुलिस ने लाठीचार्ज और गोलीबारी की जिसमें दयाराम नामक एक किसान शहीद हो गया. लेकिन जनता ने बहादुरी के साथ इस हमले का मुकाबला कर पुलिस से दो रायफलें छीन लीं.

1990 में महाराष्ट्र सरकार ने एक्शन प्लान के तहत करोड़ों रुपए खर्च करके कमाण्डो बल तैयार किया और उसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया. मुम्बई में माफिया से निपटने में दक्षता हासिल अधिकारियों को गड़चिरोली में तैनात किया. बस्तर इलाके में पुलिस की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी की गई. चम्बल की घाटी में डकैतों से लड़ने का अनुभव हासिल पुलिस बलों तथा अधिकारियों को तैनात किया गया. पूरे दण्डकारण्य में थानों की संख्या बढ़ाई गई. मध्यप्रदेश में भाजपा की सुन्दरलाल पटवा सरकार ने महेन्द्र कर्मा की अगुवाई में 1990-91 में पहला 'जन जागरण' अभियान चलाया था. महिलाओं के साथ बलात्कार, लूटपाट, हत्या, आदि क्रूर तरीके अपनाकर क्रान्तिकारी आन्दोलन का सफाया करने की कोशिश की थी. उस पहले झटके में कई लोगों ने जन संगठनों से इस्तीफा दिया था. जनता भयभीत हो गई थी. लेकिन पार्टी के नेतृत्व में धीरे-धीरे जनता फिर संगठित हो गई और 'जन जागरण' के प्रमुख गुण्डों का सफाया कर दिया. 1995 तक गांवों में जन संगठन – डीएकेएमएस की पकड़ मजबूत हो गई. दस्तों में बड़े पैमाने पर नौजवानों के भर्ती होने की प्रक्रिया शुरू हुई. उधर गड़चिरोली में 1987 से 1992 तक दस्तों में भर्तियां बढ़ गईं. दर्जनों नौजवान छापामार दस्तों में शामिल हो गए, जिससे आन्दोलन का विस्तार करने में मदद मिली.

महाराष्ट्र में भी पुलिस ने अहेरी महाराज के नेतृत्व में 'जन जागरण' की तर्ज पर 'शांतिसेना' नामक गुप्त संगठन शुरू किया था. जन विरोधी तत्वों व मुखियाओं की अगुवाई में कुछ युवकों को पैसे का लालच देकर संगठित किया गया था. पुलिस ने जंगल में इन्हें ट्रेनिंग देकर दस्तों पर हमले करके उनका सफाया करने की जिम्मेदारी दी थी. लेकिन क्रान्तिकारी जनता ने इस साजिश को तुरन्त ही समझकर इस संगठन को शुरू में ही खत्म कर दिया. इसका नेता बीरा वरसे का सफाया कर दिया. इससे जन विरोधियों व पुलिस का षड़यंत्र बुरी तरह विफल हो गया.

महाराष्ट्र में 1992 से क्रूरतम हमला शुरू हुआ. पहले देवरी-टिप्रागढ़ से शुरू हुआ वह दमनचक्र पूरे गड़चिरोली डिवीजन में फैल गया. जनता को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार करना, क्रूरतम यातनाएं देना, आत्मसमर्पण करने का दबाव डालना, आदि तरीके मुख्य रूप से अपनाए गए. 1993-94 तक यह दमन और भी भयानक रूप धारण कर लिया. आन्दोलन के मजबूत गांवों, जहां के लोगों ने दुश्मन के सामने झुकने से इनकार किया, संगठन नेताओं को पकड़कर लोगों के सामने ही गोली मारकर मुठभेड़ की कहानी गढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई. दर्जनों लोगों को पुलिस ने गोली मार दी. भण्डारा जिले के देवरी तहसील के मंगेझरी गांव में पुलिस ने 14 लोगों को पकड़कर उनकी हत्या की और लाशें चुपचाप दफनाकर उन्हें लापता बताया. बेवरटोला गांव की चार किशोरियों को पकड़कर उनके साथ सामूहिक बलात्कार कर उनकी हत्या की. इसके बाद उनका कोई अता-पता नहीं मिला. गांव रेगुलवाई में डीएकेएमएस नेता नैताम लक्ष्मण और पोरतेटि लिंगन्ना को, गांव तोंडेरा में वेलादि शंकर, बंगारमपेट में तर्रेम शंकर, आरेवाड़ा में दो व्यक्तियों, वेंकटापुरम में आत्रम हनुमंतु और नारायण को पुलिस ने भून डाला, झूठी मुठभेड़ की कहानियां गढ़ दीं. दर्जनों युवाओं को इस प्रकार मार डाला गया.

1989 में क्रान्तिकारी आन्दोलन दक्षिण बस्तर से उत्तर बस्तर में फैल गया. दुश्मन ने इस फैलाव को रोकने के लिए पूरा जोर लगाकर दस्तों पर हमले किए. केसकाल इलाके के दुरघाटी में हुई एक मुठभेड़ में कॉमरेड्स बैसाख और लछिन्दर शहीद हो गए. इसके बाद भी हमलों का सिलसिला चलता ही रहा. शुरू से ही जन संगठनों को कमजोर करने की मंशा से जनता पर भी हमला जारी रहा. कोण्डागांव, कोइलीबेड़ा और केसकाल इलाकों में दस्तों पर कई हमले हुए. मार्च 1995 में कोंडागांव इलाके में हुई एक मुठभेड़ में कॉमरेड फूलवती शहीद हो गई. फिर भी दस्तों ने दुश्मन का प्रतिरोध करते हुए जनाधार बढ़ा लिया.

1994 में मद्देड इलाके के बंडारुपल्ली गांव में डीएकेएमएस नेता कॉमरेड चापा लक्ष्मैया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लापता कर दिया. अभी तक उसका कोई अता-पता नहीं है.

दुश्मन के हमलों का डटकर मुकाबला किए बिना आन्दोलन का आगे बढ़ना सम्भव नहीं था. इसे समझते हुए पार्टी ने 1990 से दुश्मन के खिलाफ सुनियोजित व संगठित तरीके से जवाबी हमले करने का फैसला लिया. इस फैसले के मुताबिक बस्तर, गड़चिरोली और बालाघाट में कई एम्बुश और रेड किए गए. बस्तर में गोल्लापल्ली, एटागट्टा, धनोरा; गड़चिरोली में कोसपूंड्री, भीमनकोज्री, किष्टापुरम, मंगेझरी; बालाघाट में सीतेफला में दुश्मन पर महत्वपूर्ण हमले किए गए. दुश्मन से दर्जनों हथियार छीनकर गुरिल्ला दस्तों को मजबूत किया गया. इन हमलों से दुश्मन की आक्रामकता पर अंकुश लगाने में कामयाबी मिली. जनता फिर एक बार बड़े पैमाने पर जन संघर्षों में कूद पड़ी. जनता का आत्मविश्वास बढ़ गया.

ऐसी स्थिति में फौजी कार्रवाइयों की तीव्रता बढ़ती जा रही थी. जनता को संगठित करना और दुश्मन का मुकाबला करना – इन दोनों कार्यभारों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विशेष रूप से दस्तों के निर्माण की जरूरत सामने आई. 1993 में बस्तर और गड़चिरोली डिवीजनों में विशेष गुरिल्ला दस्तों का निर्माण किया गया. 1995 तक इन दस्तों का विकास पलटनों के रूप में हुआ और यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही गया. 28 जुलाई 2004 में दण्डकारण्य में पहली कम्पनी का निर्माण

किया गया. अब एरिया स्तर से राज्य स्तर तक फौजी व सांगठनिक काम के लिए अलग-अलग ढांचे विकसित हो गए हैं.

इसके बाद से गांवों के नौजवान बड़ी संख्या में गुरिल्ला दस्तों के साथ मिलकर दुश्मन के खिलाफ हमलों में भाग लेना शुरू किया. एकल कार्रवाइयों में भी कई युवती-युवकों ने भाग लेकर दुश्मन के दलालों का सफाया किया तथा पुलिस बलों को हैरान-परेशान किया. इस प्रकार ग्रामीण युवाओं ने अपने जन संगठनों तथा जनता की हिफाजत करना शुरू किया. समूची जनता के हथियारबन्द होकर दुश्मन के खिलाफ लड़ने की जरूरत ज्यादा महसूस की जाने लगी. जनता बड़ी संख्या में हथियारबन्द कार्रवाइयों में भाग लेना शुरू किया.

बस्तर में 1997 में दूसरा 'जन जागरण' अभियान चलाया गया जिसमें भैरमगढ़ इलाके के कुछ गांवों पर पाशविक हमले किए गए थे. लेकिन पहले अभियान से ली गई सीख के आधार पर पार्टी एवं जन संगठनों ने बहुत जल्द ही इसका मुकाबला कर अभियान को विफल कर दिया.

2 दिसम्बर 2000 को, हमारे प्यारे शहीद कॉमरेड श्याम, महेश और मुरली की पहली बरसी के दिन, तत्कालीन पीपुल्सवार पार्टी ने पीजीए का गठन किया. (अब यह सेना पीएलजीए कहलाती है). बाद में पार्टी की 9वीं कांग्रेस सम्पन्न हुई जिसमें दण्डकारण्य को आधार इलाके में तब्दील करने के लक्ष्य को फौरी कार्यभार के तौर पर लिया गया. गांव-गांव में जन मिलिशिया को मजबूत करने की प्रक्रिया तेज हुई. दुश्मन ने भी इस विशाल रणनीतिक इलाके में तेजी से विकसित हो रहे क्रान्तिकारी आन्दोलन का सफाया करने के लिए दीर्घकालिक और फौरी योजनाएं तैयार कर अमल शुरू किया. इसके तहत बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, थानों की मजबूत किलेबन्दी, नए बटालियनों का गठन, नए थानों की स्थापना, खुफिया विभाग का गठन, सूचना-तंत्र का फैलाव, अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती, पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त टास्कफोर्स का गठन आदि कदम उठाते हुए आन्दोलन के खिलाफ चौतरफा हमला तेज किया.

21 सितम्बर 2004 भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन था. उस दिन भारत की दो बड़ी माओवादी पार्टियों - एमसीसीआइ और भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] का विलय सम्पन्न हो गया और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन किया गया. इससे आन्दोलन को देशव्यापी स्वरूप मिल गया तथा देश के कई इलाके माओवादी आन्दोलन के प्रभाव में आ गए. दुश्मन अब 'वामपंथी उग्रवाद' को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए भाकपा (माओवादी) के खिलाफ देशव्यापी हमला छेड़ दिया. इसके तहत दण्डकारण्य में शत्रु दमन तेज हो गया. बस्तर में अभी-अभी शुरू हुआ तीसरा 'जन जागरण' अभियान भी इसी देशव्यापी हमले का हिस्सा है. दूसरी तरफ गड़चिरोली डिवीजन में दमन लगातार बढ़ता ही जा रहा है. अब समूचा दण्डकारण्य एक युद्ध क्षेत्र सा बन गया है. एक तरफ प्रतिक्रियावादी शसन-प्रशासन व उनके पुलिस बल खड़े हैं तो दूसरी तरफ भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में संगठित जनता और उसकी अपनी सेना पीएलजीए खड़ी हुई हैं. एक तरफ गांवों में उभरती हुई जनता की नई राजसत्ता खड़ी है तो दूसरी तरफ सड़ी-गली लुटेरी राजसत्ता उस पर हमला कर उसका सफाया करने की कोशिश कर रही है. यही वर्तमान परिस्थिति है यहां.

'प्रभात' : दण्डकारण्य एक विशाल आदिवासी बहुल इलाका है. आदिवासियों के विशेष मुद्दों को उठाने तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आपने क्या-क्या किया?

कॉमरेड कोसा : यहां के आन्दोलन की शुरूआत ही 'जंगल पर सभी अधिकार आदिवासियों को' के नारे से हुई. जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का अधिकार कायम करने का लक्ष्य हमारे संघर्ष की शुरूआत से ही रहा. आज भी सरकार के खिलाफ जनता के संघर्ष में मुख्य मुद्दा यही है. दरअसल आदिवासियों के सहज विकासक्रम में यह लुटेरी सरकार ही बहुत बड़ी रुकावट थी. सरकार ने जंगल पर आदिवासियों के सभी अधिकार छीनकर उन्हें उनके ही जंगल में चोर करार दिया. आदिवासी किसानों को दिहाड़ी मजदूरों में तब्दील कर उनकी श्रमशक्ति को सस्ते में लूट रही थी. हमने जहां तक सम्भव हो इसे रोकने की कोशिश की. हमारे संघर्ष इलाकों में आज आदिवासी अपने जंगल के मालिक बन गए हैं. सरकारी वन विभाग के न केवल जुल्मों व अत्याचारों को रोका गया, बल्कि आज संघर्ष इलाकों में उसका अस्तित्व ही लगभग समाप्त हो गया. आज जनता अपनी सत्ता के अंग - जनताना सरकार के जरिए जंगल की रखवाली खुद कर रही है. हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे संघर्ष के इलाकों में ऐसा एक भी किसान नहीं बचा है जिसके पास जमीन नहीं है. सभी को जमीन मिल गई.

यहां हमारी पार्टी के प्रवेश के पहले भोली-भाली आदिवासी महिलाओं का यौन शोषण जोरों पर चलता था. वन विभाग व पेपरमिल के बाबूगण, पटवारी, व्यापारी, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस वाले आदिवासी युवतियों के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर या डरा-धमकाकर उनका दैहिक शोषण करते थे. कइयों ने तो उन्हें गर्भवती बनाकर छोड़ दिया तो कइयों ने रखैल बनाकर रख लिया. इस स्थिति से महिलाओं को बाहर निकालने का श्रेय निश्चित रूप से क्रान्तिकारी आन्दोलन को ही जाता है.

आदिवासियों पर हिन्दू व ईसाई धर्म के हमलों को रोकने और आदिवासी संस्कृति को बचाने में हमारी पार्टी और जन संगठनों की कोशिशें लगातार जारी हैं. जब बस्तर में छठवीं अनुसूची लागू करने की मांग से जनता आन्दोलित हुई थी तो हमारी पार्टी ने न सिर्फ उसका समर्थन किया, बल्कि उस आन्दोलन को मजबूती प्रदान की. 'पृथक विदर्भ' राज्य और 'पृथक छत्तीसगढ़' की मांगें काफी पुरानी थी. इन मांगों का हमने शुरू से ही समर्थन किया. वर्ष 2000 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय जब बस्तर को छत्तीसगढ़ में मिलाने की बात चल रही थी, तब हमने बस्तर की आदिवासी जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप 'पृथक बस्तर' राज्य की मांग उठाई. इसके तहत हमने हजारों जनता को संघर्ष में उतारा - जन आन्दोलन का सक्रिय समर्थन किया.

गड़चिरोली में गोवारी समुदाय के लोगों तथा बस्तर में नायक गोण्ड समुदाय के लोगों ने उन्हें आदिवासियों में शामिल करने की मांग उठाई थी तो हमारी पार्टी ने इस मांग का भरपूर समर्थन किया. नागपुर में इस मांग से आन्दोलन कर रहे गोवारी लोगों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर कई लोगों की हत्या की थी. इसकी हमारी पार्टी ने कड़ी निंदा की. गोवारी आदिवासियों के प्रति यहां के सभी जन संगठनों ने भाईचारा प्रकट किया.

हीरानार, कुव्वेमारी, नगरनार, रावघाट, बोधघाट आदि परियोजनाओं के नाम से आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित करने की सरकारी कोशिशों के खिलाफ हमारी पार्टी ने संघर्ष किया. जनता के न्यायपूर्ण आन्दोलन का समर्थन किया. इस आदिवासी अंचल

की प्राकृतिक संपदाओं को साम्राज्यवादी कम्पनियों को लुटाने वाली सरकारों की सभी कोशिशों का हमने विरोध किया. आदिवासियों के अस्तित्व को खतरे में डालने वाली हरेक कोशिश का हमने विरोध किया. बस्तर की जल सम्पदाओं का दोहन करने वाली एस्सार परियोजना का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं. अब संघर्ष इलाकों में भ्रूण रूप में आकार ले रही जनता की नई राजसत्ता – जनताना सरकार आदिवासियों की स्वायत्तता के प्रति प्रतिबद्ध है. दण्डकारण्य के आदिवासियों का समग्र विकास की गारन्टी सिर्फ जनताना सरकार ही दे सकती है. इसकी वृद्धि पर ही आदिवासियों की भलाई टिकी हुई है.

'प्रभात' : आपने राजनीतिक तौर पर क्या-क्या मुद्दे उठाए? उनको लेकर किए गए संघर्षों के बारे में जरा बताइए.

कॉमरेड कोसा : सबसे पहले आपको बता दूं कि राजनीतिक तौर पर हमने शुरू से ही यह प्रचार किया है कि राजसत्ता को छीनना ही हमारा असली मकसद है. जनता के हाथ में राजनीतिक हुकूमत मिले बिना किसी भी समस्या का स्थाई समाधान नहीं हो सकता. इसके अलावा हमने समय-समय पर कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर जनता को गोलबन्द किया जिससे उनकी राजनीतिक चेतना में काफी विकास हुआ है. जब भी चुनावों का आयोजन होता है, तो हमारे तमाम संगठन बहिष्कार का आह्वान करते हुए बड़े पैमाने पर प्रचार करते हैं. इससे हजारों लोगों तक हमारा राजनीतिक संदेश पहुंच जाता है. संसदीय व्यवस्था क्या है और जनता का लोकतंत्र क्या है, इसे लोग अब बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं. साम्राज्यवाद के खिलाफ भी जनता को कई बार गोलबन्द किया गया. 1990 में बुश (सीनियर) ने जब इराक पर हमला किया था, तब हमारे जन संगठनों ने कई जगहों पर रैलियां निकालीं. 'अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद' का नारा हर तरफ सुनाई दिया. अभी 2003 में जब जूनियर बुश ने इराक पर दोबारा हमला किया, तब भी दण्डकारण्य में हजारों लोगों ने बड़ी-बड़ी रैलियां निकालीं. मैं यह गर्व के साथ बता सकता हूं कि 2001 और 2003 में क्रमशः अफगानिस्तान और इराक पर किए गए अमेरिकी हमले के खिलाफ रायपुर जैसे शहर में भी एकाध रैली शायद ही आयोजित की गई हो पर बाहरी दुनिया के द्वारा 'अबूझमाड़' के नाम से पुकारे जाने वाले माड़ क्षेत्र की हजारों जनता ने कई रैलियां निकालीं. 1996 में बंगलूर में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता के खिलाफ केएएमएस ने बड़ा आन्दोलन छेड़ा था. नारायणपुर में एक बड़ी रैली निकाली गई जिसमें 10 हजार महिलाओं ने भाग लिया. 1910 का 'महान भूमकाल' संघर्ष की यादगार में उसे 'जनता की राज्य-स्थापना दिवस' के रूप में अब हर साल 10 फरवरी को मनाया जा रहा है जिसमें हजारों लोग भाग लेकर 'भूमकाल' की विरासत को जारी रखने की कसमें खा रहे हैं. 15 अगस्त और 26 जनवरी को 'काला दिवस' तथा 23 मार्च को भगतसिंह की बरसी, 8 मार्च आदि आयोजनों से जनता की राजनीतिक चेतना बढ़ रही है. अपने संसाधनों को बचाने के लिए भी जनता ने कई संघर्ष किए हैं. जनता को बड़े पैमाने पर विस्थापित कर, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली तथा बड़े व विदेशी पूंजीपतियों की झोली भरने वाली बड़ी परियोजनाओं का विरोध कर रही है. इस तरह के कई संघर्ष किए गए हैं.

वर्तमान में एस्सार पाइप लाइन योजना, सूर्जागढ़ में लोहा खनिज का दोहन, रावघाट-चारगांव में लोहे का दोहन, आदि शोषणकारी परियोजनाओं का जनता विरोध कर रही है. इन सारे संघर्षों से हमारे संघर्ष इलाकों के बाहर की जनता भी अब स्पष्ट रूप से समझ चुकी है कि नक्सलवादी या माओवादी आन्दोलन एक राजनीतिक आन्दोलन है. हमारी पार्टी के नेतृत्व में पिछले 25 बरसों से जारी संघर्ष के प्रभाव से ऐसे इलाकों में भी जहां हमारे संगठन नहीं हैं, जनता कई मुद्दों को लेकर आन्दोलित हो रही है. हमसे समर्थन करने की मांग कर रही है. यह भी बहुत बड़ी उपलब्धी है.

'प्रभात' : इन 25 सालों में आपके संघर्ष से जनता के जीवन में क्या-क्या बदलाव आए हैं?

कॉमरेड कोसा : सबसे पहले आदिवासियों में हीनभावना की जगह आत्मविश्वास ने ली. वे अब सिर उठाके जी रहे हैं. यह सबसे बड़ा बदलाव है. और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सभी को जमीन मिली है. वे आज जंगल में स्वेच्छा से जाते हैं और जरूरती चीजें लाते हैं, उन पर कोई जुल्म नहीं करता. ठेकेदारों, साहुकारों, पूंजीपतियों व सरकारी अधिकारियों की मनमानी लूट को रोकने में हम काफी हद तक सफल हुए हैं. अपने श्रम के वाजिब दाम की मांग से लड़कर जनता ने कई उपलब्धियां हासिल कीं. आज हमारे संघर्ष क्षेत्र में तेन्दुपत्ता मजदूरी और पेपरमिल मजदूरी की जो दर दी जाती है वह देश में कहीं भी नहीं है.

यहां अब भूख से कोई नहीं मरता. हम आए दिन देश के कई हिस्सों से भुखमरी की खबरें सुनते हैं लेकिन दण्डकारण्य में नहीं. जनता का जीवन स्तर काफी बढ़ गया. यहां सरकारों ने शिक्षा और चिकित्सा के मामले में जो कुछ भी काम किया है, वह यहां के जन संघर्षों का ही नतीजा है. हालांकि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में स्थिति अभी भी बेहद खराब है. लेकिन जिन इलाकों में जन संघर्ष नहीं है वहां तो सरकारें आज कुंभकर्ण की नींद सो रही हैं, जोकि जगजाहिर है.

आज यहां के लोग अपने आपसी विवादों को लेकर कोर्ट-कचहरी का चक्कर नहीं काटते. वे अपने आप उन्हें सुलझा लेते हैं. अब तो गांव-गांव में जनता की अपनी सरकार – जनताना सरकार का गठन हो रहा है, जोकि सबसे बड़ा बदलाव है. अब इसे बचाने व फैलाने के लिए जनता कदम बढ़ा रही है.

'प्रभात' : आपका काम मुख्य रूप से जंगली इलाकों तक ही सीमित है, ऐसा माना जाता है. दण्डकारण्य के मैदानी व शहरी इलाकों में आप कमजोर क्यों हैं?

कॉमरेड कोसा : शुरू में हमारे कार्यकर्ताओं ने दण्डकारण्य के मैदानी व शहरी इलाकों में भी काम किया था. आप तो जानते ही हैं कि शहरी इलाके दुश्मन के मजबूत गढ़ होते हैं. खासतौर पर संघर्ष इलाकों से सटे शहरों में दुश्मन का जमाव बहुत अधिक होता है. वहीं से वह हम पर हमला करता है. इसके बावजूद भी हमने 1989-90 तक शहरी इलाकों में काम किया था. लेकिन दुश्मन के तीखे दमन में हमें नुकसान उठाने पड़े. हमारे कुछ कार्यकर्ता शहीद हो गए. दुश्मन के दावपेंच को सही तरीके से समझकर जवाबी दावपेंच अपनाकर काम करने में हमारी कमजोरी रही. बाद में उन इलाकों में मौजूद दमन की स्थिति और कार्यकर्ताओं की कमी के चलते वहां हमारा काम अवरुद्ध हो गया. वर्ष 2000 से इस काम में हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. आशा है कि निकट भविष्य में इस कमी को हम दूर कर सकेंगे.

'प्रभात' : फौजी क्षेत्र में पिछले 25 बरसों में आपने कितनी प्रगति हासिल की?

कॉमरेड कोसा : जैसे कि माओ ने बताया किसी भी क्रान्ति की मुख्य समस्या राजसत्ता छीनने की ही समस्या है. और राजसत्ता को सिर्फ सशस्त्र संघर्ष के जरिए ही हासिल किया जा सकता है. इस तरह आज की स्थिति में सशस्त्र संघर्ष ही संघर्ष का मुख्य स्वरूप और सेना ही संगठन का मुख्य स्वरूप है. 25 साल पहले हमने जब यहां कदम रखा था, तब हम 12 बोर की कुछ देशी बन्दूकें और देशी बमों से लैस थे. 1984 तक हमारे पास एक भी रायफल नहीं थी. उस समय हम दुश्मन पर हमले भी नहीं करते थे. फौजी प्रशिक्षण भी हमें कोई खास नहीं था. मुख्य रूप से आत्मरक्षा में रहकर जनता को जागृत व संगठित किया करते थे. लेकिन ज्यों-ज्यों शत्रु दमन बढ़ता गया, हम अपने आन्दोलन को फौजी तौर पर ज्यादा विकसित करते गए. शुरू में जन विरोधियों व जमींदारों की बन्दूकें छीनकर हमने खुद को बेहतर हथियारों से लैस किया. आज हमारे पास जितनी रायफलें मौजूद हैं उनमें से 90 प्रतिशत दुश्मन के पुलिस बलों के हाथों से छीनी हुई हैं. यानी हमारा हथियारों का मुख्य स्रोत खुद दुश्मन ही है. दुश्मन के हाथ में जो भी नया हथियार आता है वह हमारे पास भी आ रहा है. उदाहरण के लिए अब अर्ध सैनिक बलों का मुख्य हथियार इंसास रायफल है, तो हमारे पास भी अब इंसास रायफलें आने लगी हैं.

जहां तक प्रशिक्षण का सवाल है, हम पहले मुख्य रूप से छापामार दस्तों को ही प्रशिक्षण दिया करते थे. आज हमारे संघर्ष इलाके के लगभग सभी गांवों के जन मिलिशिया सदस्य और संगठन कार्यकर्ता तक फौजी प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं. जहां भी दुश्मन गश्त पर गांवों में आता है तो जनता और मिलिशिया जरूर उसका प्रतिरोध कर रहे हैं. इस जनयुद्ध में जनता की भागीदारी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कई जगहों में खुद मिलिशिया सदस्यों ने पुलिस पर आश्चर्यजनक हमले करके हथियार छीन लाए हैं. ग्रामीण महिलाएं भी बड़ी संख्या में फौजी प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं.

शुरू में छापामार दस्ता ही हमारा एक मात्र फौजी संगठन हुआ करता था. यही फौजी व सांगठनिक दोनों कर्तव्य संभालता था. लेकिन 1993 से इसमें विभाजन व विकास की प्रक्रिया शुरू हुई. विशेष रूप से फौजी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए विशेष दस्तों का गठन से शुरू कर आज हम कम्पनी के निर्माण तक पहुंच चुके हैं. खासकर 2000 में पीएलजीए के गठन के बाद फौजी क्षेत्र में ज्यादा विकास सम्भव हुआ है. एक समय हम मुट्ठी भर लोग यहां आए थे, लेकिन आज हजारों लोग इस आन्दोलन में शामिल हो गए. इसे मैं एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानता हूं.

जहां तक हमलों का सवाल है, पहले पहल छोटे-छोटे लक्ष्यों को चुनकर हमले करते थे. लेकिन आज हम सैकड़ों की संख्या में जाकर दुश्मन पर हमले कर पा रहे हैं. दुश्मन के बड़े फॉर्मेशनों पर भी हमले कर रहे हैं. इतना ही नहीं, दुश्मन के अभेद्य समझे जाने वाले अड्डों पर भी हम सफलतापूर्वक हमले कर पा रहे हैं. आज दुश्मन कम संख्या में हमारे इलाकों में कदम रखने से कतरा रहा है, यह भी हमारे जनयुद्ध की एक उपलब्धि है.

'प्रभात' : महिला मोर्चे के विकास के बारे में बताइए.

कॉमरेड कोसा : एक समय था जब यहां की आदिवासी महिला सरकारी अधिकारी को या सेठ-साहुकार को देखते ही डर जाती थी. गांव में कोई अजनबी आने से घर के भीतर दुबककर रह जाती थी. मजदूरी काम पर जाने से बाबू लोगों के गाली-गलौज और अत्याचारों को चुपचाप सह लेती थी. आज उसी 'महिला' को देखकर वो लोग डर से कांप रहे हैं. यहां की महिला अब सिर उठाकर जी रही है. सभी संघर्षों में वह पुरुष के बराबर भाग ले रही है.

इतना ही नहीं, आदिवासी रीति-रिवाजों के नाम पर चलती रही जबरिया विवाह की प्रथा को तोड़कर अब महिलाएं अब अपनी पसन्द की शादियां कर रही हैं. यहां पहले महिलाएं डीएकेएमएस में ही शामिल हुआ करती थीं. तत्कालीन पीपुल्सवार पार्टी के इतिहास में पहली बार दण्डकारण्य में ही महिला संगठन - क्रान्तिकारी आदिवासी महिला संगठन (केएएमएस) का निर्माण किया गया णल जिसमें हजारों महिलाओं को गोलबन्द किया गया. आज केएएमएस देश के सबसे बड़े महिला संगठनों में एक बन गया. रीति-रिवाजों की आड़ में जारी कुप्रथाओं तथा सरकारी शोषण-उत्पीड़न के खिलाफ आज दण्डकारण्य की महिला देश की अन्य शोषित-पीड़ित महिलाओं के साथ अपनी आवाज बुलन्द कर रही है. दण्डकारण्य के गांव-गांव में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जोर शोर से मनाया जाता है जिसमें हजारों महिलाएं भाग लेती हैं. अब दण्डकारण्य में पीएलजीए में महिलाओं की संख्या 40 प्रतिशत तक बढ़ी है. गांव-गांव में गठित हो रही जनताना सरकारों में भी वे मुख्य भूमिका निभा रही हैं. आज विशेष महिला संगठनकर्ता, महिला एलजीएस और पलटनों -कम्पनियों में महिलाओं के विशेष सेक्षन आदि विशेष संगठनों का निर्माण हुआ है जिससे महिलाओं के विकास में काफी मदद मिल रही है. यहां की महिलाएं अब दस्तों, पलटनों व अनेक स्तरों की पार्टी कमेटियों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं. परन्तु आन्दोलन की जरूरत के मद्देनजर यह प्रगति काफी कम है. स्थानीय महिलाओं को राजनीतिक व विचारधारात्मक मोर्चों में ऊपर लाने के लिए और ज्यादा जोर देने की जरूरत है.

'प्रभात' : सांस्कृतिक मोर्चे में पिछले 25 बरसों से हासिल प्रगति पर रोशनी डालिए.

कॉमरेड कोसा : संस्कृति का क्षेत्र एक बेहद व्यापक क्षेत्र है. यह समाज को हर तरह से प्रभावित करता है. लेकिन जनयुद्ध में व्यस्तता के कारण हम इस क्षेत्र में ज्यादा काम नहीं कर पाए हैं. जनता के चौमुखी विकास के रास्ते में बाधा बने हुए अंधविश्वास, महिलाओं पर परम्परागत दबाव, गलत रीति-रिवाज, आदि में जितना परिवर्तन लाना चाहिए था उतना हम नहीं ला पाए हैं. हालांकि पिछले 25 बरसों में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की गई हैं. मसलन गड़चिरोली डिवीजन के कुछ इलाकों में शादी के बाद जबरन महिलाओं के ब्लऊज हटाने की कुप्रथा थी. इसके खिलाफ जनता में जागृति लाकर संघर्ष छेड़ दिया तो धीरे-धीरे वह प्रथा खत्म हो गई. महिलाओं को जबरन उठा ले जाकर शादी करने की कुप्रथा भी संघर्ष के जरिए लगभग खत्म हो गई. उत्तर बस्तर में गोटुल में युवक-युवतियों के बीच यौन सम्बन्धों की प्रथा चलती आ रही थी. इसमें युवतियों पर दबाव डालकर उनकी मर्जी के खिलाफ युवकों के साथ सम्बन्ध रखने पर मजबूर किया जाता था. इस रूढ़िगत रिवाज को बदलने की जरूरत पर जनता को गोलबन्द किया गया जिससे यह प्रथा खत्म हो गई. उत्पादन की प्रक्रिया को बाधित

करने वाले तीज–त्यौहारों को सुव्यवस्थित कर दिया गया जिससे खेती के कामों में जनता अब ज्यादा समय दे पा रही है. खासकर माड़ इलाके में 10 साल पहले तक पुरुष लम्बे बाल रखते थे, लेकिन हमारे प्रचार व प्रयास से अब यह प्रथा लगभग खत्म हो गई. सभी पुरुष बाल कटवा रहे हैं. लेकिन खासकर महिलाओं में शृंगार के साधनों के प्रति बढ़ रहे मोह को कम करने में हम विफल हो रहे हैं. बाजारू संस्कृति इतनी हावी हो रही है कि क्रान्तिकारी संगठनों में मौजूद स्त्री–पुरुष भी किसी न किसी हद तक शृंगार के साधनों व नकली गहनों को खरीद रहे हैं, जोकि बिलकुल अनावश्यक है. इसे हतोत्साहित करने की जरूरत है.

कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है. आज हर गांव में छोटे–छोटे बच्चे भी क्रान्तिकारी गीत गुनगुनाते हैं, ऐम्बुश का खेल खेलते हैं. क्रान्तिकारी गीत संघर्ष के प्रचार–प्रसार का एक सशक्त माध्यम बनकर जनता के दिल में रच–बस गया है. जन गीतों को क्रान्तिकारी गीतों में ढालने की प्रक्रिया चल रही है. लेकिन इस क्षेत्र में चुनौतियां भी कम नहीं हैं. एक तरफ साम्राज्यवादी संस्कृति और दूसरी तरफ हिन्दू मनुवादी संस्कृति की घुसपैठ तेजी से हो रही है. इसका मुकाबला करना और जनवादी संस्कृति को विकसित करना इस क्षेत्र में मुख्य चुनौती है. इस क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करने के लिए अब 'चेतना नाट्य मंच' एक विशाल जन संगठन बनकर उभर रहा है.

साहित्य के क्षेत्र में भी क्रान्तिकारी आन्दोलन ने बड़ा बदलाव लाया है. अब पार्टी, पीएलजीए व जन संगठनों के कार्यकर्ता एक हाथ में बन्दूक लेकर लड़ते हुए ही दूसरे हाथ में कलम लेकर क्रान्तिकारी साहित्य का सृजन कर रहे हैं. अनपढ़ आदिवासी युवक–युवतियां अब पढ़–लिखकर कविता–कहानी लिख रहे हैं. अब गोंडी भाषा में साहित्य का सृजन हो रहा है. हम कई पत्र–पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे हैं. लेकिन यह काम आज की जरूरत की तुलना में बहुत कम है. पूरे समाज को प्रभावित करने लायक इस क्षेत्र में विकास होना बाकी है.

'प्रभात' : 25 साल का समय काफी लम्बा है न! आज की इस स्थिति में पहुचने के लिए आपको इतने साल क्यों लग गए?

कॉमरेड कोसा : हां, यह बात सही है कि 25 साल का समय काफी ज्यादा ही है. लेकिन इन 25 सालों तक पार्टी का टिके रहना, लगातार संघर्ष जारी रखना भी अपने आपमें एक महत्वपूर्ण बात है. जैसे कि हमारी पार्टी द्वारा तैयार की गई 'भारत की क्रान्ति की रणनीति और कार्यनीति' में स्पष्ट रूप से कहा गया है, भारत सरकार एक शक्तिशाली सेना से लैस मजबूत दुश्मन है. लाखों की संख्या में सेना, पुलिस बल और अर्ध–सैनिक बल मौजूद हैं जिनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं. यहां की राज्यव्यवस्था ज्यादा केन्द्रीकृत है. संचार सुविधाओं का नेटवर्क भी मजबूत है. इसके बावजूद भी हमने दीर्घकालीन जनयुद्ध की कार्यदिशा पर ठोस रूप से व दृढ़ता से अमल करते हुए संघर्ष जारी रखा और खुद को एक बड़ी ताकत के रूप में उभारा. कई नुकसानों को झेलकर इस मुकाम पर पहुंचना भी बड़ी बात है. आज दण्डकारण्य के आन्दोलन को देखखर दुश्मन जिस तरह डर से कांप रहा है और हताश होकर इसका सफाया करने की जी–तोड़ कोशिश कर रहा है, इससे भी हमारे इस आन्दोलन की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है.

जहां तक पार्टी का सवाल है, महान नक्सलबाड़ी संघर्ष की अस्थाई पराजय के बाद, अवसरवादियों की गद्दारी से पार्टी बिखर गई थी. कॉमरेड चारु मजुमदार के समय की केन्द्रीय कमेटी लगभग खत्म हो गई थी. दोबारा पार्टी को संगठित करना, उसे सही कार्यनीति में दक्ष बनाना और नए सिरे संघर्ष को खड़ा करना – ये सब बड़ी चुनौतियां थीं. दुश्मन के हमले बढ़ने के बाद जबकि तीखे दमन का मुकाबला करते हुए आन्दोलन आगे बढ़ रहा था, पार्टी में दो–दो बार – 1985 और 1990 में सर्वोच्च नेतृत्व के स्तर पर उत्पन्न हुए संकटों के चलते भी पार्टी का काम प्रभावित हुआ था. सही वक्त पर सही फैसले लेकर सही कार्यनीति अपनाने में, जैसे कि फौजी संगठन को विशेष रूप से विकसित करने में कुछ कमजोरियां रही थीं. हालांकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया पिछले 25 बरसों में दण्डकारण्य में हमने जो प्रगति हासिल की वही मुख्य पहलू है.

'प्रभात' : भारत के शासक वर्ग दण्डकारण्य के आन्दोलन को भारतीय क्रान्ति का एक मजबूत गढ़ मानते हुए व्यापक दमन अभियान चला रहे हैं. सेना को भी तैनात करने की सम्भावना नजर आने लगी है. ऐसे में क्या आपको विश्वास है कि आप यहां टिक पाएंगे और इसका मुकाबला कर पाएंगे?

कॉमरेड कोसा : हमारा युद्ध जनयुद्ध है. जनयुद्ध का मतलब तमाम शोषित जनता का सम्पूर्ण युद्ध है. हमें यहां पर मजबूत जनाधार हासिल है. हमारा विश्वास है और सच्चाई भी है कि किसी भी युद्ध में हार–जीत का फैसला इसी बात से होता है कि जनता किसके पक्ष में है. आधुनिक हथियार, भारी–भरकम सेना युद्ध जीतने के लिए काफी नहीं है. जनता का समर्थन और सक्रिय भागीदारी ही मुख्य बिन्दु हैं. इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि हम भीषण हमले के बावजूद भी जनता पर निर्भर करते हुए टिक पाएंगे. दुश्मन भले ही मजबूत हो, पर उसे जनता का समर्थन बिलकुल नहीं है. पिछले 58 सालों के 'आजाद' भारत के इतिहास में जनता को यह स्पष्ट हो गया कि ये सरकारें उनके लिए कुछ नहीं करने वाली हैं. इसीलिए लोग अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं. इसके अलावा यहां की भौगोलिक स्थिति भी गुरिल्ला युद्ध के लिए अनुकूल है. इसका भी हम फायदा उठाएंगे. फिर भी चूंकि फिलहाल यह गुरिल्ला युद्ध है, इसलिए अगर दुश्मन ने हमें मजबूर किया तो हम इस इलाके को खाली कर नए इलाकों की ओर भी कूच कर सकते हैं. फिर जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो तब हम फिर आ सकते हैं.

'प्रभात' : फिलहाल बस्तर में 'जन जागरण' के नाम से एक दमन अभियान चल रहा है. इसको लेकर मीडिया में तरह–तरह की खबरें आ रही हैं कि जो आदिवासी अब तक नक्सलियों को शरण देते रहे वही आज नक्सलियों का विरोध कर रहे हैं. ऐसे अभियानों के समय–समय पर सिर उठाने के क्या कारण हैं?

कॉमरेड कोसा : इसे आदिवासियों के स्वस्फूर्त आन्दोलन कहना सचाई से कोसों दूर है. अगर आदिवासी ही हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं तो आदिवासियों की हत्याएं क्यों की जा रही हैं? 'सलवा जुडूम' के गुण्डे और पुलिस गांवों पर हमले करके घरों को क्यों जला रहे हैं? भोलीभाली महिलाओं के साथ दुष्कर्म क्यों कर रहे हैं? यह सब गोबेल्स प्रचार के अलावा कुछ नहीं है.

आपने पूछा कि ऐसे अभियान क्यों बार–बार सामने आ रहे हैं. सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि इन अभियानों के पीछे लुटेरे शासक वर्गों व साम्राज्यवादियों की सोची–समझी साजिश है. वे हमारे इस आन्दोलन का पूरी तरह सफाया करने के लिए महेन्द्र कर्मा जैसे

दलालों को चुनकर ला रहे हैं. क्योंकि वे समझते हैं कि ऐसे दमन अभियान की कमान किसी 'आदिवासी' नेता के हाथों में दे देने से इसे 'आदिवासी' रंग आएगा. वे हमारे आन्दोलन को कुचलने के लिए इसलिए उतावले हो रहे हैं कि यहां पर मौजूद अपार जल, वन व खनिज सम्पदाओं को लूटना उनका असली मकसद है. हमारी पार्टी के नेतृत्व में दण्डकारण्य की जनता ने पिछले 25 बरसों से जल, जंगल और जमीन पर अपने अधिकार के लिए लड़कर कई उपलब्धियां हासिल की हैं. सूर्जागढ़ (गड़चिरोली), रावघाट, हीरानार, बोधघाट, चारगांव (बस्तर) आदि जगहों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कदम रखने नहीं दिया. इससे साम्राज्यवादी बौखलाए हुए हैं. वे किसी भी तरह यहां के आन्दोलन का सफाया कर यहां की सम्पदाओं को लूटना चाहते हैं. रमन सिंह आजकल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का दुलारा बन गया है. इसके अलावा, यहां पर उदीयमान जनता की नई राजसत्ता से भी वे घबराए हुए हैं. यह सब एक षड़यंत्र के तहत ही चल रहा है.

हमारी जनता ने दो-दो बार 'जन जागरण' अभियान को मात दी है. अबकी बार यह हमला काफी पाशविक और फासीवादी तरीके से चल रहा है. जब तक क्रान्ति को पूर्ण विजय हासिल नहीं होगी तब तक ऐसे दमन अभियान अलग-अलग रूपों में सामने आते रहेंगे ही. इनका मुकाबला करते हुए ही क्रान्तिकारी आन्दोलन आगे बढ़ सकता है. मेरा विश्वास है कि जनता वर्तमान अभियान को भी निश्चित रूप से परास्त कर देगी क्योंकि इतिहास का निर्माता जनता ही है.

'प्रभात' : गड़चिरोली डिवीजन में आन्दोलन लगातार कई सालों से शत्रु दमन का शिकार होता रहा है. वहां आन्दोलन का विकासक्रम किस प्रकार है?

कॉमरेड कोसा : पिछले 13 सालों से गड़चिरोली की जनता भीषण दमन झेलती आ रही है. हालांकि दमन पहले भी था पर तब उसकी तीव्रता कम थी. चूंकि महाराष्ट्र में सशस्त्र संघर्ष सिर्फ गड़चिरोली और गोंदिया दोनों ही जिलों तक सीमित है. इससे आन्दोलन पर दमनचक्र चलाने में दुश्मन को सुविधा हो रही है. वह अपनी पूरी ताकत को यहां लगाकर दमन कर रहा है. पर यहां की जनता भी इस दमन की आदी हो चुकी है और दमन के बीचोबीच ही वे अपनी समस्याओं को लेकर आन्दोलन में उतर रहे हैं. एक तरफ लोग सालों से अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ गिरफ्तारियां, मारपीट, यातनाएं, जेल की सजाएं, हत्याएं लगातार जारी हैं. पर सरकार जनता की समस्याओं को तो दूर नहीं कर रही है. इसलिए जनता ने इन सभी दिक्कतों के बावजूद भी संघर्ष का परचम ऊंचा किया हुआ है. हाल ही में उस डिवीजन में सम्पन्न तेन्दुपत्ता मजदूरी संघर्ष, बांस कटाई संघर्ष, अकाल की समस्या को लेकर आयोजित रैलियां, आदि में जनता ने बड़ी तादाद में भाग लिया. इससे यह स्पष्ट होता है कि दमन से जनता की संघर्ष की चेतना कुंद नहीं होती, बल्कि और ज्यादा धारदार हो सकती है. इस वर्ष पीएलजीए में बड़ी संख्या में हुई भर्तीयों से भी यही साबित हो रहा है.

वहां पर दुश्मन कई प्रकार के छापामारी दावपेंच अपनाते हुए घूमने के बावजूद इस साल पीएलजीए ने जनता की सक्रिय मदद से कई हमले किए. दुश्मन को जोरदार झटके लगाए. हथियारबन्द कार्रवाइयों में जनता और जन मिलिशिया की भूमिका भी बढ़ रही है. इस तरह जनयुद्ध में और तेजी लाकर ही दुश्मन के हमले को परास्त कर सकते हैं.

'प्रभात' : पिछले 25 बरसों में कई कॉमरेड शहीद हुए हैं. आप उन्हें किस तरह याद करते हैं?

कॉमरेड कोसा : मेरा मानना है कि पिछले 25 बरसों में हमने जो कुछ भी हासिल किया है वह हमारे प्यारे शहीदों की अनमोल कुरबानियों का ही नतीजा है. पेद्दि शंकर से लेकर भीमाल और रोशन तक दण्डकारण्य में अब तक 300 से ज्यादा पार्टी व जन संगठन सदस्यों, पीएलजीए के योद्धाओं व कमाण्डरों और अलग-अलग स्तर के नेताओं ने अपना खून बहाया है. कॉमरेड मड़ावी दादा, सुखदेव, मंगतू, आजाद, बाबन्ना, गणपति, संतोष, सोमजी, चन्द्रन्ना, अशोक, राजू, विक्रम, रणदेव, जोगन्ना, निर्मला, कमला, सन्नू, रामदास जैसे कॉमरेडों ने दण्डकारण्य आन्दोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. दण्डकारण्य की जनता इन्हें कभी नहीं भूलती. हर गांव में इनकी याद में स्मारक बनाए गए हैं. जनता के लिए काम करते हुए जान कुरबान करने वाले आम सदस्यों को भी याद करना, उनकी याद में स्मारक बनाना – जनता की उन्नत क्रान्तिकारी चेतना का परिचायक है. दुश्मन उन्हें गिरा भी रहा है, पर लोग उन्हें फिर से खड़ा कर रहे हैं. हर साल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक 'शहीद सप्ताह' का आयोजन दण्डकारण्य में बड़े पैमाने पर किया जाता है. मैं इस मौके पर हमारी पार्टी के संस्थापक नेता द्वय कॉमरेड चारु मजुमदार व कॉमरेड कन्नाई चटर्जी समेत भारतीय क्रान्ति के तमाम शहीदों को – हमदर्दों से लेकर कार्यकर्ता-नेता तक सभी को विनम्रता से याद करता हूं. दण्डकारण्य में संघर्ष और कुरबानी की परम्परा पहले से रही है. अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर शहीद हुए गेंदसिंह, गुण्डादुर, बाबूराव सेडिमेक, आदि लोक नायकों को तथा उन विद्रोहों में शहीद हुए आम जनता को भी मैं इस उपलक्ष्य में सम्मानपूर्वक याद करता हूं.

'प्रभात' : दण्डकारण्य में जनयुद्ध की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दण्डकारण्यवासियों और देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?

कॉमरेड कोसा : मैं दण्डकारण्य की संघर्षशील जनता का आह्वान करता हूं कि वे कई और कुरबानियां देने के लिए आगे आएं और इस जनयुद्ध को मजबूती से आगे बढ़ाएं. हर परिवार से युवक-युवतियों को पीएलजीए में शामिल होने का प्रोत्साहन दें. नौजवानों से मेरा आह्वान है कि वे पीएलजीए में बड़ी संख्या में शामिल होकर अनेक कुरबानियां देते हुए दुश्मन के खिलाफ दृढ़तापूर्वक संघर्ष करें. सामंतवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीवाद व साम्राज्यवाद का सफाया करके एक खुशहाल व जनवादी भारत के निर्माण के लिए कदम बढ़ाएं. दण्डकारण्य के तमाम छात्रों व बुद्धिजीवियों से मेरी अपील है कि वे सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभनों से दूर रहें और जनयुद्ध में शामिल होवें और उसका समर्थन करें.

देशवासियों को मेरा संदेश यही है कि वे केन्द्र-राज्य सरकारों द्वारा जारी साम्राज्यवाद-शासित भूमण्डलीकरण की नीतियों के खिलाफ तथा देश में बढ़ रहे हिन्दू फासीवाद के खिलाफ व्यापक संघर्ष करें. पूंजीवादी मीडिया द्वारा हमारे न्यायपूर्ण आन्दोलन के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार का विरोध करें. यहां पर जारी जनयुद्ध को आपकी हर तरीके की मदद की जरूरत है. यहां पर जारी सरकारी दमन के खिलाफ आवाज उठाकर जनता का समर्थन करें. आप देश के चारों तरफ शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष के नए-नए मोर्चे खोलकर हमारे इस संघर्ष का समर्थन कर सकते हैं. ✶

बस्तर को साम्राज्यवादी लूट का चरागाह बनाना ही फासीवादी 'जन जागरण' अभियान का असली उद्देश्य

पिछले जून महीने से दक्षिण बस्तर जिले के पश्चिमी हिस्से में चल रहा 'जन जागरण' अभियान या 'सलवा जुडूम' लगातार सुर्खियों में है. इसे ''जनता का स्वस्फूर्त आन्दोलन'' और ''शांतिपूर्ण अभियान'' कहकर बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जा रहा है. ''एक झूठ को सौ बार दोहराने से एक दिन वह सच होकर रहेगा'' – फासीवादी गोबेल्स के इस सिद्धान्त को आत्मसात करने वाले लुटेरे शासक वर्गों तथा उनके भाड़े के पुलिस–प्रशासन ने क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ जहरीली प्रचार मुहिम छेड़ रखी है. पिछले 25 बरसों से बस्तर समेत समूचे दण्डकारण्य में जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं. गांव–गांव में जनता की नई राजसत्ता का उदय हो रहा है. शोषकों–लुटेरों को काफी हद तक मार भगाया गया. खासकर 2001 में सम्पन्न तत्कालीन पीपुल्सवार पार्टी की 9वीं कांग्रेस में दण्डकारण्य को आधार इलाके में तब्दील करने का कार्यभार अपनाए जाने के बाद से आन्दोलन का रफ्तार और भी बढ़ गया. बस्तर में मौजूद अपार जल, वन और खनिज सम्पदाओं पर नजरें गड़ाए हुए लुटेरों – यानी बड़े पूंजीपतियों और साम्राज्यवादी कम्पनियों के लिए यह आन्दोलन गले की हड्डी साबित हो रहा है. दूसरी तरफ वे इस समूचे आदिवासी इलाके के लाल इलाके में तब्दील हो जाने की सम्भावना से भी भयभीत हैं. इसीलिए उन्होंने एक सोची–समझी साजिश के तहत ही इस तथाकथित 'जन जागरण' अभियान को आगे लाया.

बस्तर में क्रान्तिकारी आन्दोलन के विकास के परिणामस्वरूप गांवों में दुष्ट मुखियाओं, मांझियों, पंच–सरपंचों के भ्रष्टाचार, जुल्मों व अत्याचारों पर भी लगाम लग गई. शोषित–पीड़ित आदिवासी जनता ने कई भूस्वामियों से जमीनें छीन लीं. इससे शोषकों का यह वर्ग कुंठित है कि उन्हें पहले जैसे जनता को मनमाने लूटने का मौका नहीं मिल रहा है. सरकारी योजनाओं को, जिन्हें 'विकास कार्यों' के नाम से प्रचारित किया जाता है, लागू करके लाखों रुपए हड़पकर खाने का मौका भी उन्हें नहीं मिल रहा है. इसी मांझी–मुखियाओं के खेमे से हैं महेन्द्र कर्मा, केदार कश्यप, आदि–आदि. और तो और, बस्तर में मौजूद खनिज सम्पदाओं का दोहन करने की मंशा से यहां आ रही टाटा, एस्सार जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से इनको करोड़ों रुपए की दलाली जो मिलनी थी. यही वजह है कि ये लुटेरे प्रतिनिधि ''दलगत भावना से ऊपर उठकर'' इस दमनकारी मुहिम को अंजाम दे रहे हैं.

'जन जागरण' अभियान नया नहीं है!

1990–91 में तथा 1997 में इसी नाम से दो दमन अभियान चलाए गया थे. उनका भी नेतृत्व महेन्द्र कर्मा ने ही किया था. लेकिन क्रान्तिकारी जनता ने उन्हें विफल कर दिया था. तब भी इसी ढंग से प्रचारित किया गया था कि ''नक्सलियों के खिलाफ जनता का विद्रोह फूटा है'', ''नक्सलियों के पैर उखड़ने लगे हैं'', आदि–आदि. सच्चाई यह है कि लुटेरों के ऐसे अभियानों का मुकाबला करते हुए ही यहां की क्रान्तिकारी जनता तपकर फौलाद बन चुकी है. पहले की तुलना में अब इस आन्दोलन का ज्यादा फैलाव हुआ है और हजारों लोग इससे जुड़ गए हैं तो तीसरे 'जन जागरण' अभियान को भी क्रान्तिकारी जनता निश्चित रूप से पराजित करेगी, भले ही इसके उसे कई कुरबानियां क्यों न देनी पड़ें.

'जन जागरण' अभियान एक साजिश है !

पिछले मई महीने में दक्षिण बस्तर के विंजरम और पश्चिम बस्तर के कर्रेमरका में पीएलजीए सैनिकों ने आतंकी सीआरपी बलों पर शूरतापूर्वक हमले किए थे. इनमें एक दर्जन से ज्यादा पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया गया तथा करीब दो दर्जन को घायल किया गया था. इससे बौखलाए लुटेरे शासक वर्गों ने एक साजिश के तहत जहरीला दुष्प्रचार अभियान छेड़ दिया. एक तरफ व्यापक पुलिसिया दमन चलाते हुए ही दूसरी तरफ गुपचुप तरीके से गांवों में मौजूद दुष्ट मुखियाओं, सरपंचों तथा कांग्रेसी व भाजपाई कार्यकर्ताओं को बुलाकर मंत्रणाएं की गईं. महेन्द्र कर्मा व पुलिस अधिकारियों ने उनसे बात करके एक और 'जन जागरण' दमन अभियान की जमीनी तैयारियां पूरी कीं. इसे केन्द्रीय गृहमंत्री की अगुवाई में चलने वाली संयुक्त ऑपरेशनल कमान की देखरेख और मार्गदर्शन में शुरू किया गया है.

ज्यों ही यह दमन अभियान तेज हुआ, पुलिस–प्रशासन ने तमाम प्रसार माध्यमों (अखबार, रेडियो, टीवी) का दुरुपयोग करते हुए झूठे बयान देना, तोड़ी–मरोड़ी गई खबरें फैलाना शुरू किया. ''नक्सली विकास विरोधी हैं'', ''तेन्दुपत्ता काम बन्द करवाया'', ''आदिवासी संस्कृति व रीति–रिवाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं'', ''हाट बाजार बन्द करवाया'', ''आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं'' – आदि आरोपों की झड़ी लगाते हुए लगातार झूठी खबरें फैलाई गईं. अखबार वालों ने भी अपने प्रतिक्रियावादी चरित्र के अनुरूप सचाई को दफनाने की पूरी कोशिश की. पुलिस अधिकारी स्वयं रिपोर्टें लिखकर तमाम अखबारों में छपवा रहे हैं. जनता के पक्षधर पत्रकारों को इलाके में घूमने का मौका ही नहीं

मूकावेल्ली गांव में 'सलवा जुडूम' गुण्डों व पुलिस के पाशविक हमले में मारी गई महिलाएं

'सलवा जुडूम' गुण्डों व पुलिस द्वारा जलाया गया गांव मज्झिमेंडरी

दिया जा रहा है. बीजापुर एसपी मनहर ने तो साफ आदेश दिया कि जो पत्रकार नक्सलियों को कवर करने आएगा उसे मरवाया जाए. इस तरह लोकतंत्र का मजाक उड़ाकर इस पाशविक अभियान को अंजाम दिया जा रहा है.

इसकी शुरूआत यूं हुई!

5 जून को ग्राम उसिकापटनम में अंबेली गांव के गन्नू पटेल, बंदेपारा गांव के मासा गायतल जैसे बदनाम मुखियाओं ने साजिश के तहत डीएकेएमएस के स्थानीय नेताओं को जन समस्याओं पर चर्चा करने के बहाने बुलाया था. इस गहरी साजिश से पूरी तरह अनजान संगठन सदस्य उनके पास गए थे जहां पहले से ही मीटिंग लगी हुई थी. उक्त मुखियाओं और उनके गुर्गों ने 5 संगठन सदस्यों को पकड़कर उनकी बुरी तरह पिटाई कर कुटरू पुलिस थाने में सौम्प दिया.

बाद में, 18 जून को 'जन जागरण' गुण्डावाहिनी, जिसमें लुटेरे मुखिया, सरपंच, सचिव और उनके गुर्गे शामिल थे, ने बड़ी संख्या में ताड़िमेंडरी गांव पर हमला किया. उन्होंने जनता और संगठन सदस्यों को आत्मसमर्पण करने, 'सलवा जुडूम' में शामिल होने, नक्सलवादियों को गांवों में न आने देने की धमकियां दीं. इस मौके पर उनकी पकड़ में आए दो संगठन सदस्यों की बुरी तरह पिटाई की और कुल्हाड़ियों से घायल किया.

यह खबर सुनकर आसपास के गांवों की जन मिलिशिया एवं पीएलजीए के अन्य सैनिकों ने ताड़िमेंडरी गांव की जनता के बचाव में आकर 'जन जागरण' गुण्डों पर पलटा हमला कर दिया जिससे वे दुम दबाकर भाग गए. शासक वर्गों ने यह प्रचारित किया कि इस हमले में बड़ी संख्या में आदिवासी मारे गए और कुछ लापता हो गए. पर सचाई यह है कि इस प्रतिरोध में एक भी व्यक्ति नहीं मारा गया.

कोतरापाल जनता का बहादुराना प्रतिरोध

कुटरू से नैमेड़-भैरमगढ़ तक जाने वाली सड़क से इंद्रावती नदी के बीच स्थित कम से कम 70 गांवों में क्रान्तिकारी आन्दोलन का विस्तार नहीं हो सका है. क्रान्तिकारी आन्दोलन से सीधा संपर्क न होने के कारण इन गांवों के लोगों को बहला-फुसलाकर 'जन जागरण' मीटिंगों में बुलाने में पुलिस-प्रशासन व गुण्डावाहिनी को ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है. इन गांवों और भैरमगढ़-बीजापुर सड़क पर स्थित कुछ गांवों के लोगों को साम-दाम-दण्ड-भेद के तरीकों से बुलाकर 18 जून को माटवाड़ा में एक सभा आयोजित की गई जिसमें 3 हजार लोगों ने भाग लिया. महेन्द्र कर्मा के साथ-साथ स्थानीय मुखिया कोरसा सुकलू, लेकाम जिलाराम ने भी इसमें भाग लिया. इन्द्रावती इलाके के सत्तुवा, बैल और धरमा गांवों के कुछ असामाजिक तत्व, जिन्हें वहां की जनता ने अलग-अलग कारणों

अरियाल सामूहिक हत्याकाण्ड की निंदा करो !

पश्चिम बस्तर डिवीजन के मिरतुल पुलिस थाने से 2 किलोमीटर दूर स्थित अरियाल गांव पिछले 5 महीनों से लगातार जारी सफेद आतंक के बावजूद दुश्मन के सामने नहीं झुका है. 'सलवा जुडूम' के गुण्डों और पुलिस के हमलों और धमकियों की परवाह किए बिना गांव के लोग अपनी रक्षा के लिए जंगल में रहते हुए दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं. 'सलवा जुडूम' के चलते नक्सलवादी भाग रहे हैं और कई गांव झुककर उसके पक्ष हो गए हैं कहकर ढिंढोरा पीटने वाले महेन्द्र कर्मा और उसके गुर्गों को यह गांव एक चुनौती बन गया. इसीलिए किसी भी तरह इस गांव को झुकाने के लिए उन्होंने साजिश रची. हालांकि अरियाल गांव का कुख्यात मुखिया दोर्रु मंगू, जो शुरू से ही जनता के खिलाफ था, इस बार भी 'सलवा जुडूम' में शामिल होकर नेता बन गया. इसने पुलिस व गुण्डों को गलत सूचना दी थी कि उसके गांव के संगठन सदस्य पुलिस पर हमला करने वाले हैं. उसने पुलिस को जंगल में गांव के लोगों के छिपने का ठिकाना भी बता दिया. तो पुलिस ने एक एक बड़ा हमला कर अरियाल गांव के 10 निहत्थे लोगों को पकड़ लिया. तब वे जंगल में खुद को छुपाने जा रहे थे. उन्होंने चिल्ला-चिल्लाकर कहा कि हम आम ग्रामीण हैं जो डर के मारे जंगल में जा रहे हैं. लेकिन पुलिस दरिंदों के कान में जूं तक नहीं रेंगी. पहले से ही एक बड़े हत्याकाण्ड को अंजाम देने का मन बना चुके पुलिस वालों ने उन्हें लाइन में खड़ा करके गोलियां बरसाईं. बाद में घोषणा की कि उन्होंने 10 नक्सलियों को मार गिरा दिया. लेकिन उन्होंने अखबार वालों को एक भी तस्वीर जारी नहीं की क्योंकि उसे मालूम था कि इससे उनके जघन्य अपराध की पोल खुल सकती है. यहां तक कि उनके नामों की घोषणा भी नहीं की. इन 10 लोगों में 12 साल का एक छोटा बच्चा भी शामिल था जिसका नाम है कड़ती कुम्माल. लेकिन विडम्बना यह है कि एक बच्चा समेत 10 निहत्थे ग्रामीणों की जघन्य हत्या की इस घटना को बाहरी दुनिया जानती तक नहीं. पुलिस-प्रशासन ने अखबारों में ऐसी खबरें लिखने से मना कर, एक शब्द में कहें तो सारी मीडिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर जमीनी सच्चाईयों पर लौह परदा ओढ़ रखा है. जो वे लिखते हैं पही छपता है. 1 सितम्बर को घटित यह अमानवीय घटना यह बताती है कि छत्तीसगढ़ में लोगों के जीने का अधिकार घोर संकट में है. पुलिस ने उनकी लाशें भी गांव वालों को न देकर खुद ही जंगल में सामूहिक रूप से जला दीं. जिस दुष्ट मुखिया दोर्रु मंगू ने पुलिस को इत्तला देकर हमले के लिए उकसाया था, खुद उसके कुछ रिश्तेदार भी इस हत्याकाण्ड में मारे गए.

इस हत्याकाण्ड में मारे गए लोगों के नाम : कड़ती चिन्नाल (38), कड़ती सन्नू (35), कड़ती कमलू (42), कड़ती आयतू (45), कड़ती रामाल (50), कड़ती कुम्माल (12), ऊजी मासाराम (35), ऊजी जयराम (41), एमला सुक्कू (29) और कड़ती बधरू (32). 'प्रभात' इन लोगों की मृत्यु पर शोक प्रकट करती है और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है. ✶

विकास विरोधी कौन हैं?

नक्सलियों को विकास के विरोधी कहने वाले शासन को इस सवाल का जवाब देना होगा कि 58 सालों की 'आजादी' के बाद भी देश की अत्यधिक जनता दो जून की रोटी के लिए मोहताज क्यों है. यह भी बताना होगा कि उन इलाकों में भी आज गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी आदि समस्याएं क्यों व्याप्त हैं जहां नक्सलवाद का नामोनिशान भी नहीं है. बैलाडीला के खदानों से करोड़ों रुपए का लोहा निकाला जाता है और बेहद सस्ते में जापानी साम्राज्यवादियों को बेचा जाता है, पर वहां की जनता का कितना विकास हो पाया? वर्ष 2002 में 'बस्तर विकास' का नारा देकर नगरनार में स्टीलप्लान्ट लगाने के लिए लाठी और गोली के बल पर लोगों को जबरन विस्थापित किया गया था. सैकड़ों लोगों की जमीन छीनी गई थी और उन्हें उजाड़ दिया गया था. बस्तर के युवाओं को हजारों नौकरियां मिलने का सब्जबाग दिखाया गया था. लेकिन इससे कितना विकास हुआ, यह तो सारी जनता जानती है. वहां के निवासी बेघरबार होकर दर-दर भटक रहे हैं. बस्तर में औद्योगीकरण का मतलब बरबादी, विस्थापन और संसाधनों की लूट से ज्यादा कुछ नहीं है, यह सच्चाई कई बार साबित हो चुकी है. हम बड़ी परियोजनाओं और बड़े उद्योगों का विरोध कर रहे हैं. ये सब आधुनिक एवं मशीनीकृत हैं और नौकरियों की गुंजाइश न के बराबर है. हम ही नहीं रायपुर के आसपास के चौरेंगा, बेमता, चिचोली, आदि अनेक गांवों की आम जनता भी आज 'उद्योग भगाओ – खेत बचाओ' का नारा देकर स्पंज अयरन उद्योगों का विरोध कर रही है क्योंकि इन उद्योगों से गांवों के हरे-भरे खेत चौपट हो रहे हैं. कारखानों के काले धुंए से ग्रामीण जन जीवन अंधेरी की गर्त में तबाह हो रहा है. देश के कई संगठन और कई लोग बड़ी परियोजनाओं का मुखर विरोध कर रहे हैं. इसका मतलब यह नहीं कि वे विकास का विरोध कर रहे हैं. हम जनता के सच्चे व चौमुखी विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं. अगर छोटे व मध्यम पूंजीपति यहां उद्योग खोलने सामने आते हैं और उनसे जनता के अस्तित्व को तथा पर्यावरण (जल, जंगल व जमीन) को कोई खतरा न हो और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले तो हमारी जनता उनका विरोध नहीं करती. लुटेरी सरकारें यहां 'विकास' के नाम से जो उद्योग या परियोजनाएं ला रही हैं उससे दरअसल दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों, साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और दलाल नेताओं का ही 'विकास' होगा. इसके कितने भी उदाहरण दिए जा सकते हैं. बैलाडीला, नगरनार, एस्सार पाइप लाइन, रावघाट, बोधघाट, टाटा स्टील, एस्सार स्टील आदि सभी से जनता का विनाश और विस्थापन ही हुआ है और होने वाला है. ✶

से दण्डित किया था, इसमें सक्रिय भूमिका निभाने लग गए. पुलिस और इन गुण्डों ने करीब एक हजार जनता को हांकते हुए ले जाकर पास में स्थित कोतरापाल गांव पर हमला कर दिया. गांव में डीएकेएमएस व केएएमएस सदस्यों ने इस खतरे को पहले ही भांपकर बूढ़ों और बच्चों को गांव से बाहर भेज दिया. गांव के तमाम युवती-युवकों ने दो दलों में बंटकर तीर-धनुषों से लैस होकर जवाबी हमले की योजना बनाई. ज्यों ही घातक हथियारों से लैस 'जन जागरण' की गुण्डावाहिनी ने गांव में कदम रखा, तो तुरन्त हमला बोल दिया. इसमें तीन गुण्डे मौके पर ही मारे गए, जबकि 12 गुण्डा नेताओं को लोगों ने दौड़ा-दौड़ाकर पकड़ लिया. गुण्डावाहिनी की सुरक्षा में आई पुलिस भी इस अप्रत्याशित जन प्रतिरोध से इस कदर भयभीत हो गई कि वह जान हथेली पर रखकर भैरमगढ़ थाने तक भाग गई. कोतरापाल की जनता, खासकर नौजवानों ने खुद की रक्षा करने जिस अदम्य साहस व पहलकदमी का प्रदर्शन किया, वह समूचे दण्डकारण्य के जन समुदायों के लिए एक नमूना है. सचाई यह रही तो लुटेरे शासक वर्गों के टुकड़ों पर पलने वाली मीडिया ने इसे ''जनता पर नक्सलवादियों का हमला'' बताकर इसमें 12 लोगों के मारे जाने की झूठी खबरें परोस दीं.

कोतरापाल पर पुलिस का पाशविक हमला

18 जून के जन प्रतिरोध से बौखलाए पुलिस-प्रशासन ने कोतरापाल गांव पर फिर 1 जुलाई को अमानवीय हमला किया. बस्तर आई.जी. एमडब्ल्यू अंसारी, बीजापुर एसपी मनहर और महेन्द्र कर्मा की अगुवाई में सैकड़ों पुलिस-गुण्डावाहिनी ने गांव पर ऐसा हमला कर दिया जैसे किसी आक्रमणकारी सेना दुश्मन देश पर करती है. हमले की आशंका से सभी लोग पहले ही जंगल में शरण लिए हुए थे. पुलिस व गुण्डावाहिनी ने 8 घरों में आग लगाई. सुअर, मुरगा, बकरा, आदि पालतू जानवरों को तीरों से मारकर उठा ले गए. इस सारे पाशविक काण्ड को महेन्द्र कर्मा खुद नेतृत्व कर रहा था तो कलेक्टर व अन्य प्रशासनिक अमला तमाशा देख रहे थे. इस बीच गांव में लौट रहे दो बुजुर्ग किसानों उइके सन्नू (56) और वंजम मंगू (53) की सीआरपी बलों ने निर्मम हत्या की. एक अन्य बूढ़ी महिला को भी गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया. करीब 2-3 घण्टों तक आतंक का यह नंगा नाच चलता रहा.

'सलवा जुडूम' को 'शांति मिशन' कहना बहुत बड़ी साजिश

इसके पहले 20-22 जून को बीजापुर में 'जन जागरण' गुण्डों की सभा आयोजित की गई थी. इसकी अगुवाई महेन्द्र कर्मा, प्रभारी मंत्री केदार कश्यप और विधायक राजेन्द्र पामभोई ने की थी. इसमें नक्सलवादियों को बस्तर से भगाने का संकल्प दोहराया गया. अपने इस जुल्मी अभियान को 'सलवा जुडूम' का नाम देकर इसकी व्याख्या 'शांति मिशन' के रूप में की गई. 'शांति' के घिसे-पिटे राग आलापे गए. 'जुडूम' का अर्थ 'सामूहिक शिकार' है – यह बात गोंडी भाषा जानने वाला हर इनसान जानता है. और शिकार कभी अहिंसात्मक रूप से नहीं हो सकता. लोगों के घर जलाना, गोलियों से भून डालना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना, सुअर-मुरगा मारना, घरों को लूटना – ये सब किस 'शांति मिशन' का हिस्सा है, हर नागरिक को सोचना है. पुलिस-गुण्डावाहिनी संयुक्त रूप से बस्तर के अन्दरूनी इलाकों में हत्या, आगजनी, बलात्कार और लूट का जो भयानक मुहिम चला रही है, इस पर परदा डालने की कोशिश ही है इसे 'शांति मिशन' और 'सस्फूर्त जन आन्दोलन' कहना.

जुल्म व आतंक का सिलसिला जारी

– अगस्त के पहले सप्ताह में मज्रिमेंडरी गांव पर पुलिस व गुण्डावाहिनी हमला करके सभी घरों को जला डाला. सुअरबाड़ों, मुरगाबाड़ों को भी जलाकर अपनी पाशविकता का नंगा प्रदर्शन किया. जो भी सुअर, बकरा, मुरगा मिला उसे तीरों से मारकर खा लिया. गांव की जनता पहले ही घर छोड़कर जंगल में भाग चुकी थी. उसी दिन गांव तुमिरिगुण्डा में संगठन नेता मंगडू का घर समेत 4 घर जला दिए. उन्होंने

मंगडू की बीवी को गिरफ्तार कर प्रताड़ित करके बाद में छोड़ दिया. ग्राम केरपे में भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया. महेन्द्र कर्मा ने खुद केरपे में डेरा डालकर इस सारे दमनकाण्ड को संचालित किया.

– फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के कर्रेमरका पर हमला करके पुलिस–गुण्डावाहिनी ने संगठन सदस्य माराल का घर जला दिया. 6 लोगों को गिरफ्तार किया. उन्हें रोकने की कोशिश करने पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया.

– मरकोड़ी गांव के कुछ किसान अपने रिश्तेदारों की शादी के सिलसिले में जब अपने पुश्तैनी गांव गए थे तो उन्हें 'जन जागरण' गुण्डावाहिनी ने पकड़ लिया. गांव वालों को उसने यह चेतावनी दी कि यदि वे 'जन जागरण' में शामिल नहीं होंगे तो उनकी हत्या की जाएगी. इससे मरकोड़ी गांव की जनता घबराकर 'जन जागरण' में शामिल हो गई. इस प्रकार धमकी, अपहरण, लूट, आगजनी, बलात्कार, आदि तमाम हथकण्डे अपनाकर ग्रामीणों पर दबाव डाला जा रहा है कि वे 'जन जागरण' में शामिल हो जाएं.

– 22 जुलाई को पुलिस–प्रशासन ने ग्राम मुण्डेर पर कहर बरपाया. यह गांव महेन्द्र कर्मा का गृहग्राम फरसापाल से मात्र 8 किलोमीटर दूर पर स्थित है. आइजी अंसारी के प्रत्यक्ष नेतृत्व में दरिन्दों ने पूरे गांव को लूट लिया. मुरगा, सुअर, बकरों को तीरों से मार डाला. पूरे 10 घरों में आग लगा दी. गांव का एक भी व्यक्ति उनकी पकड़ में नहीं आया क्योंकि सब अपनी जान बचाने के लिए पहले ही जंगल में भाग चुके थे. इस गुस्से से 25 जुलाई को इस गांव पर फिर एक बार हमला किया. जो आदमी दिखाई दिया उसकी पिटाई कर दी. इस गांव को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया.

– 25 जुलाई को फूलगट्टा गांव पर भी गुण्डावाहिनी ने हमला कर दिया. दो गांवों से लगभग 50 लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने गुण्डों के सामने झुककर 'जन जागरण' में शामिल होने से मना किया था.

– 20 जुलाई की रात पीएलजीए के नेतृत्व में जनता ने गांव पोंदुम में कुछ जन दुश्मनों पर हमला कर उन्हें सजा दी. इससे बौखलाकर पुलिस व गुण्डावाहिनी ने अगले दिन उस गांव पर हमला करके 2 किसानों के घर जला दिए. गांव पल्लेवाया पर छापेमारी करके घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट मचाई. 8 घरों को आग के हवाले किया और 10 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें तीन महिलाएं शामिल हैं.

– 29 जुलाई को गुण्डावाहिनी–पुलिस ने कर्रेबोदली गांव पर हमला करके तबाही मचाई. 10 घरों में आग लगाई. जो मिला उसकी पिटाई की. एक संगठन सदस्य का पैर काट डाला. 15 लोगों को गिरफ्तार किया.

– इस बीच 11 अगस्त को कोतरापाल गांव पर फिर एक बार हमला करके 3 अन्य लोगों की हत्या की गई. मारे गए किसानों के नाम आटम बोडी और लेकम बुधराम हैं. एक का नाम पता नहीं चला है.

– गांव कत्तूर के दो किसान कुटरू बाजार गए थे जिन्हें गुण्डावाहिनी–पुलिस ने पकड़ लिया. उनमें से एक की हत्या कर सिर को कलम कर धड़े को सड़क पर फेंक दिया और सिर को जंगल में फेंक दिया. रोंगटे खड़े कर देने वाली ये हत्याएं मध्ययुगीन बर्बरता को याद दिलाती हैं.

– गंगलूर इलाके में गुण्डावाहिनी–पुलिस ने व्यापक तबाही व कत्लेआम मचाया. अगस्त के आखिरी सप्ताह में पोट्टेम में 8 घर, तूडेम में पूरा गांव, डोलकल में 3 घर, आकवा में 18 घर, जोजेर में 3 घर जला दिए. ईरिल गांव के सुक्कू नामक किसान की जघन्य हत्या की. उसका सिर काटकर मकई के खेत में टांग दिया तथा धड़ा कहीं और फेंक दिया.

– मज्जीमेंडरी, कोतरापाल, मनकेली, मुंडेर, पोट्टेम, पुल्लुम, आलवूर, पेद्दा जोजेर, चिन्ना कोरमा आदि गांवों को लगभग पूरी तरह जला दिया गया. घर जलाने के लिए वे बाकायदा डीजिल व मिट्टी तेल के स्प्रेयर साथ लेकर आ रहे हैं और घरों पर छिड़कने के बाद ही आग लगा रहे हैं.

– 15 अगस्त के दिन जांगला गांव में 5 लोगों के घर जला डाला गया. बेकसूर लोगों के घर जलाकर पुलिस–गुण्डावाहिनी ने 'आजादी' का जश्न मनाया.

– 5 अक्टूबर को बीजापुर तहसील के मूकावेल्ली गांव में 'सलवा जुडूम' के गुण्डों व पुलिस ने धावा बोला. अपने खेत की रखवाली कर रही दो महिलाओं – वेडिंजे नंगी और वेडिंजे मल्ली (वेडिंजे चिन्नाल की दो पत्नियों) को गोली मार दी. उन दरिंदों ने डेढ़ साल के छोटे बच्चे को भी गोली मार दी जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया. मारी गई महिलाओं में एक गर्भवती थी जिसे गोली मारने से वह वहीं गिर पड़ी थी. बाद में पुलिस व गुण्डों ने उसकी कोख को चीरकर भ्रूण को बाहर निकालकर बाद में दोनों की हत्या की. दिल दहला देने वाले इन कुकर्मों को अंजाम देने के बाद फिर 8 तारीख को एक और हमला करके 10 घर जला दिए. पूरा गांव लूट दिया. इतने में पीएलजीए सैनिक वहां पहुंचे और जवाबी हमला कर दिया. पुलिस व गुण्डे गोलाबारी करते हुए भाग गए.

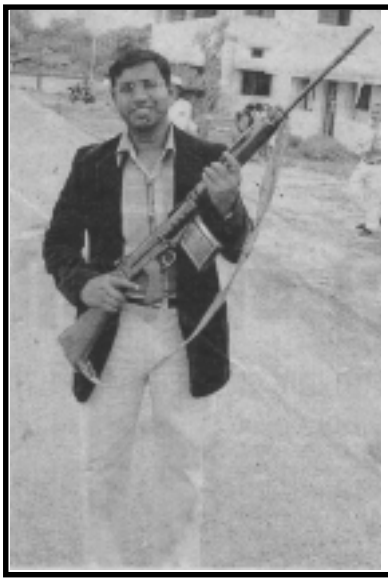

इस तस्वीर में जो आदमी दिखाई दे रहा है वह कोई पुलिस अधिकारी नहीं है, बल्कि कांकेर जिले का कलेक्टर डॉ. एस.के. राजू है. दक्षिण बस्तर में उठे 'जन जागरण' अभियान को कांकेर जिले में भी चलाने के लिए उतावले होते हुए इसने हाथ में बन्दूक लेकर यह तस्वीर खिंचवाई. इस दमन अभियान को 'आदिवासी जनता का सस्फूर्त संघर्ष' कहकर किए जा रहे प्रचार में अगर रत्ती भर भी सचाई है तो एक प्रशासनिक अधिकारी के हाथ में बन्दूक क्यों है? अगर यह 'शान्ति मार्च' है तो बन्दूक की जरूरत ही क्या है – वह भी एक कलेक्टर के हाथ में? इसे देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है वर्तमान 'सलवा जुडूम' या 'जन जागरण' अभियान न तो 'स्वस्फूर्त' आन्दोलन है न ही 'शांतिपूर्ण'. इसे नव गठित भाकपा (माओवादी) के खिलाफ केन्द्र–राज्य सरकारों द्वारा छेड़े गए देशव्यापी हमले से जोड़कर देखना चाहिए जिसे शासन–प्रशासन–पुलिस ने एक सोची–समझी साजिश के तहत शुरू किया है. ✶

महिलाओं के साथ बलात्कार को जन दमन के साधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे अर्ध-सैनिक बलों को मुंहतोड़ जवाब दो !

दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन का सफाया करने की मुहिम के तहत संघर्ष इलाकों में तैनात अर्ध सैनिक बलों द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं. पिछले कुछ सालों से क्रान्तिकारी आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. सभाओं, प्रदर्शनों, आदि में उनका बड़ी संख्या में भाग लेना और केएएमएस में संगठित होना, मिलिशिया में बड़ी संख्या में भर्ती होकर पुलिस बलों का प्रतिरोध करना, पीएलजीए में बड़ी संख्या में भर्ती हो जाना बढ़ा है. इसे देखकर बौखलाए दुश्मन ने अपने वर्तमान दमन अभियान के दौरान महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार कर हत्या करने की क्रूरतापूर्ण तरीका अपनाया हुआ है. पिछले 5 महीनों के 'जन जागरण' अभियान में स्पष्ट रूप से देखा गया है कि पुलिस-प्रशासन ने महिलाओं के साथ बलात्कार को दमन के एक साधन के रूप में ईजाद किया है.

अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस जुल्मी अभियान में 30 से ज्यादा महिलाएं बलात्कार का शिकार हुईं. पांच महिलाओं की हत्या की गई. इनमें दो महिलाएं गर्भवती थीं. गांवों में छापेमारियों के दौरान गिरफ्तार की जाने वाली महिलाओं तथा 'सलवा जुडूम' के गुण्डों के दबाव और खौफ से उनके पास जाने वाली महिलाओं को थानों में रखकर उनके साथ बलात्कार करना आम हो गया. खासकर कुटरू पुलिस थाना यातनाओं और बलात्कार का एक बड़ा शिविर बना है.

पुलिस व 'सलवा जुडूम' के गुण्डों द्वारा सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई महिलाओं के नाम

	महिला का नाम	गांव
1)	माड़वी बुधरी	कोण्डम
2)	सोमली	कोण्डम
3)	मुन्नी	कोण्डम
4)	मोडियम संपो	कर्रेबोधली
5)	मोडियम सीमो	कर्रेबोधली
6)	ओयम बाली	पल्लेवाया
7)	माड़वी पार्वती	कर्रे पोन्दुम
8)	माड़वी कोपे	कर्रे पोन्दुम
9)	रुकनी	कर्रे पोन्दुम
10)	बोग्गम गूगे (गर्भवती)	नीलम
11)	कड़ती मुन्नी	फूलगट्टा
12)	कड़ती पाण्डे	वेद्दम
13)	कोरसा मुन्नी	जांगला
14)	कलमू जय्यू	जांगला
15)	कोरसा बुटकी	जांगला
16)	माड़वी सरिता	कर्रेमरका
17)	तेल्लम जमली	कर्रेमरका
18)	कड़ती जयमती	अरियाल
19)	सुखमती	पिट्टडगूडेम
20)	–	कोतरापाल
21)	–	कोतरापाल
22)	–	कोतरापाल
23)	–	कोपाल
24)	–	कोपाल
25)	कुरसा संतो	फूलगट्टा

बलात्कार के बाद हत्या की गई महिलाओं के नाम

1)	मोडियम सुक्की	पेद्दा कोरमा
2)	कुरसम लक्के	पेद्दा कोरमा
3)	मड़काम सन्नी (गर्भवती)	एटेपाड़
4)	वेडिंजे मल्ली	मूकावेल्ली
5)	वेडिंजे नंगी (गर्भवती)	मूकावेल्ली
6)	बोग्गम सोमवारी	कोटलू

– अक्टूबर के पहले सप्ताह में जेगुरगोण्डा क्षेत्र के राजुम गांव में गुण्डों व पुलिस ने 5 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार कर बाद में उनकी हत्या की. एक किसान जब सल्फी के पेड़ पर था तो उसे वहीं गोली मार दी, जिससे वह मरकर गिर पड़ा.

– 25 सितम्बर को बीजापुर तहसील के मनकेली गांव में 'सलवा जुडूम' की सभा होने की घोषणा की गई थी. पर दरअसल उस दिन वहां सभा नहीं बल्कि अत्याचार व कत्लेआम हुए थे. गुण्डों व पुलिस ने दो निरीह किसानों की जघन्य हत्या की और गांव के 20 से ज्यादा घर जला दिए. 5 महिलाओं और 2 बच्चों को गिरफ्तार किया जिनका अब तक कोई अता-पता नहीं है.

– कुटरू में 'सलवा जुडूम' गुण्डों व पुलिस ने एक बड़ा यातना शिविर खोल रखा है. पकड़े गए आदिवासियों को यहां पर हर रात घोर यातनाएं दे रहे हैं. यातनाओं के चलते कई लोगों ने दम तोड़ दिया है. बर्बरता का आलम यह है कि उनकी लाशें जहां-तहां फेंक रहे हैं जिन्हें कुत्ते काट रहे हैं. इसके अलावा कुछ लाशों को इंद्रावती नदी में डाल दिया गया. इस क्षेत्र के लोगों ने कम से कम ऐसी चार लाशों को पानी में बहते देखा जिनके सिर कलम कर दिए गए थे.

व्यापक आतंक का यह सिलसिला इन पंक्तियों के लिखे-जाने तक जारी ही है. मारे गए लोगों की सही संख्या मिलना भी मुश्किल हो रहा है.

पदयात्राओं का ढोंग

महेन्द्र कर्मा, केदार कश्यप व अन्य नेताओं की पदयात्राओं के सम्बन्ध में तरह-तरह की खबरें फैलाई गई थी. बाहरी दुनिया को यह शायद ही पता हो, मगर सच्चाई यह है कि जिन-जिन गांवों में पदयात्राएं सम्पन्न होने का दावा किया गया, उन तमाम गांवों में पुलिस-नगा फोर्स व 'जन जागरण' गुण्डावाहिनी ने हत्या, बलात्कार, आगजनी, लूट, आदि विध्वंसकारी कुकृत्य ही किए थे. कोड्डेली से मिरतुल तक महेन्द्र कर्मा द्वारा पदयात्रा की खबर पूरी तरह झूठी है, वहां पुलिस-गुण्डावाहिनी ने आतंक का ताण्डव मचाया था. जहां भी सभा या पदयात्रा के आयोजन की बात होती है, तो वहां की जनता पहले ही गांव खाली कर जंगल में शरण ले रही है. अब इस हिंसक अभियान को भोपालपट्टनम तथा कोंटा तहसीलों में फैलाने की जी तोड़ कोशिशें जारी हैं.

नन्हे बच्चों पर पुलिस की बर्बरता

पिछले 5 महीनों से पश्चिम बस्तर में 'सलवा जुडूम' या 'जन जागरण' के नाम पर जारी सफेद आतंक में बड़े ही नहीं, छोटे बच्चे भी मारे जा रहे हैं. रोंगटे खड़े कर देने वाले बर्बर अंदाज में उनकी हत्या की जा रही है. 'आपरेशन ग्रीन हन्ट' के नाम से जारी दमन अभियान के पहले दौर में 26 अगस्त को पोट्टेनार गांव पर हमला करने आ रहे नगा पुलिस बलों पर पीएलजीए ने घात लगाकर हमला किया था. इससे घबराकर पुलिस वाले भाग रहे थे. भागते समय जंगल में मवेशी चराने वाले चार चरवाह उन्हें मिले थे. दरिंदे पुलिस ने उन चारों लोगों को वहीं गोली मार दी और उन्हें नक्सली बताते हुए मुठभेड़ की घोषणा की. मारे गए चार लोगों में एक बच्चा भी शामिल था जिसकी उम्र महज 12 साल थी.

28 अगस्त को नगा पुलिस बलों और 'सलवा जुडूम' गुण्डों के संयुक्त झुण्ड ने आकवा गांव को घेरकर हमला किया. लेकिन गांव में एक भी आदमी उन्हें नहीं मिला. वहां पर 22 घरों में उन्होंने आग लगा दी. 12 साल का एक लड़का वहां छिपा हुआ मिला तो झुण्ड ने उसे पकड़कर उसका गला रेत डाला. सिर को एक जगह और धड़ को कहीं और फेंककर चले गए.

2 सितम्बर को मिरतुल से 2 किलोमीटर दूर पर स्थित अरियल गांव में गांव के जालिम मुखिया दोर्रु मंगू द्वारा दी गई सूचना के आधार पर नगा पुलिस ने छापा मारा. जंगल में तलाशी लेते समय उन्हें 10 आदमी दिखाई दिए जो डर के मारे जंगल में छिपे हुए थे. पुलिस ने उन सभी को लाइन में खड़े करवाकर गोली मार दी. इनमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था जिसका नाम है कड़ती कुम्माल. यह नन्हा कॉमरेड गांव में बाल संगठन का अध्यक्ष था.

10 अक्टूबर परालनार गांव में 14 साल का एक लड़का बारसा सोनू को भी पुलिस ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया. यह लड़का बुखार से पीड़ित था. गांव के मिलिशिया दस्ते के साथ दुश्मन के सम्भावित हमले का मुकाबला कर अपने गांव की रक्षा करने हेतु एक जगह इकट्ठे थे. धोखे से किए गए हमले में सोनू दुश्मन के हाथों पकड़ा गया, जो उस समय बुखार से कांपते हुए लेटा हुआ था. लेकिन बेहद अमानवीय ढंग से पुलिस ने उसे बुरी यातनाएं देने के बाद गोली मारकर हत्या की.

3 अक्टूबर को लोवा गांव पर पुलिस ने धावा बोला और अपने खेत में जुताई कर रहे कॉमरेड कोवाल को गिरफ्तार किया. कॉमरेड कोवाल मनकेली गांव के जनताना सरकार का अध्यक्ष था. उसे पुलिस ने वहीं गोली मार दी. उस समय कोवाल का 14 वर्षीय लड़का राजू भी वहीं था, वह इस जघन्य हत्या का चश्मदीद गवाह था. पुलिस उसे उठाकर ले गई. अभी तक उसका कोई अता-पता नहीं है. सम्भवतः पुलिस ने उसकी हत्या कर लाश कहीं फेंक दी होगी.

5 अक्टूबर को मूकावेल्ली गांव में अपने खेत में काम कर रही दो महिलाओं को गुण्डों और पुलिस ने पकड़कर उनकी हत्या की. इन दो महिलाओं में एक गर्भवती थी जिसकी कोख को पुलिस ने संगीनों से चीरकर पाशविकता का प्रदर्शन किया. वहीं पर डेढ़ साल के एक और छोटे बच्चे को भी पुलिस ने गोली मारकर घायल कर दिया.

दुश्मन शायद यह सोच रहा होगा कि वह ऐसी हत्याओं से लोगों में दहशत फैलाकर क्रान्तिकारी आन्दोलन का सफाया कर देगा. पर सच्चाई यह है कि अपने बच्चों को खो चुकी मांओं के दिल में भड़क रही नफरत की आग में लुटेरे शासक वर्गों और उनके भाड़े के पुलिस बलों का झुलसकर राख हो जाना निश्चित है. ✶

जन आन्दोलन के खिलाफ चौतरफा हमला

एक तरफ इस दमनकारी अभियान को जारी रखते हुए ही दूसरी तरफ 'कॉर्पेट सेक्यूरिटी' के नाम पर कई गांवों में पुलिस कैम्प बिठा दिए गए. बोदली, पिण्डुम, माटवाडा, कोड्डेली, नैमेड, तोयनार, गोदुमा, संकेनपल्ली, करकेली, अम्बेली, आदि गांवों में पुलिस कैम्प खोलकर आसपास के गांवों में दहशत फैलाई जा रही है. और अधिक अर्द्ध सैनिक बलों के लिए रमन सरकार लगातार केन्द्र से मांग कर रही है. महेन्द्र कर्मा अनेक बार खुद दिल्ली जाकर सोनिया गांधी व मनमोहन सिंह से बात कर आया है. इसे एक नमूने के तौर पर लेकर देश भर में लागू करने की बातें की जा रही हैं. इस 'जन जागरण' अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए अर्द्ध सैनिक बलों की रणनीतिक तैनाती के साथ-साथ राज्य सरकार दो पुलिस अधीक्षक, 3 डीएसपी, 10 निरीक्षक, 10-10 उप-निरीक्षक व सहायक निरीक्षक सिर्फ 'जन जागरण' के गुण्डों व नेताओं की सुरक्षा में भेजे.

'आपरेशन रक्षक' और 'आपरेशन ग्रीन हंट' के नाम से वर्तमान में दमन अभियान चलाए जा रहा है. इसके साथ ही गांवों में 'ग्राम सुरक्षा समिति' का निर्माण कर उन्हें हथियार भी देने की घोषणा भी की गई. कश्मीर की तर्ज पर यहां भी कुछ युवकों को विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के तौर पर नियुक्ति की जा रही हैं. कुछेक गुण्डों को दन्तेवाड़ा में ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है. जनता में से एक तबके को अपनी तरफ रिझाकर मुखबिर नेटवर्क बनाने के लिए पुलिस-प्रशासन एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा है.

19 सितम्बर को दिल्ली में आयोजित नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में संयुक्त टास्कफोर्स का तत्काल गठन करने, सभी राज्यों के बीच बेहतर तालमेल, खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान, पुलिस व अर्ध सैनिक बल बढ़ाने, बलों का आधुनिकीकरण करने, आदि फैसले लिए गए. इससे यह स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में क्रान्तिकारी आन्दोलन पर चौतरफा हमला और बढ़ने वाला है.

जनता का शानदार प्रतिरोध

जबसे 'जन जागरण' के नाम से यह दमनकारी अभियान शुरू हो गया तभी से जनता का प्रतिरोध भी शुरू हो चुका है. पार्टी, पीएलजीए, जन संगठनों तथा जनता ने अब तक अनेक जवाबी हमले किए. 3 सितम्बर को पद्देड़ के पास पीएलजीए द्वारा किए गए जबर्दस्त एम्बुश में 24 सीआरपीएफ जवान मारे गए तथा 3 अन्य घायल हो गए. (इसकी तफसील रिपोर्ट पेज 31 में है.) इस हमले ने शासक वर्गों को हिलाकर रख दिया. उसके पहले बोदली, उसिकापट्टनम, अम्बेली, आदि गांवों में जनता ने 'जन जागरण' में सक्रिय भाग ले रहे 7-8 कट्टर गुण्डों को मार डाला. इसके अलावा बीजापुर में कांग्रेसी जनपद सदस्य विजय गिरी,

(शेष पेज 3 पर ....)

इस अभियान के तहत गुण्डों व पुलिस के हाथों मारे गए लोगों तथा बलात्कार का शिकार महिलाओं के नाम (अब तक मिली जानकारी के मुताबिक)

	मारे गए व्यक्ति का नाम	गांव का नाम	संगठन में भागीदारी	हत्या की तारीख
1)	कारम पाण्डु (45)	ईरिल	नहीं	2/9
2)	तामो सुखराम (20)	डुमरी परालनार	डीएकेएमएस कमेटी सदस्य	1/9
3)	आटम बोड़ा (30)	डुमरी परालनार	डीएकेएमएस सदस्य	11/8
4)	बोगमी सन्नू (18)	मुन्डेर	डीएकेएमएस सदस्य	28/8
5)	बोगामी कोटलाल (40)	दोरुम	नहीं	1/9
6)	बोगामी सोमवारी (36)	दोरुम	नहीं	1/9
7)	कड़ती बय्याल (45)	पुल्लादी	नहीं	1/9
8)	हेमला रेकाल (50)	पुल्लादि	नहीं	1/9
9)	मड़काम कुम्माल	हालवूर	डीएकेएमएस सदस्य	9/8
10)	तेल्लाम बुगुर (55)	हिन्डरी	दस्ता सदस्य का पिता	6/9
11)	लेकाम लखमू (50)	पोट्टेनार	डीएकेएमएस सदस्य	5/9
12)	माड़वी सोमारू (35)	पोट्टेनार	डीएकेएमएस सदस्य	5/9
13)	आलम महदेव (30)	पोट्टेनार	डीएकेएमएस सदस्य	5/9
14)	मोड़ियाम बोड्डाल (25)	पोट्टेनार	डीएकेएमएस सदस्य	5/9
15)	तामो रामू (35)	कर्रेमरका	डीएकेएमएस अध्यक्ष	16/8
16)	लेकम लक्कू (35)	जांगला	डीएकेएमएस सदस्य	27/8
17)	माड़वी पाकलू (35)	गोंगला	डीएकेएमएस सचिव	27/8
18)	..... (18)	जांगला	डीएकेएमएस सदस्य	–
19)	उइके सन्नू (50)	कोत्रापाल	नहीं	1/7
20)	वाजाम मंडा (55)	कोत्रापाल	नहीं	1/7
21)	लेखामी बुधराम (35)	कोत्रापाल	नहीं	11/8
22)	कड़ती चिन्ना (40)	हरियाल	नहीं	2/9
23)	कड़ती सन्नू (35)	हरियाल	नहीं	2/9
24)	कड़ती कमलू (35)	हरियाल	नहीं	2/9
25)	कड़ती आयतू (40)	हरियाल	नहीं	2/9
26)	कड़ती रामाल (45)	हरियाल	नहीं	2/9
27)	कड़ती कुम्माल (12)	हरियाल	बाल संगठन अध्यक्ष	2/9
28)	उजी मसाराम (40)	हरियाल	नहीं	2/9
29)	उजी जयराम (35)	हरियाल	नहीं	2/9
30)	एमला सुक्कू (40)	हरियाल	नहीं	2/9
31)	कड़ती बधरू (35)	हरियाल	नहीं	2/9
32)	माड़वी मेस्सा (35)	हिन्डी	डीएकेएमएस सदस्य	2/9
33)	पोट्टम चरी	पूसनार	डीएकेएमएस सदस्य	12/9
34)	एन्डीवु गुल्लू (22)	गोंगला	डीएकेएमएस सचिव	20/9
35)	पोट्टाम सोनू (20)	गोंगला	डीएकेएमएस कमेटी सदस्य	20/9
36)	कोरसा संतो (20)	पुलगट्टा	केएएमएस कमेटी सदस्य	2/9
37)	वेट्टो जोगा	कोंडम	डीएकेएमएस कमेटी सदस्य	3/9
38)	माड़वी लक्ष्मण	पल्लेवाया	डीएकेएमएस सदस्य	22/9
39)	कोरसा सुक्कू	मनकेल	डीएकेएमएस सदस्य	25/9
40)	पूनेम काण्डाल	मनकेल	डीएकेएमएस सदस्य	25/9
41)	मोड़ियम सूदरू	मनकेल	डीएकेएमएस सदस्य	15/9

	मारे गए व्यक्ति का नाम	गांव का नाम	संगठन में भागीदारी	हत्या की तारीख
42)	कड़ती कुम्माल	मुन्डेर	डीएकेएमएस सदस्य	3/9
43)	कड़ती कमलू	मुन्डेर	डीएकेएमएस सदस्य	10/9
44)	कलमा बधरू	नीलम	डीएकेएमएस सदस्य	15/9
45)	एमला कोवा	मनकेल	जनताना सरकार अध्यक्ष	3/10
46)	कुरसम आयतू	मनकेल	डीएकेएमएस सदस्य	3/10
47)	मोड़ियम सुक्की	पेद्दा कोरमा	केएएमएस अध्यक्ष	7/10
48)	कुरसाम लक्के	पेद्दा कोरमा	केएएमएस कमेटी सदस्य	7/10
49)	बाड़से सोमू	परालनार	बाल संगठन अध्यक्ष	11/10
50)	मड़काम चन्नू	परालनार	डीएकेएमएस सदस्य	9/10
51)	मड़काम चन्नी	एटेपाड़	डीएकेएमएस सदस्य	5/10
52)	आपका सोनू	पदेरा	मिलिशिया	13/9
53)	सोड़ी कोसा	गोरनम	मिलिशिया	15/5
54)	पूनेम बुधू	पुंबाड़	मिलिशिया	1/9
55)	पाकलू (उरसा चन्नू)	पामरा	दस्ता सदस्य	2/9
56)	एमला लच्छू	मोसला	डीएकेएमएस रेंज कमेटी अध्यक्ष	9/10
57)	माड़वी विज्जा (बोमड़ा)	केशकुत्तुल	दस्ता सदस्य	11/7
58)	वेडिंजे नंगी (24)	मूकावेल्ली	नहीं	5/10
59)	वेडिंजे मल्ली (23)	मूकावेल्ली	केएएमएस सदस्या	5/10
60)	तालि सोंबारू (35)	मुकराम	पार्टी सदस्य	10/9
61)	कोरके (20)	आलवाड़ा	डीएकेएमएस सदस्य	8/9
62)	विज्जाल (22)	आलवाड़ा	डीएकेएमएस सदस्य	8/9
63)	पूसू (25)	मोरिमडुगु	डीएकेएमएस सदस्य	20/9
64)	वेडिंजे सुरेश (23)	ताड़िमेंडरी	मिलिशिया कमाण्डर	20/9

(हमें अफसोस है कि भीषण दमन के चलते पुलिस के हाथों मारे गए तमाम लोगों के नाम हम इकट्ठे नहीं कर पाए.)

पुलिस व 'सलवा जुडूम' के गुण्डों द्वारा सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई महिलाओं के नाम

1)	माड़वी बुधरी	कोण्डम
2)	सोमली	कोण्डम
3)	मुन्नी	कोण्डम
4)	मोडियम संपो	कर्रेबोधली
5)	मोडियम सीमो	कर्रेबोधली
6)	ओयम बाली	पल्लेवाया
7)	माड़वी पार्वती	कर्रे पोन्दुम
8)	माड़वी कोपे	कर्रे पोन्दुम
9)	रुकनी	कर्रे पोन्दुम
10)	बोग्गम गूगे (गर्भवती)	नीलम
11)	कड़ती मुन्नी	फूलगट्टा
12)	कड़ती पाण्डे	वेद्यम
13)	कोरसा मुन्नी	जांगला
14)	कलमू जय्यू	जांगला
15)	कोरसा बुटकी	जांगला
16)	माड़वी सरिता	कर्रेमरका
17)	तेल्लम जमली	कर्रेमरका
18)	कड़ती जयमती	अरियाल
19)	सुखमती	पिट्टडगूडेम
20)	–	कोतरापाल
21)	–	कोतरापाल
22)	–	कोतरापाल
23)	–	कोतरापाल
24)	–	कोपाल
25)	कुरसा संतो	फूलगट्टा

बलात्कार के बाद हत्या की गई महिलाओं के नाम

1)	मोडियम सुक्की	पेद्दा कोरमा
2)	कुरसम लक्के	पेद्दा कोरमा
3)	मड़काम सन्नी (गर्भवती)	एटेपाड़
4)	वेडिंजे मल्ली	मूकावेल्ली
5)	वेडिंजे नंगी (गर्भवती)	मूकावेल्ली
6)	बोग्गम सोमवारी	कोटलू

श्रद्धांजलि

फासीवादी 'जन जागरण' अभियान का मुकाबला करते हुए अपनी जान कुरबान करने वाले

जन योद्धाओं, लोक नायकों और आम जनता को लाल सलाम !

पिछले जून महीने से 'जन जागरण' अभियान के नाम से जारी पाशविक व अमानवीय हमले में अब तक करीब 100 स्त्री-पुरुष मारे गए, जिनमें अत्यधिक आम लोग हैं. 50 से ज्यादा गांवों को पूरे या आंशिक तौर पर जला दिया गया. 30 से ज्यादा महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. इनमें कुछ महिलाएं गर्भवती थीं. कुछ महिलाओं को बलात्कार के बाद गोली मार दी गई. इतिहास में इसकी तुलना में बहुत कम उदाहरण मिलते हैं. इस जुल्मी अभियान के खिलाफ जनता का प्रतिरोध शुरू से ही जारी है. जनता ने इस अभियान की अगुवाई कर रहे कुछ कट्टर मुखिया और गुण्डों को मार डाला. 3 सितम्बर को पोंजेर के पास पीएलजीए सैनिकों ने जनता के प्रत्यक्ष सहयोग से पुलिस बलों के बहुचर्चित बारूदीसुरंग-रोधक वाहन (माइनप्रूफ गाड़ी) को उड़ाकर 24 सीआरपी जवानों को मार डाला. जहां कहीं भी पुलिस व गुण्डे गांवों पर हमले करने आ रहे हैं जनता, जन मिलिशिया और पीएलजीए के अन्य बलों के सैनिक जहां तक सम्भव हो उन पर जवाबी हमले कर रहे हैं. दरअसल इस जबर्दस्त जन प्रतिरोध की बदौलत ही गुण्डों व पुलिस के मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे हैं. गुण्डा नेता महेन्द्र कर्मा इस जुल्मी अभियान को समूचे बस्तर में फैलाने की जी-तोड़ कोशिश कर रहा है. 2006 तक बस्तर में नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया करने के दावे करते हुए अपनी बौखलाहट का प्रदर्शन कर रहा है. लेकिन जनता इस दमन अभियान का मुंहतोड़ जवाब देगी, गुण्डा नेताओं को कड़ा सबक सिखा देगी. जनता ही इतिहास का निर्माता है, अन्तिम विजय जनता की ही होगी.

कॉमरेड विज्जाल

मारे गए तमाम लोग क्रान्ति के समर्थक थे. वे किसी न किसी रूप में क्रान्तिकारी आन्दोलन में शामिल थे. कई लोग अपने-अपने गांवों में जन संगठनों, जन मिलिशिया और जनताना सरकार में अलग-अलग जिम्मेदारी निभाते रहे थे. इनमें कुछ पीएलजीए के लाल योद्धा भी शामिल हैं. ऐसे लोग भी इनमें शामिल हैं जो किसी भी संगठन में नहीं थे, पर वे क्रान्ति का समर्थक जरूर करते थे. ये सभी लोग भारत की नव जनवादी क्रान्ति को सफल बनाने के लक्ष्य से जारी जनयुद्ध के वीर शहीद हैं. भाकपा (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी इन तमाम लोगों को नम्रतापूर्वक श्रद्धांजली पेश करती है. इनके अधूरे सपनों को पूरा कर इनकी शहादत का बदला लेने की शपथ लेती है. हम इस मौके पर दण्डकारण्य के तमाम जनता से अहवान कर रहे हैं कि पश्चिम बस्तर के शहीदों की याद में गांव-गांव में शोकसभाओं और जुलूसों का आयोजन करें. उनकी शहादत को श्रद्धांजली पेश करें. इस भयानक दमन अभियान में अपने घरों, फसलों, पालतू जानवरों, सम्पत्तियों और प्रियजनों को खो चुके जनता के प्रति संवेदना व हार्दिक समर्थन प्रकट करें. दण्डकारण्य की संघर्षशील जनता से हम अपील करते हैं कि समूचे दण्डकारण्य में लुटेरे शासक वर्गों और उनके भाड़े के पुलिस व अर्ध सैनिक बलों के खिलाफ जनयुद्ध को तेज कर पश्चिम बस्तर के शहीदों के खून का बदला लें.

आइए, इनमें से कुछ वीर शहीदों के जीवन का संक्षिप्त परिचय लें.

पीएलजीए का जांबाज योद्धा कॉमरेड विज्जाल (माड़वी बोमडा)

11 जुलाई 2005 को बस्तर जनता का अव्वल नम्बर दुश्मन महेन्द्र कर्मा की अगुवाई में जारी 'जन जागरण' अभियान के तहत दन्तेवाड़ा जिले के ग्राम पिण्डुम में सभा होने वाली थी. 'जन जागरण' के गुण्डे व पुलिस बल मीटिंग के नाम पर गांव में हमला बोलकर घर जलाकर, लोगों की हत्या कर आतंक मचाने वाले थे. जनता की रक्षा करने हेतु पीएलजीए के सैनिकों ने गुण्डों और पुलिस पर जवाबी हमला करने की योजना बनाई. पर बम बिछाते समय दुर्घटनावश विस्फोट होने से पीएलजीए का जांबाज सिपाही कॉमरेड विज्जाल को शहादत प्राप्त हुई. पश्चिम बस्तर डिवीजन के भैरमगढ़ इलाके की उत्पीड़ित आदिवासी जनता अपना प्यारा एवं लड़ाकू नेता खोया.

25 वर्षीय कॉमरेड विज्जाल का जन्म दन्तेवाड़ा तहसील के गीदम विकासखण्ड के गांव जावंगनार में हुआ था. जमीन की कमी के चलते उनका परिवार कई साल पहले भैरमगढ़ तहसील के केशकुत्तुल गांव में आ बसा. घर पर कॉ. विज्जाल का नाम माड़वी बोमड़ा था. वह माता-पिता का सबसे बड़ा लड़का था. गरीब किसान परिवार में जन्मे कॉ. विज्जाल को माता-पिता ने लाड़-प्यार के साथ पाला-पोसा था. उनकी मां आंगनवाड़ी में सहायिका का काम करती थी. कॉ. विज्जाल शादीशुदा थे - वह अपने पीछे बीवी और दो बच्चों को छोड़ गए. क्रान्ति के लक्ष्य से उन्होंने बीवी-बच्चों को छोड़कर जनयुद्ध में कूद पड़ा था.

बेहद गरीबी से जूझता हुआ पलने-बढ़ने वाला कॉ. विज्जाल बचपन से ही हर काम में मां-बाप का हाथ बंटाता था. बैल चराते, साथी बच्चों के साथ खेलते-कूदते ही उसने आदिवासियों की परम्परागत युद्धकला में दक्षता हासिल की थी. तीरंदाजी में उसे अत्यधिक दिलचस्पी थी. तब तक आसपास के गांवों में चल रहे क्रान्तिकारी जन संघर्षों का असर भी उस पर पड़ने लगा था. सरकारी वन विभाग, पटवारी, सेठ-साहुकारों के जुल्मों और अत्याचारों को देखकर उसका खून खौलने लगता था.

वह हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा रखता था. इस बीच उसके गांव में भी क्रान्तिकारी गतिविधियों का फैलाव हो चुका था. 2000 में वह डीएकेएमएस में शामिल हो गया. संगठन में सक्रिय रूप से काम करते हुए उसने आसपास के गांवों में भी संगठन का निर्माण करने में मदद की. चुनाव बहिष्कार अभियानों तथा तेन्दुपत्ता व बांस मजदूरों के संघर्षों में उसने उत्साह के साथ भाग लिया.

शहीद सप्ताह के मौके पर गांव–गांव में आयोजित होने वाले सभा–सम्मेलनों व रैलियों में कॉ. विज्ञाल ने सक्रिय रूप से भाग लिया. भैरमगढ़ जैसे शहरों में उसने दुश्मन की आंखों में मिट्टी झोंककर बने–बनाए शहीद स्मारक खड़ा किया था. पीएलजीए के स्थापना सप्ताह के मौके पर दुश्मन के खिलाफ हमलों, बन्द आदि के आयोजनों में सक्रियता से भाग लेता था. उस इलाके में होने वाली हरेक क्रान्तिकारी गतिविधि में उसकी भूमिका हुआ करती थी. फरवरी 2003 में, जबकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार बस्तर के क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने के लिए सीआरपीएफ को तैनात करने की तैयारियां कर रही थी, कॉ. विज्ञाल ने मिलिशिया के अन्य युवकों के साथ मिलकर दुश्मन से रायफल छीन ली. गोटपाड में आयोजित करसड़ में गश्त पर आए पुलिस दल के एक सदस्य पर कुल्हाड़ी से वार कर कॉ. विज्ञाल ने बड़ी शूरता के साथ उसकी रायफल छीन ली. बाद में उसने वह पार्टी को सौम्प दी.

दुश्मन से रायफल छीनने के बाद कॉ. विज्ञाल पर दुश्मन की नजर बढ़ गई. उसके घर पर पुलिस ने कई बार छापेमारी की. कॉ. विज्ञाल ने अपना पूरा जीवन क्रान्ति के लिए समर्पित करने का पैसला लेकर पीएलजीए दस्ते में शामिल हो गया. जुलाई 2003 में वह मिरतुल एलओएस (स्थानीय सांगठनिक दस्ता) का सदस्य बना था. मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद के मार्गदर्शन में लड़कर सामन्तवाद, दलाल पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का सफाया करने से ही जनता को असली अजादी मिल सकती है – इसी समझ के साथ कॉ. विज्ञाल लाल सैनिक बना और फौजी पोशाक पहनकर गांव–गांव में जनता को लामबन्द करना शुरू किया. दस्ते में रहकर उसने पढ़ना–लिखना सीखना भी शुरू किया और धीरे–धीरे पार्टी की पत्रिकाओं को पढ़कर समझने लगा. दस्ते में अनुशासन का पालन करने में तथा साथियों व जनता से घुलमिल जाने में कॉ. विज्ञाल एक आदर्शवान लाल सैनिक था. कॉ. विज्ञाल के लड़ाकूपन और अनुशासनप्रियता को देखकर पार्टी ने जून 2004 में उसका एलजीस (जिसे उस समय एसजीएस कहा जाता था) में तबादला किया गया. 21 सितम्बर 2004 – भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में सुनहरा दिन. भारत की दो बड़ी माओवादी पार्टियों – एमसीसीआइ और भाकपा (मा–ले) [पीपुल्सवार] के विलय और भाकपा (माओवादी) के गठन की खबर सुनकर कॉ. विज्ञाल की खुशी का ठिकाना न रहा. सभी साथियों और जनता के साथ उसने भी उसे जश्न के तौर पर मनाया.

भैरमगढ़ एलजीएस में रहकर उसने दुश्मन पर किए गए कई हमलों में भाग लिया. उसमें उल्लेखनीय हैं – संयुक्त गश्त अभियान के नाम पर सीआरपीएफ एवं सीएएफ बलों ने फरवरी 2005 में जब गंगलूर इलाके में आतंकपूर्ण कार्रवाइयां शुरू कीं तो उन पर पीएलजीए ने हमला करके सीआरपीएफ के एक जवान को घायल कर दिया. इसमें कॉ. विज्ञाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

23 मार्च 2005 को दन्तेवाड़ा जिला मुख्यालय में राज्यपाल के.एम. सेठ का दौरा था. उसके आगमन के मौके पर हेलिपैड में तैनात पुलिस बलों पर कॉ. विज्ञाल के नेतृत्व में एक मिलिशिया दस्ता ने एक अत्यंत साहसिक हमला कर दिया. दुश्मन की कमजोरी का सही आंकलन करके उन्होंने अपने पास मौजूद चाकुओं से ही एक पुलिस जवान को वहीं मार डाला और एक अन्य को घायल कर दिया. उनसे 2 एसएलआर रायफलें छीनकर वे सकुशल लौट गए. जिला मुख्यालय में अत्याधुनिक हथियारों से लैस सैकड़ों पुलिस बलों की तैनाती के बावजूद किए गए इस शूरतापूर्ण हमले ने दुश्मन के दिलों में हड़कंप मचाई. सूझबूझ, पहलकदमी और साहस के साथ कॉ. विज्ञाल ने इस हमले को अंजाम देकर तमाम जनता व पीएलजीए सैनिकों के सामने एक अद्वितीय मिसाल पेश की.

23 मई 2005 को राष्ट्रीय राजमार्ग–16 पर बीजापुर–भैरमगढ़ के बीच सीआरपीएफ के काफिले पर किए गए जबर्दस्त एम्बुश में भी कॉ. विज्ञाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा. इस हमले में पांच पुलिस वाले मारे गए और 7 अन्य घायल हो गए. मुख्य सड़क पर किए गए इस हमले से शोषक शासक वर्गों की नींदें उड़ गईं. दुश्मन के 'ऑपरेशन एरिया डॉमिनेशन' टांय–टांय फिस्स हो गई.

अपने तमाम दमन अभियानों के लगातार पिट जाने से बौखलाए शासक वर्गों ने महेन्द्र कर्मा को आगे कर क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ एक नीचतापूर्ण हमला – 'जन जागरण' अभियान शुरू किया. जनता की जान–माल की रक्षा करने तथा इस दमन अभियान को हराकर आन्दोलन को आगे बढ़ाने हेतु पीएलजीए ने 'जन जागरण' गुण्डावाहिनी और पुलिस बलों पर कई प्रतिरोधी हमले किए. कोतरापाल, केशकुत्तुल गांवों में हुए हमलों में कॉ. विज्ञाल का योगदान रहा. 11 जुलाई को इसी सिलसिले में पिंडुम में हमले की तैयारियों के दौरान दुर्घटनावश बम फटने से उनकी दुखद मौत हुई. कॉ. विज्ञाल की मौत से पीएलजीए ने एक साहसी व जांबाज योद्धा खोया. 'दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी' कॉ. विज्ञाल को विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि पेश करती है तथा उनके शोकसंतप्त परिवार व भैरमगढ़ क्षेत्र की जनता के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है. हम दण्डकारण्य की लड़ाकू जनता का आह्वान करते हैं कि जिस मकसद की खातिर कॉ. विज्ञाल ने अपनी जान पर खेला था, उसे पूरा करने हजारों–लाखों की संख्या में जनयुद्ध में शामिल होवें.

अदम्य साहस का पर्याय
कॉमरेड पाकलू (उरसा छन्नू)

'ऑपरेशन ग्रीन हन्ट' के नाम से दुश्मन द्वारा जारी जुल्मी दमन अभियान का मुकाबला करते समय कॉमरेड पाकलू ने वीरगति को प्राप्त किया. नगा पुलिस बलों और गुण्डावाहिनी द्वारा जारी सफेद आतंक पर रोक लगाने के लिए पीएलजीए के वीर सैनिकों ने 2 सितम्बर को उन पर घात लगाकर हमला किया. इसमें कॉमरेड पाकलू घायल होकर आखिरी सांस तक लड़कर शहीद हुआ.

25 वर्षीय कॉमरेड पाकलू का जन्म भैरमगढ़ तहसील के पामरा गांव में हुआ था. गरीब आदिवासी परिवार में जन्मे कॉमरेड पाकलू का नाम उरसा छन्नू था. वह बचपन से ही क्रान्तिकारी आन्दोलन से प्रभावित था. गांव में मवेशी चराते समय वह अपने दोस्तों के साथ क्रान्ति के गीत ही गुनगुनाया करते थे. तीसरी कक्षा तक पढ़ चुके कॉमरेड पाकलू पहले बाल संगठन का सदस्य बना था.

1996 में वह डीएकेएमएस सदस्य बन गया. अपने गांव में संगठन अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मिरतुल इलाके में किए गए कई संघर्षों में उन्होंने जनता का नेतृत्व किया. तेन्दुपत्ता मजदूरी बढ़ाने हेतु किए गए जन संघर्षों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा. गांवों में दुष्ट मुखियाओं के प्रभुत्व को समाप्त कर जनता को जन संगठनों के नेतृत्व में संगठित करने में कॉ. पाकलू ने अपना योगदान दिया था. जनता पर मुखियाओं द्वारा

जारी सामाजिक व आर्थिक शोषण को जड़ से खत्म करने में उनका योगदान रहा. सामन्ती व दलाल पूंजीपतियों का दलाल और कांग्रेसी नेता महेन्द्र कर्मा की अगुवाई में 1997 में चलाए गए दूसरे 'जन जागरण' अभियान के खिलाफ किए गए प्रतिरोधी संघर्ष में कॉमरेड पाकलू ने दृढ़तापूर्वक भाग लिया था. 'जन जागरण' गुण्डों को मार भगाने में वह आगे रहे थे. दमन के बीचोबीच ही वह कई संघर्षों में तपकर फौलाद बना था. अपनी चेतना को बढ़ा लेते हुए वह जनवरी 2002 में पीएलजीए दस्ते में भर्ती हो गया. 2002 से मद्देड दस्ते में सदस्य के रूप में काम करते हुए उस इलाके में किए गए कई संघर्षों में भाग लिया. दस्ते में अनुशासन का पालन करने में वह एक आदर्शपूर्ण सैनिक था. उन्होंने अपनी राजनीतिक व फौजी क्षमताओं को विकसित करने का लगातार प्रयास किया. फौजी मामलों में उनकी सक्रियता को देखकर पार्टी ने उन्हें 2002 में दक्षिण सब-जोनल ब्यूरो के फौजी प्रशिक्षक टोली में सदस्य बनाया. दक्षिण ब्यूरो के दक्षिण बस्तर और पश्चिम बस्तर डिवीजनों में आयोजित कई फौजी प्रशिक्षण कैम्पों में उन्होंने प्रशिक्षक रूप में जन मिलिशिया के बीसियों नौजवानों को प्रशिक्षित किया था. कई आदिवासी युवाओं को पीएलजीए के लाल सैनिक के रूप में विकसित करने में उनका योगदान रहा. पार्टी द्वारा अपनाए गए कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियानों को सफल बनाने हेतु पीएलजीए के आधार व माध्यमिक बलों को प्रशिक्षित करने में उनका योगदान भुलाए भूल नहीं सकते. सदा हंसमुख, सभी के साथ सरल बरताव करने वाले कॉमरेड पाकलू प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को बढ़िया ढंग से समझाया करता था. साथी कॉमरेडों और जनता के साथ नम्रतापूर्वक बरताव करने वाले कॉमरेड पाकलू हम सभी के लिए एक आदर्श है.

कॉमरेड पाकलू ने अपने गुरिल्ला जीवन में कई हमलों में भाग लिया. 2003 फरवरी में मुरदोंडा के पास बस में सफर कर रहे पुलिस वालों पर हमला कर तीन पुलिस वालों का सफाया कर, उनके हथियार छीन लेने में उनका योगदान रहा. 2004 और 2005 की गर्मियों में पार्टी द्वारा चलाए गए कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियानों में उन्होंने उत्साहपूर्वक कई कार्रवाइयों में शिरकत की. 21 मई 2005 को करेंमरका के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुश्मन पर किए गए जबर्दस्त हमले में कॉमरेड पाकलू ने शूरतापूर्वक भाग लिया. इस घटना में सीआरपीएफ के छह जवान मारे गए तथा सात घायल हुए थे.

फिलहाल पश्चिम बस्तर डिवीजन में जारी दमनकारी 'जन जागरण' अभियान का मुकाबला करने में कॉमरेड पाकलू आगे रहा. जनता पर जारी हत्या, बलात्कार, लूट और आगजनी के सिलसिले को रोकने हेतु, जनता की रक्षा की खातिर की गई कई कार्रवाइयों में उन्होंने भाग लिया. कार्पेट सिक्यूरिटी के तहत लगाए गए पुलिस कैम्पों पर हमले करने तथा 'जन जागरण' के कई गुण्डा नेताओं का सफाया करने में उनका योगदान रहा. 28 अगस्त से 3 सितम्बर के बीच रमन सिंह की फासीवादी सरकार ने सीआरपीएफ और नगा फोर्स के सैकड़ों बलों को उतारकर 'ऑपरेशन ग्रीन हन्ट' के नाम से 150 वर्ग किलोमीटर के दायरे में एक व्यापक उन्मूलन अभियान चलाया. इस दौरान 2 सितम्बर को तिम्मेम गांव के पास पीएलजीए के दस्ते ने नगा पुलिस बलों पर घात लगाकर हमला किया. इस हमले में कॉमरेड पाकलू बहादुरी के साथ लड़ते हुए दुश्मन की गोलियों से बुरी तरह घायल हो गया. घायल कॉमरेड पर पुलिस ने गोलियों की बौछार कर उनकी हत्या की. बाद में 'सलवा जुडूम' के गुण्डों ने मृत पाकलू के सिर तथा शरीर के अन्य अंगों को काटकर बर्बरता का नंगा प्रदर्शन किया. इसलिए पुलिस ने मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने का बयान दिया पर तस्वीर नहीं पेश की ताकि उसकी पाशविकता का पता न चल सके. कॉमरेड पाकलू की इस तरह निर्मम हत्या करने के पीछे उनकी मंशा यही है कि जनता में आतंक फैलाकर उसे क्रान्तिकारी आन्दोलन से अलग कर दिया जाए. लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी हत्याओं और आतंक से जनता के दिल में और ज्यादा नफरत व गुस्सा भड़क रहे हैं जिसमें शोषक-लुटेरों को जलकर राख होने से कोई नहीं बचा सकता. इतिहास के पहियों को कोई भी पीछे की तरफ मोड़ नहीं सकते.

झूठी मुठभेड़ में शहीद हुए लोक नायक कॉमरेड एमला लच्छू

'जन जागरण' के नाम पर जनता पर जारी बर्बरतापूर्ण दमन अभियान में कॉमरेड एमला लच्छू एक और शहीद बन गए. 6 से 14 अक्टूबर तक 'ऑपरेशन ग्रीन हन्ट' के नाम पर जारी दमनात्मक कार्रवाई के दौरान एक मुखबिर की मदद से 8 अक्टूबर को चेरपाल रेंज डीएकेएमएस अध्यक्ष कॉमरेड एमला लच्छू को पुलिस ने मोसला गांव में पकड़ लिया. क्रूर यातनाएं देकर बाद में गोली मारकर उसकी हत्या की. पुलिस ने बयान जारी किया कि 'मुठभेड़' में 'एरिया कमाण्डर' एमला लच्छू मारा गया.

25 वर्षीय एमला लच्छू का जन्म बीजापुर के निकट मोसला गांव में हुआ था. गरीब किसान परिवार में पले-बढ़े कॉमरेड लच्छू अपने पीछे बीवी और एक बेटा छोड़ गया. वह 2000 से गांव के किसान संगठन - डीएकेएमएस में मुख्य भूमिका निभाते आ रहा था. उसे 2003 से चेरपाल रेंज कमेटी में सदस्य की जिम्मेदारी दी गई थी. अगस्त 2004 में आयोजित डीएकेएमएस रेंज अधिवेशन में उसे रेंज अध्यक्ष चुन लिया गया. नैमेड, कड्डेर, गदमल, कैका, मोसला, पोरमूर, आदि गांवों की जनता को लच्छू ने कई राजनीतिक व आर्थिक संघर्षों में गोलबन्द किया. राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्चे बांटने, पोस्टर लगाने आदि कार्यक्रमों में उनका योगदान था. शहीद सप्ताह, पीएलजीए सप्ताह, 8 मार्च, पार्टी का जन्म दिन आदि महत्वपूर्ण दिनों के मौके पर जनता में क्रान्ति का संदेश ले जाने के काम में वह भाग लेता था. अपने इलाके में 'जन जागरण' के नाम से शुरू हुए जुल्मी अभियान के दौरान भी लच्छू ने जनता और जन संगठनों को दुष्ट मुखियाओं के खिलाफ दृढ़तापूर्वक खड़ा किया. अपने रेंज की जनता को दुश्मन के आगे न झुकने के लिए उत्साहित किया. भयानक दमन के बीचोबीच भी गांवों में घूमकर 'सलवा जुडूम' से घबराने वाले लोगों का हौसला बढ़ाता रहा. दण्डकारण्य को मुक्तांचल में बदलने के लक्ष्य से दृढ़ता से लड़ते हुए एमला लच्छू शहीद हुआ. आइए, कॉमरेड लच्छू के अधूरे सपनों को पूरा करने तथा जुल्मी 'सलवा जुडूम' को दफनाने की कसम खाएं.

क्रान्तिकारी आदिवासी महिला संगठन नेत्रियां कॉमरेड मोड़ियम सुक्की और कुरसम लक्के

जून महीने से जारी 'जन जागरण' अभियन हत्या, आगजनी, बलात्कार, लूट और आतंक का पर्याय बन चुका है. अब तक इस अभियान में दर्जनों महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और कई महिलाओं की हत्या भी की गई. उन्हीं में से हैं कॉमरेड मोड़ियम सुक्की और कुरसम लक्के. 6 से 13 अक्टूबर तक चली 'ऑपरेशन ग्रीन हन्ट' के दौरान गंगलूर इलाके के गांवों में नगा पुलिस और गुण्डावाहिनी ने भयानक आतंक मचाया. 7 अक्टूबर को उन्होंने कोरमा गांव पर हमला बोल दिया. वहां अपनी सुरक्षा के लिए संतरी में तैनात ये दोनों महिलाएं जब उन्हें देखकर भागने लगीं तो गुण्डों व पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर उन्हें पकड़

लिया. बाद में इन दोनों के साथ पाशविक ढंग से सामूहिक बलात्कार कर बाद में दोनों की हत्या की. लाशों को वहीं फेंककर चले गए.

कॉमरेड मोड़ियम सुक्की केएएमएस के जनताना सरकार दायरे की अध्यक्षा थी और कॉमरेड कुरसम लक्के कमेटी सदस्या थी. 20–22 साल उम्र की वे दोनों पिछले 5 सालों से केएएमएस में सक्रिय रूप से काम कर रही थीं. बचपन में ये दोनों बाल संगठन में थीं. ये दोनों कॉमरेडों के परिवार भी क्रान्तिकारी आन्दोलन से जुड़े हुए हैं. इनके माता–पिता, भाई–बहन अन्य जन संगठनों में सदस्य या नेता के रूप में काम कर रहे हैं. वे पहले अपने गांवों में केएएमएस की जिम्मेदारी बखूबी से निभाने के बाद जनताना सरकार के दायरे की कमेटी में चुन ली गईं.

इन दोनों युवा कॉमरेडों ने अपने आसपास के गांवों में महिलाओं को कई संघर्षों में गोलबन्द किया. मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक रिवाज के तहत महिलाओं को मिंजाई के समय खलिहान में कदम न रखने देने की प्रथा को इन्होंने बदल डाला. सारी महिलाएं अब खलिहान में कदम रखती हैं. उसी प्रकार घर की जिस खोली में धान रखा जाता है, उसमें भी महिलाओं के प्रवेश पर पाबन्दी थी. इसे भी एक अभियान के रूप में संघर्ष के जरिए बदल दिया गया. इसमें कॉमरेड्स सुक्की और लक्के का योगदान रहा. गांवों में संगठन का विरोध करने वाले मुखियाओं से आए विरोध तथा उनकी कई किस्म की टिप्पणियों की परवाह न करते हुए इन्होंने संगठन का कामकाज जारी रखा. पुसनार और कोरमा गांवों में जनताना सरकार द्वारा एक बड़ा तालाब का निर्माण किया गया था. इसके निर्माण के दौरान इन दोनों कॉमरेडों ने महिलाओं को संगठित कर उनका उत्साह बढ़ाकर काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने में योगदान किया. मिलिशिया द्वारा इस इलाके में दुश्मन के खिलाफ की गई कई कार्रवाइयों में उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका रही. आइए, अपनी नौजवानी में ही दुश्मन की क्रूरता की बलि चढ़ चुकी इन दोनों बहादुरिनों को सिर झुकाकर श्रद्धांजलि पेश करेंगे. उनकी कुरबानी को ऊंचा उठाए रखेंगे.

लोगों का प्यारा नेता
कॉमरेड कोवाल

दन्तेवाड़ा जिले के बीजापुर विकासखण्ड के आवुनार गांव में कॉमरेड कोवाल का जन्म हुआ था. लेकिन जीवन संघर्ष ने उसे मनकेली गांव ले आया, जहां वह बसकर बीवी–बच्चों के साथ गुजर–बसर करने लगा. 40 वर्षीय कॉमरेड कोवाल ने अपने गांव की जनताना सरकार का अध्यक्ष और ग्राम पार्टी कमेटी का सचिव बनकर जनता के दिल में एक प्यारा नेता की छवि बनाई. 1988–89 के दरम्यान डीएकेएमएस सदस्य बनने वाला कॉमरेड कोवाल पिछले 17 सालों से क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ जुड़े रहे. जनता की मुक्ति के लिए लड़कर अपनी जान न्यौछावर करने वाले कॉमरेड कोवाल बीजापुर इलाके के शोषित आदिवासियों के दिल में सदा अमर रहेंगे.

1990 में महेन्द्र कर्मा की अगुवाई में चलाए गए पहले 'जन जागरण' अभियान के दौरान भी कॉमरेड कोवाल मजबूती से खड़े थे. उसका मुंहतोड़ जवाब देकर जनता को आन्दोलन में संगठित करने में कॉमरेड कोवाल की यादगार भूमिका रही. बीजापुर, पदेड़ा और चेरपाल में आन्दोलन के खिलाफ खड़े हुए दुष्ट मुखियाओं को सबक सिखाने में कॉमरेड कोवाल का योगदान था. मनकेली, ईसुलनार आदि गांवों में बांस कूपों में मजदूरी बढ़ाने के लिए किए गए संघर्ष में कॉमरेड कोवाल ने जनता को गोलबन्द किया था. वन विभाग के नाकेदार, दफेदार, रेंजर, जैसे अधिकारी लोगों पर कई प्रकार के जुल्म करते थे. जंगल में मवेशी चराने, घर बनाने या जलाऊ लकड़ी लाने पर रिश्वत वसूलते थे और झूठे केस लगाकर प्रताड़ित करते थे. कॉमरेड कोवाल ने वन विभाग वालों के शोषण और लूट के खिलाफ जनता को गोलबन्द कर संघर्ष किया. 'सामाजिक वनीकरण' के नाम पर खेत जमीनों पर पौधे लगवाने की साजिश जब विश्व बैंक के आदेश पर सरकार ने रची तो कॉमरेड कोवाल ने जनता को इकट्ठा कर उसे नाकाम किया. सरकार ने 'फूट डालो – राज करो' की नीति के तहत गांवों में 'वन सुरक्षा समितियों' का गठन कर जनता में आपसी झगड़ा पैदा करने की कोशिश की तो कॉमरेड कोवाल ने अपने इलाके में इस योजना को विफल बनाया.

1999 में कॉमरेड कोवाल को डीएकेएमएस के बीजापुर रेंज कमेटी अध्यक्ष चुन लिया गया. इस नाते रेंज भर में चलाए गए जन संघर्षों में उन्होंने भाग लिया और जनता का नेतृत्व किया. तेन्दुपत्ता मजदूरी बढ़ाने के लिए वन विभाग और ठेकेदारों के खिलाफ किए गए जन संघर्षों का उन्होंने नेतृत्व किया था. चौथीं कक्षा तक पढ़ चुके कॉमरेड कोवाल पार्टी की पत्रिका 'प्रभात' नियमित रूप से पढ़ा करते थे. मन जो भी शंकाएं होती हैं तो जिम्मेवार कॉमरेडों से पूछकर सही जानकारी हासिल करते थे. इस तरह अपनी राजनीतिक समझदारी बढ़ा लेते थे.

रेंज कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बीजापुर के आसपास के गांवों – तुमनार, सागुवाया, कन्नय्यागूडेम, पारालपारा, बासागूडेम, चिलनार, संतोषपुर, आदि गांवों में डीएकेएमएस का निर्माण कर गांव के दुष्ट मुखियाओं के खिलाफ संघर्ष में जनता को उतारा था. बीजापुर पुलिस जिला मुख्यालय से महज एक किलोमीटर दूर पर, पुलिस की निरंतर गश्त अभियानों के बीच ही कॉमरेड कोवाल ने संगठन का काम जारी रखा. उन्होंने छात्र, नौजवानों को भी पार्टी का साहित्य पहुंचाकर उन्हें क्रान्तिकारी राजनीति की ओर उन्होंने आकर्षित किया. पीएलजीए स्थापना दिवस, शहीद दिवस, 8 मार्च आदि कार्यक्रमों के अवसर पर बीजापुर कस्बे में पुलिस की पहरेदारी के बीच ही पोस्टर–पर्चे बंटते थे. दीवार–लेखन की जाती थी. इसके पीछे कॉमरेड कोवाल की भूमिका महत्वपूर्ण थी. एक बार तो पुलिस ने पोस्टर लगाते समय उन पर गोलियां भी चलाई थीं, पर वह बच गए.

दो साल पहले कॉमरेड कोवाल को मनकेली गांव की जनताना सरकार का अध्यक्ष चुन लिया गया. इस नाते उन्होंने अपने दायरे के गांवों में जनता को जनयुद्ध के लिए बड़े पैमाने पर तैयार करते हुए जनता की नई राजसत्ता को मजबूती से संगठित करने का प्रयास किया. वह जनता को बताया करते थे कि लुटेरी राजसत्ता को हथियारबन्द ताकत के जरिए जड़ से खत्म करने से ही जनता की यह नई राजसत्ता बच सकती है और बढ़ सकती है. जनता को राजनीतिक रूप से संगठित करते हुए ही उन्होंने अनेक विकास कार्यक्रमों को संचालित किया. आज दण्डकारण्य में तेजी से विकसित हो रही जनता की वैकल्पिक अर्थव्यवस्था, जिसका मुख्य आधार है सहकारिता और आत्मनिर्भरता, के पीछे कॉमरेड कोवाल जैसे कॉमरेडों के महत्वपूर्ण योगदान को भुलाए भूल नहीं सकते. कॉमरेड कोवाल ने सर्वहारा दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रलोभनों से दूर रहते हुए वर्ग दुश्मनों के प्रति समझौताहीन संघर्ष किया.

वर्तमान 'जन जागरण' अभियान के जवाब में पश्चिम बस्तर डिवीजन में पार्टी ने एक बड़ा 'जन प्रतिरोध अभियान' छेड़ रखा है. कॉमरेड कोवाल ने अपने आसपास के गांवों में जनता का हौसला बढ़ाते हुए उसे 'सलवा जुडूम' के विरोध में कतारबद्ध किया. 3 सितम्बर को पुंजेर के पास पीएलजीए के द्वारा किए गए जबर्दस्त एम्बुश का शानदार दास्तान उन्होंने गांव–गांव में सुनाया. उन्हें पक्का विश्वास था कि अन्तिम

(शेष पेज 25 पर ....)

श्रद्धांजली

पुलिस की गोलीबारी में शहीद हुए
कॉमरेड नंदाल को लाल सलाम !

दक्षिण बस्तर डिवीजन के पीएलजीए की एक एक्शन टीम एक दुश्मन का सफाया करने के इरादे से 10 अप्रैल 2005 को दोरनापाल कस्बे में गई हुई थी. इसकी खबर किसी खबरिए के जरिए पुलिस को मिली. तो तुरन्त ही पुलिस बलों ने उस टीम को, जिसमें दो ही सदस्य थे, चारों तरफ से घेर लिया. मोटार सायकिल पर दो पुलिस वाले आकर स्वचालित रायफलों से हमारे कॉमरेडों पर अंधाधुंध गोलीबारी की. जब दोनों कॉमरेड इससे बचने के लिए दौड़ रहे थे, तब कॉमरेड नंदाल को गोली लगने से वहीं गिर पड़ा. पुलिस उसे नजदीक से गोली मारकर क्रूरतापूर्वक हत्या की. इस तरह पीएलजीए ने एक जांबांज वीर सैनिक खोया.

25 वर्षीय कॉमरेड नंदाल, जिसका नाम घर पर सोड़ी हिड़मा था, का जन्म दन्तेवाड़ा जिला, किष्टारम एरिया, सिंगामडुगु गांव में हुआ था. उसके पिता गांव में डीएकेएमएस का नेता थे. शुरू में जब उस गांव में छापामार दस्ते जाते थे, तब नंदाल छापामारों के गोद में खेला करता था. इस प्रकार वह क्रान्तिकारी माहौल में ही पला–बढ़ा था. बचपन में बाल संगठन, जवानी में कदम रखते ही ग्राम सुरक्षा दल और उसके बाद पीएलजीए की एक्शन टीम का जांबाज योद्धा के रूप में उसका विकास ठीक ऐसा ही हुआ जैसा उस इलाके में क्रान्तिकारी आन्दोलन का हुआ. 2002 जून में वह पीएलजीए दस्ते में भर्ती हुआ था. कुछ दिनों तक उसे डीवीसी सदस्य के सुरक्षा गारद रखा गया था. उस समय उसने कई घात हमलों में शिरकत की. 2004 में उसे प्रशिक्षक टीम का सदस्य चुना गया. प्रशिक्षक के रूप में उसने जन मिलिशिया के कई सदस्यों को ट्रेनिंग दी. एक प्रशिक्षक के रूप में उसका काम काफी सराहनीय रहा.

अगस्त 2003 में कोंटा के नजदीक विधायक कोवासी लखमा के दौरे के दौरान पुलिस पर पीएलजीए सैनिकों ने हमला किया था. उसमें कॉमरेड नंदाल भी था. उस हमले में एक पुलिस जवान मारा गया. बाद में लोकसभा चुनावों के समय पुलिस की एक गाड़ी उड़ाने में भी कॉमरेड नंदाल की भागीदारी रही, जिसमें 5 पुलिस जवान मारे गए थे. 2003 में पामेड थानेदार को घेरकर उसकी पिस्तौल जब्त कर उसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई में भी कॉमरेड नंदाल शामिल था. पार्टी और सैन्य कमान जो भी आदेश देतीं उसका पालन करने में हमेशा तत्परता दिखाया करता था. कॉमरेड नंदाल की याद में उनके गांव में लोगों ने एक स्मारक का निर्माण कर बीते 28 जुलाई को उसे श्रद्धांजलि पेश की. हजारों लोगों की उपस्थिति में स्मारक का अनावरण किया गया और एक विशाल सभा आयोजित की गई. उस सभा को उनके पिता अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए सम्बोधित किया. उन्होंने ऐलान किया कि जितने भी नौजवान जनयुद्ध में शामिल हैं वे सब मेरे बेटे हैं. उन्होंने लोगों का आह्वान किया वर्तमान लुटेरी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष तेज कर नंदाल समेत हजारों जनवीरों के सपनों को साकार बनाएं.

बीमारी के कारण शहीद हुए
कॉमरेड अर्जुन को लाल सलाम !

कॉमरेड अर्जुन का जन्म उत्तर बस्तर डिवीजन के रावघाट इलाके के काकबरस गांव के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था. गांव में स्थित पाठशाला में उसने पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई की. गरीबी के चलते आगे की पढ़ाई वह कर नहीं सका. 1990 के दशक से इस इलाके में तेज हो रहे क्रान्तिकारी गतिविधियों से वह प्रभावित था. 2002 में वह अपने गांव में डीएकेएमएस सदस्य बना. बाद में 2004 में वह पीएलजीए सैनिक बनकर दस्ते में भर्ती हुआ. कॉमरेड अर्जुन एक मिलनसार व्यक्ति था. पार्टी नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देती तो वह हंसी–खुशी से पूरा करता था. अप्रैल 2005 में वह गंभीर बीमारी का शिकार हुआ था. उसे बचाने के लिए दस्ता के कॉमरेडों ने पूरी कोशिश की, पर नाकाम रही. अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया. इस तरह वह काकबरस गांव से जनयुद्ध का पहला शहीद बन गया. आसपास के गांवों के सभी लोगों ने मिलकर कॉमरेड अर्जुन की याद में उसके गृहग्राम काकबरस में एक स्मारक का निर्माण किया. इस साल शहीद सप्ताह के दौरान 30 जुलाई को उसका अनावरण किया गया. उस मौके पर आयोजित सभा में हजारों लोगों ने भाग लेकर उसे श्रद्धांजलि पेश की.

जन मिलिशिया का लाल सैनिक
कॉमरेड कारू को लाल सलाम !

गड़चिरोली जिले के एटापल्ली तहसील कसनसूर इलाके के गांव गड्डेर का निवासी था कॉमरेड कारू. वह एक गरीब आदिवासी परिवार की आखिरी संतान था. 1995 से वह क्रान्तिकारी आन्दोलन से जुड़ गया. पहले बाल संगठन का सदस्य रहा और बाद में डीएकेएमएस का सदस्य बन गया. पार्टी की गतिविधियों में उसकी सक्रियता को देखते हुए पार्टी ने उसे ग्राम सुरक्षा दस्ते का डिप्यूटी कमाण्डर बनाया और बाद में 2003 में वह उसका कमाण्डर बन गया. एरिया में पोस्टर, बैनर लगाने और पर्चे बांटने आदि प्रचार कार्यक्रमों के साथ–साथ दुश्मन के खिलाफ हमले की कार्रवाइयों में भी वह उत्साह के साथ भाग लिया करता था. 2005 मई में उस इलाके में गठित रेगुलर जन मिलिशिया दस्ते में उसे सदस्य चुन लिया गया. बाद में पार्टी के द्वारा आयोजित सैन्य प्रशिक्षण कैम्प में कॉमरेड कारू ने उत्साह के साथ भाग लिया. 3 मई 2005 को वह जब एक बन्दूक बनवाने के सिलसिले में सायकिल पर जा रहा था, तब रास्ते में दुर्घटनावश उसे सांप काटा. तुरन्त बाद उसकी मृत्यु हुई. बाद में गांव के सभी मिलिशिया सदस्यों ने एक शोकसभा आयोजित कर शहीद कॉमरेड कारू को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजली पेश की.

मलिंगेर शहीद कॉमरेड्स भीमाल और रोशन की लाशें *(रिपोर्ट पेज 26 में)*

दुष्ट मुखियाओं के हाथों मारे गए कॉमरेड शिवराम को लाल सलाम !

माड़ डिवीजन के इंद्रावती इलाके के भैरमगढ़ विकासखण्ड के बेलनार गांव में एक गरीब किसान परिवार में कॉमरेड शिवराम का जन्म हुआ था. 1998 से उसे क्रान्तिकारी आन्दोलन से प्रत्यक्ष परिचय हुआ. उस गांव में बाल संगठन का निर्माण शिवराम के साथ ही हुआ. गांव के सभी बच्चों को क्रान्तिकारी गीत सिखाने में कॉमरेड शिवराम काफी उत्साह दिखाता था. 2000 में वह अपने बड़े भाई के साथ डीएकेएमएस सदस्य बन गया. दोनों भाइयों ने बेलनार गांव में क्रान्तिकारी गतिविधियों का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जन संगठनों की अगुवाई में जन दुश्मन के घरों पर किए गए हमलों और सम्पत्ति जब्ती में उन दोनों भाइयों ने भाग लिया. बाद में कॉमरेड शिवराम का भाई पूर्णकालिक क्रान्तिकारी बनकर दस्ते में भर्ती हुआ और वह अपने गांव में ग्राम सुरक्षा दस्ते का नेतृत्व करने लगा. बाद में कुछ समस्याओं से उसका भाई घर वापस आया और कुछ महीनों बाद अपने निजी कारणों से उसने आत्महत्या कर ली. इस हादसे के बावजूद कॉमरेड शिवराम क्रान्तिकारी आन्दोलन में दृढ़ता से डटे रहे. अपने साथी सदस्यों को क्रान्तिकारी राजनीति समझाते हुए गांव में दिन-रात पहरेदारी किया करते थे. इस तरह सक्रियता से काम करने वाले शिवराम की हत्या की साजिश की गई. सत्तुवा गांव के बदनाम मुखियाओं ने 20 अक्टूबर 2004 को हाट बाजार से लौट रहे शिवराम पर घात लगाकर हमला बोल दिया. तीरों से उसकी हत्या की. इस खबर को सुनते ही आसपास के 8 गांवों से एक हजार लोग इकट्ठे हो गए. उन्होंने बेलनार में कॉमरेड शिवराम का अंतिम संस्कार पूरा कर बाद में उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार सत्तुवा गांव के मुखियाओं के घरों पर हमला कर उनकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली.

पीएलजीए का वीर कमाण्डर कॉमरेड इकबाल (सोड़ी कन्नाल) अमर रहे !

कॉमरेड इकबाल का जन्म दन्तेवाड़ा जिला, कोंटा तहसील, बोड्डीगुड़ा गांव में हुआ था. गरीब आदिवासी परिवार में जन्मे इस कॉमरेड का नाम सोड़ी कन्नाल था. 2000 में वह पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनकर सीएनएम में शामिल हुआ था. वह एक अच्छा कलाकार था. नाच-गीत में उसे काफी दिलचस्पी थी. सीएनएम में रहकर उसने कई गांवों में क्रान्तिकारी प्रचार किया. गलत रीति-रिवाजों के खिलाफ जनता की चेतना बढ़ाई. दो-तीन साल सीएनएम में काम करने के बाद उसे पामेड इलाके के एलजीएस में स्थानान्तरित किया गया. एलजीएस में रहते हुए उसने दुश्मन के खिलाफ की गई कई कार्रवाइयों में बहादुरी के साथ भाग लिया. टीसीओसी के दौरान किए गए कई घात हमलों में उसका योगदान रहा. उसकी सक्रियता और दृढ़ संकल्प और पार्टी के मकसद के प्रति उसके दृढ़ विश्वास को देखते हुए डिवीजनल कमेटी ने उसे हाल ही में कोंटा एलजीएस में कमाण्डर की जिम्मेदारी दी. लेकिन यह जिम्मेदारी उठाने से पहले ही उनकी दुखद मृत्यु हुई. कॉमरेड इकबाल दस्ते में अनुशासन का कड़ाई से पालन करता था. हर काम को उत्साह के साथ अंजाम देता था. उसे सभी जनता और साथी सदस्य बेहद पसन्द करते थे. आइए, इस बहादुर कमाण्डर के अधूरे सपनों को पूरा करने की शपथ लें. ✶

(..... पेज 23 का शेष)

जीत जनता की ही होकर रहेगी. 25 सितम्बर को मनकेली में 'सलवा जुडूम' सभा के बारे में महेन्द्र कर्मा और उसके गुर्गों ने बड़ा प्रचार किया था. हजारों लोगों के भाग लेने का दावा किया था. पर उस सभा में मनकेली गांव का एक भी व्यक्ति ने भाग नहीं लिया. ग्रामीणों ने यह ऐलान किया कि वे क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ खड़े हैं. इससे बौखलाए पुलिस व गुण्डावाहिनी ने दो मासूम लोगों की हत्या की. बाद में कॉमरेड कोवाल पर दबाव और बढ़ गया. उनकी हत्या की कई साजिशें रची गई. 3 अक्टूबर को जब वह अपने बेटे के साथ खेत जोत रहे थे, तो गुण्डों व पुलिस बलों ने चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया. तब वे निहत्थे थे. उन्हें क्रूर यातनाएं देकर बाद में गोली मार दी. पास के खेत में जुताई कर रहे एक और किसान मोड़ियम आयतू को भी पुलिस ने गोली मार दी. कॉमरेड कोवाल का 10 साल का बेटा राजू को पुलिस ने लापता कर दिया. कॉमरेड कोवाल की लाश पर गुण्डों ने कुल्हाड़ियों से कई वार किए. उसे वहीं फेंककर चले गए. बाद में पुलिस ने मोटी-मोटी सुर्खियों से मुठभेड़ में एरिया कमाण्डर कोवाल को मार गिराने की खबर छपवाई. लुटेरे शासक वर्गों ने खुशियां मनाईं. लेकिन इस हत्या से कॉमरेड कोवाल के द्वारा पिछले 17 सालों के दौरान उस इलाके में बोए गए क्रान्ति के बीजों की फसल को कोई भी प्रतिक्रियावादी ताकत ध्वस्त नहीं कर सकती. जनता कॉमरेड कोवाल की हत्या का बदला जरूर लेगी. उसके अधूरे सपने को जरूर साकार बनाएगी. ✶

भूल सुधार

'प्रभात' के पिछले अंक में डौला हमले में शहीद हुए कॉमरेड मंगतू की जीवनी में उनका नाम गलत छपा था. इसके लिए हमें खेद है. कॉमरेड मंगतू का असली नाम कोंडन्ना था. उनका गांव महबूबनगर जिला स्थित आविरिपल्लि था.

– सम्पादकमण्डल

मलिंगेर शहीदों को लाल सलाम

कॉमरेड भीमाल और कॉमरेड रोशन अमर रहें !

24 सितम्बर 2005 को दन्तेवाड़ा जिले के कटेकल्याण जनपद के ग्राम तर्रेमरका के पास छापामार दस्ते पर पुलिस द्वारा किए गए कातिलाना हमले में एलजीएस कमाण्डर कॉमरेड भीमाल तथा दस्ता सदस्य कॉमरेड रोशन शहीद हो गए. यह गांव मलिंगेर इलाके में स्थित है जहां पर क्रान्तिकारी आन्दोलन का विस्तार कुछ ही महीने पहले, दिसम्बर 2004 में हुआ था. इस इलाके की आदिवासी जनता बेहद गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी आदि समस्याओं से जूझ रही है. यहां पर सामन्ती मुखियाओं का बोलबाला है. वे जनता का कई प्रकार का शोषण–उत्पीड़न कर रहे हैं. विकास के नाम पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं से यहां के नेता व अफसर ही फायदा उठाते आ रहे हैं. ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में पिछले साल ज्यों ही भाकपा (माओवादी) के गुरिल्ला दस्तों ने कदम रखा तो जनता ने जोरदार स्वागत किया. दूसरी तरफ जनता के दुश्मनों ने पुलिस मुखबिरी करते हुए दस्ते का सफाया करने की साजिशें कीं. जब दस्ते ने पहले पहल इस इलाके में कदम रखा तो मुखियाओं की मुखबिरी से पुलिस ने फरवरी 2005 में दस्ते पर जब्बेली गांव के पास हमला किया था. हालांकि पीएलजीए सैनिकों ने उसका जोरदार मुकाबला कर दुश्मन के हमले को विफल किया था. तभी से दुश्मन ने दस्ते पर एक बड़ा हमला करने की योजना बनाई. किरन्दुल, कुआकोंडा और नकुलनार थानों के पुलिस बल हाथ धोकर दस्ते के पीछे पड़े थे. तर्रेमरका में पक्की सूचना पाकर एसटीएफ व विशेष पुलिस बलों ने घातक हमला करके इन दो कॉमरेडों – कॉमरेड्स भीमाल और रोशन की निर्मम हत्या की. मलिंगेर इलाके में क्रान्तिकारी आन्दोलन का विस्तार करने हेतु इन दोनों नौजवान योद्धाओं ने अपना खून बहाकर माओवादी लाल पताके की लालिमा बढ़ा दी. ये दोनों ही कॉमरेड कच्ची उम्र से ही क्रान्तिकारी आन्दोलन से जुड़े हुए थे, बल्कि यह कहना ठीक होगा कि दक्षिण बस्तर के क्रान्तिकारी आन्दोलन की गोद में ही ये दोनों पले–बढ़े थे. अपनी कुरबानी से इस इलाके की जनता के दिल में अमिट छाप छोड़ने वाले इन युवा क्रान्तिकारियों का संक्षिप्त जीवन परिचय पेश है.

कॉमरेड भीमाल

कॉमरेड भीमाल का जन्म दन्तेवाड़ा जिले के जेगुरगोंडा रेंज के जोन्नागूडेम गांव में हुआ था. घर पर उनका नाम माड़िवी देवा था. बचपन से वह क्रान्तिकारी आन्दोलन से प्रभावित था. शुरू में बाल संगठन का सदस्य बनकर काम करने वाला देवा जवान होते ही ग्राम सुरक्षा दस्ते का सदस्य बन गया. बाद में, वह 2001 में स्थानीय छापामार दस्ते में भर्ती हो गया. दस्ते में वह सबसे मिलजुलकर रहता था और कोई भी काम देने से उत्साह के साथ पूरा किया करता था. दस्ते में पढ़ना–लिखना सीखकर साथी कॉमरेडों तथा ग्रामीण जनता को दवाएं भी दिया करता था. शुरू से ही फौजी कार्रवाइयों में कॉमरेड भीमाल को ज्यादा दिलचस्पी थी. घर में रहते समय ही उसे पार्टी की उम्मीदवार सदस्यता मिली थी. दस्ते में भर्ती होने के बाद वह पार्टी सदस्य बन गया. 2005 में उसे एरिया कमेटी सदस्य के रूप में चुन लिया गया.

2003 सितम्बर में गीदम थाने पर तथा 2004 फरवरी में कोरापुट में पीएलजीए द्वारा किए गए शानदार हमलों में कॉमरेड भीमाल ने साहस के साथ भाग लिया. उन हमलों को सफल बनाने में उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. हाल ही में मलिंगेर एरिया में गठित एलजीएस में उसे कमाण्डर बनाया गया. दक्षिण बस्तर डिवीजनल कमाण्ड का भी वह सदस्य बना था. दुश्मन के तीखे दमन के बावजूद मलिंगेर इलाके में जनता के सहयोग से एक विशाल जन आन्दोलन का निर्माण करने के उम्दा लक्ष्य से ये सारे कॉमरेड गए हुए थे. दुश्मन के साथ हुई लड़ाई में कॉमरेड भीमाल ने वीरगति को प्राप्त किया. पीएलजीए ने एक होनहार और उभरता नौजवान कमाण्डर खोया. आइए, मलिंगेर क्षेत्र को अपने खून से लाल करने वाले इस बहादुर कमाण्डर की शहादत को ऊंचा उठाए रखें.

कॉमरेड रोशन

दक्षिण बस्तर के दन्तेवाड़ा तहसील के कुआकोंडा और कटेकल्याण विकासखण्डों में क्रान्तिकारी आन्दोलन का विस्तार करने के लक्ष्य से एसजेडसी ने जिन कॉमरेडों का चुनाव किया था, उनमें रोशन सबसे छोटी उम्र का नौजवान था. इस फैसले को उसने सहर्ष स्वीकार किया. कॉमरेड रोशन का जन्म कटेकल्याण क्षेत्र के उसी तुर्रेमरका गांव में हुआ था, जहां 24 सितम्बर को हुई मुठभेड़ में कॉमरेड भीमाल के साथ उन्होंने अपने खून बहाया. गरीब आदिवासी परिवार में जन्म लेने वाला कॉमरेड रोशन का नाम माड़वी बामन था. जब वह छोटा था तब उनके माता–पिता जमीन की किल्लत के चलते पेट पालने के लिए भैरमगढ़ क्षेत्र के जप्पूर गांव में जा बसे थे. बचपन से ही क्रान्तिकारी आन्दोलन से प्रभावित कॉमरेड रोशन सबसे पहले अपने गांव में बाल संगठन का सदस्य बना था. बाल संगठन में रहकर क्रान्तिकारी गीत सीखकर अपने साथी बच्चों को सिखाया करता था. गांव में आने वाले सीएनएम दस्तों के साथ मिलकर नाचना सीखा था. छापामार दस्ते में भर्ती होने के लिए वह बचपन से ही उत्सुक था. हालांकि उम्र कम है बताकर दस्ते के नेतृत्वकारी साथी उसके प्रस्ताव को टालते रहते थे. अपने गांव के डीएकेएमएस नेताओं के साथ मिलकर क्रान्तिकारी प्रचार की गतिविधियों में भाग लिया करता था. पीएलजीए की वर्षगांठ के अवसर पर प्रचार अभियान के साथ–साथ दुश्मन पर की गई फौजी कार्रवाइयों में भी कॉमरेड रोशन ने भाग लिया.

कॉमरेड रोशन को सांस्कृतिक गतिविधियों में काफी रुचि थी. सीएनएम द्वारा दिए गए कई प्रदर्शनों में उसने नाचा–गाया था. बाद में उसे डिवीजन सीएनएम टोली में लिया गया. उसने भैरमगढ़ के साथ–साथ मद्देड, नेशनल पार्क आदि इलाकों में दिए गए कई सांस्कृतिक प्रदर्शनों में भाग लिया था. जब पार्टी ने मलिंगेर इलाके में पार्टी का कार्यक्षेत्र फैलाने का निर्णय लिया तो सहज ही रोशन उत्साह के साथ सामने आया. यानी वह जिस इलाके में जन्म लेकर गरीबी के चलते पेट पकड़कर दूसरी जगह आ बसा था, ठीक उसी इलाके में उसे पीएलजीए का लाल सैनिक बनकर जाना था. इससे और क्या खुशी चाहिए थी उस नौजवान क्रान्तिकारी को? उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने जन्मक्षेत्र में आन्दोलन का विस्तार करने की कोशिशों में भाग लिया. तर्रेमरका के गरीब आदिवासियों ने कॉमरेड रोशन की मौत पर आंसू बहाए कि अपने गांव में पलने वाले लड़के ने एक कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी के रूप में अपने ही गांव में आखिरी सांस ली. आइए, अपनी कुरबानी से मलिंगेर क्षेत्र में भाकपा (माओवादी) का नाम रोशन करने वाले नौजवान साथी कॉमरेड रोशन को अपना सिर झुकाकर श्रद्धांजली पेश करें – उसके सपनों को साकार बनाने की कसम खाएं. ✶

लन्दन बम हमलों के लिए ब्लेइर और उसका गिरोह ही जिम्मेदार

अमेरिकी-ब्रितानी साम्राज्यवादी युद्धों का जवाब जनयुद्धों से देंगे - आतंकवादी कार्रवाइयों से नहीं !!

7 जुलाई को लन्दन में एक साथ हुए बम हमलों में कम से कम 55 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है. तीन विस्फोट लन्दन के भूमिगत रेल मार्ग पर हुए थे जबकि एक विस्फोट बस पर हुआ था. चारों विस्फोट आत्मघाती हमलावरों द्वारा किए गए थे. बाद में किंग्स क्रॉस स्टेशन में लगे क्लोज्ड सरकिट कैमरे के जरिए हमलावरों की पहचान की गई. अपनी पीठ पर बैग लादे हुए ये चारों लोग वहां से अलग होकर अलग-अलग दिशाओं में गए थे. सभी को पाकिस्तानी मूल के ब्रितानी मुस्लिम नागरिकों के रूप में शिनाख्त कर ली गई.

सवाल यह है कि महज 19 साल के युवा ब्रितानी मुसलमानों के आत्मघाती बमबार बनने का कारण क्या होगा. इराक में हो रहे आतंकी हमले, फिलिस्तीन में हो रहे अत्याचार, अफगानिस्तान में हो रहे जुल्म तथा अमेरिका, ब्रिटेन और उनके अन्य सहयोगियों द्वारा लगातार दी जा रही आतंकी धमकियां – यही जनता के गुस्से की जड़ हैं. इराक में प्रतिबन्धों के चलते करीब 10 लाख लोग, जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे शामिल थे, मौत के मुंह में समा गए थे. अब पिछले ढाई साल से जारी इराक युद्ध में करीब एक लाख लोग और मारे गए. वहां एक दशक से ज्यादा समय से जारी है अकथनीय बर्बरता! फिलिस्तीन तो इससे भी ज्यादा अरसे से इसे झेल रहा है. साम्राज्यवादियों और उनके सियोनवादी गुर्गों ने उन्हें उनके घरों से निकाल बाहर कर दिया और वे लगभग आधी सदी से अपनी ही सरजमीन पर बन्दी बनाए गए हैं. अमेरिकी और ब्रितानी साम्राज्यवादियों द्वारा समर्थित इज्राएली सियोनवादियों ने उनकी निर्मम हत्या की. साम्राज्यवादियों के जुल्मों के ये कुछ नमूने भर हैं. इसके अलावा, ब्रितानी एशियाइयों को, खासकर मुसलमानों को लगातार नस्लवादी हमलों और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है – न सिर्फ फासीवादी संगठनों द्वारा, बल्कि सरकारी मशीनरी द्वारा भी. वे नफरत फैलाते हैं और गोरी जनता को इन लोगों के खिलाफ उकसाते हैं. इसके अलावा ये लुटेरे कत्लेआम भी मचाते हैं. ज्यादा से ज्यादा मुनाफों को बटोरने के लिए वे किसी को भी मारते हैं, काटते हैं, यातनाएं देते हैं और हत्या कर देते हैं. इसके लिए उन्हें कोई सजा नहीं मिलती, बल्कि उन्हें सभ्यता के स्तम्भ कहा जाता है. वे दूसरों की यह कहकर निंदा करने का साहस रखते हैं कि वे उनके 'महान' सभ्यता को खतरा पहुंचा रहे हैं.

मुसलमान आतंकवादी इस तरह की कार्रवाइयों के अलावा बेहतर कुछ नहीं जानते क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि इन जुल्मों की जड़ क्या है या इसका समाधान क्या है. इसका जवाब जानने वाले कम्युनिस्ट एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में कहीं भी नहीं हैं. दुनिया भर में कम्युनिस्ट आन्दोलन के पीछे कदम और संशोधनवादियों के हाथों कम्युनिजम (साम्यवाद) की हुई बदनामी के चलते जनता किसी अन्य विकल्प की तरफ जाने को मजबूर है. इन इलाकों में कई कम्युनिस्ट पार्टियां हुआ करती थीं, पर वे अब या तो मैदान में नहीं हैं या फिर उनका पतन प्रतिक्रियावाद में हो चुका है.

चूंकि साम्राज्यवादियों का सही मुकाबला कर सकने वाली ताकतें कहीं नहीं हैं, इसलिए जनता धर्म को अपने सैद्धान्तिक साधन के रूप में तथा आतंकवाद को अपनी पद्धति के रूप में स्वीकार करने लगी है. निश्चित रूप से इसका कोई भविष्य नहीं है. सार्वजनिक स्थलों पर बम विस्फोट करने के उनके आतंकवादी तरीके नुकसानदेह हैं. इससे बेकसूर लोग मारे जाते हैं, न कि बुराई करने वाले अपराध. नरम निशानों को चुनना फौजी तौर पर आसान भले ही हो, पर यह समाधान कतई नहीं है. सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिकी और ब्रितानी साम्राज्यवादियों के बमों से मासूम लोग मारे गए थे, इसका बदला भी उसी रूप में लेने की सोच गलत है. संभवतः मारे गए उन 55 लोगों में से बहुत से लोगों ने उसी शहर में युद्ध के खिलाफ आयोजित शानदार प्रदर्शनों में भी भाग लिया हो. यह बहुत ही दुखद बात है कि अब वे खुद इन हमलों के शिकार बन गए.

ऐसी कार्रवाइयां राजनीतिक रूप से नुकसानदायक है. इससे फासीवादियों और नस्लवादियों को मुसलमानों और एशियाइयों के खिलाफ गोरे लोगों को उकसाने तथा अपनी छवि बेहतर बनाने का ही मौका मिलेगा. अब तक एक मुसलमान की हत्या की गई और समूचे ब्रिटेन में कई एशियाइयों पर हमले किए गए. इससे युद्ध के खिलाफ सभी लोगों में एकजुटता की बजाए फूट पड़ेगी. अगर वहां सरकारी आतंक के खिलाफ डटकर लड़ने वाले कम्युनिस्ट होते तो निश्चित रूप से मुसलमानों और अन्य पीड़ित लोगों के पास न्याय के लिए लड़ने का सच्चा विकल्प होता.

इन गलत तरीकों के बावजूद भी हमें यह दृढ़ता से कहना होगा कि बेकसूर लन्दनवासियों की मौत के लिए ब्लेइर, बुश, आदि अपराधी ही जिम्मेदार हैं – वैसे ही जैसे इराकियों, फिलिस्तीनियों, अफगानों, आदि बेकसूर लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं. एक गोरे आदमी की जिन्दगी भी उतनी ही कीमती है जितनी कि अरबों, एशियाइयों, अफ्रीकियों, लाटिनों, आदि की है. 'प्रभात' लन्दन बम हमलों में मारे गए तमाम लोगों की मौत पर शोक मनाती है, जैसे वह इराक, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान,आदि इलाकों में मारे गए लाखों लोगों की मौत पर मनाती है. ✶

मधुबन के शौर्यपूर्ण संघर्ष को बुलंद करें!

दिनांक 23 जून, 2005 को दोपहर 1.15 बजे जनमुक्ति छापामार सेना (पी.एल.जी.ए.) के लगभग 150 जवानों और 50 लड़ाकू जनता ने पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन बाजार पर आश्चर्यजनक ढंग से एक ही साथ 6 स्थानों– थाना, अंचल-कार्यालय, दो बैंकों, खूंखार जमींदार सीताराम सिंह के आवास और पेट्रोल पम्प पर बिजली की गति से हमला बोलकर आश्चर्यजनक रेड अभियान की कार्रवाई को मिनटों में सफलतापूर्वक सम्पन्न कर थाना से 3- **एसएलआर**, 1 - .303 रायफल, अंचल-कार्यालय से 4 - .303 रायफल, बैंक से 1- **दुनाली** बंदूक तथा सीताराम सिंह के आवास से 2 - **दुनाली बन्दूकें** और दोनों बैंकों से ..... रूपया जप्त कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पिपराही से एक कार्बाइन और एक .303 रायफल भी जप्त किया गया है।

मधुबन के आश्चर्यजनक रेड अभियान की कार्रवाई को अपनी जान की कुर्बानी देकर सफल करने वाले जनमुक्ति छापामार सेना **(पीएलजीए)** के प्लाटूनों, स्थानीय छापामार स्कवाडों **(एलजीएस)**, जनमिलिशिया स्कवाडों **(पीएमएस)** और आत्मरक्षा दल **(एसडीएस)** के अदम्य साहसी वीर योद्धाओं और लड़ाकू जनता को केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन ने **एक वक्तव्य जारी कर** गरमजोशी भरा लाल सलाम पेश **किया**।

साम्राज्यवाद के दलाल भारतीय शोषक-शासक वर्गों ने साम्राज्यवाद के इशारे पर **भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में देश के अनेक हिस्सों में जारी** न्यायपूर्ण क्रांतिकारी संघर्ष को कुचलने के लिए क्रांतिकारी संगठनों को प्रतिबंधित घोषित कर शीर्ष नेतृत्वकारियों, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर फर्जी मुठभेड़ में गोली मारकर हत्याएं करना, बर्बर शारीरिक और मानसिक यातनाएं देना, घेराव-दमन अभियान के तहत जनता को बेरहमी से मार-पीट करने, फर्जी मुठभेड़ में गोली मारने, माँ-बहनों एवं बहु-बेटियों का सामूहिक बलात्कार करने जैसा मध्ययु**गी**न बर्बर हमला चला**ए रखा है**। क्रांतिकारी संघर्ष के ऊपर दमन चलाने के लिए सेना का इस्तेमाल करने हेतु तैया**रियां चल रही हैं**। सैनिक हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करना तो शुरू कर ही दिया है। दूसरी तरफ, शोषक-शासक वर्ग जितना ही दमन चला रहा है उतना ही क्रांतिकारी संघर्ष तीव्र से तीव्रतर होते जा रहा है, यह कामरेड माओ के कथन की सच्चाई को ही प्रमाणित करता है कि जहां जुल्म और दमन होता है वहीं प्रतिरोध भी होता है। उससे भी आगे बढ़कर यहां जितना दमन हो रहा है उतना ही प्रतिरोध, प्रतिरोध और प्रतिरोध तेज होते जा रहा है। **जेओसी** के तहत चलाये जा रहे बर्बर घेराव-दमन के खिलाफ केन्द्रीय योजना अनुसार कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण के तहत जवाबी प्रतिरोधात्मक कार्रवाई को अंजाम देते हुए **उत्तरी बिहार, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश विशेष इलाके के** क्रांतिकारी संघर्ष को गुरिल्ला जोन के स्तर से आधार इलाका के स्तर में विकसित करने हेतु उन्नत स्तर के संघर्ष की तैयारी में **पीएलजीए** जुटी हुई है और परिस्थिति के मद्देनजर प्रतिरोधात्मक कार्रवाई को अंजाम दे रही है। मधुबन के आश्चर्यजनक रेड अभियान उसका ही अभिन्न अंग है।

मधुबन का आश्चर्यजनक रेड अभियान बिहार-झारखण्ड के अब तक के क्रांतिकारी संघर्षों में सबसे बड़ा तथा गुणात्मक रूप से उन्नत स्तर का संघर्ष है, **जोकि** एक ही साथ 6 स्थानों पर हमले किये गये और लड़ाई को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। पुलिस के आला-अधिकारी ने भी इसे स्वीकारा है। यह लड़ाई उत्तर बिहार के विशाल मैदानी इलाके में क्रांतिकारी संघर्ष को गुरिल्ला जोन के स्तर में विकास करने तथा अस्थाई आधार इलाका के स्तर में जाने के क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह लड़ाई इस मायने में भी उन्नत स्तर की लड़ाई है क्योंकि जब मधुबन संघर्ष को सफल किये जाने के बाद दुश्मन द्वारा सी.आर.पी.एफ., एस.टी.एफ., एस.एस.बी. और आर.पी.एफ. के पांच सौ जवानों को लगाकर घेराबंदी अभियान चलाया गया जिसके दौरान कई मुठभे**ड़ें हुईं**, तब पी.एल.जी.ए. के जवानों ने उसका डटकर मुकाबला करते हुए उन्हें धूल चटा**ईं**, उनके कई सिपाहियों को मार गिराया और उनके हथियार भी जप्त कि**ए** और अंततः 'वार प्लानिंग' के तहत घेरकर कुचल डालने के दुश्मन के बुरे मनसूबे को नकाम कर दिया।

दुश्मनों ने इस लड़ाई से जनता को भ्रमित करने और अपनी लाज बचाने के लिए झूठा अफवाह उड़ाने लगा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए उसने दर्जनों, बीस-तीस की संख्या में माओवादियों को मार गिराया है, जोनल कमांडर कामरेड रवि को मार गिराया है आदि। सरासर यह झूठा और भ्रामक प्रचार है। वास्तविकता यही है कि मधुबन संघर्ष सफल करके लौटते वक्त पुलिस द्वारा रास्ते पर घेराबंदी किये जाने पर घेरे को तोड़कर सभी साथियों को सुरक्षित निकालने के दौरान डटकर पुलिस के साथ मुकाबला करने के दौरान पाँच साथियों को शहादत देनी पड़ी और थाना पर हमला करने के दौरान एक साथी शहीद हुए हैं।

जबकि पी.एल.जी.ए. के जवानों ने दुश्मन के 7 जवानों को मार गिराया। जिसमें मधुबन थाना पर दो सिपाहियों, बैंक के एक गार्ड, पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में फेनहारा थानान्तर्गत श्यामपुर में दो जवानों को और पीपराही गांव की मुठभेड़ के दौरान एक हवलदार और एक सिपाही को मार गिराकर उनसे एक कार्बाइन और एक .303 रायफल जप्त किया।

'प्रभात' मधुबन के शौर्यपूर्ण संघर्ष को सफलता दिलाने वाले तमाम कॉमरेडों को – पीएलजीए के बहादुर कमाण्डरों व जांबाज योद्धाओं को, उत्तरी बिहार के लड़ाकू अवाम को लाल अभिनन्दन पेश करती है. इस संघर्ष के सिलसिले में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले साहसी योद्धाओं को विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजली पेश करती है. उनके सपनों को साकार बनाने का संकल्प दोहराती है. ✶

भारत-अमेरिका फौजी समझौते को रद्द करो !

अमेरिकी जकड़ से देश को बाहर निकालो !!

अपने पहले ही अमेरिकी दौरे में देश के रक्षा मंत्री प्रणव मुखर्जी ने देश की सुरक्षा को अमेरिकी साम्राज्यवादियों के पास गिरवी रखते हुए एक 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया. 28 जून 2005 को प्रणव मुखर्जी और उसके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने ''अगले दस साल के लिए अमेरिका-भारत सुरक्षा सम्बन्ध हेतु ढांचा'' पर दस्तखत किया. ये सुरक्षा समझौते दो देशों के बीच बढ़ रहे रणनीतिक समझौतों का हिस्सा हैं, जबकि भारत अमेरिकी साम्राज्यवाद के भू-राजनीतिक मकड़जाल में और ज्यादा फंसता जा रहा है.

यह नया ''ढांचा'' यह तय करता है : संयुक्त अभ्यासों और विनिमयों को संचालित करना; बहुराष्ट्रीय कार्रवाइयों में सहयोग करना; आतंकवाद को हराने सेनाओं की क्षमताएं बढ़ाना; व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने हेतु क्षमताएं बढ़ाना; भारत को सुरक्षा बिक्री बढ़ाना; और प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा में सहयोग बढ़ाना. अपने दौरे के दौरान प्रणव मुखर्जी ने बुश के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की जिनमें उप-राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख और कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य शामिल हैं. उसने संयुक्त बल कमान और उत्तरी कमान का दौरा किया. दो देशों के प्रमुखों की पहली मुलाकात की पूर्व संध्या पर इस समझौते पर दस्तखत की गई जोकि पूरे आत्मसमर्पण का रास्ता बनाता है!

इस समझौते के बाद एक ''सुरक्षा संग्रहण उत्पादन ग्रुप'' का गठन किया गया ताकि रक्षा व्यापार पर नजर रखी जा सके और तकनीकी सहयोग की सम्भावनाएं तलाशी जा सकें. ये समझौते रक्षा सम्बन्धों को आगे बढ़ाने में एक दशक पहले हस्ताक्षरित समझौते की तुलना में एक छलांग हैं. पूर्व में बनाया गया 'रक्षा नीति ग्रुप' द्विपक्षीय रणनीतिक रक्षा सम्बन्ध का मार्गदर्शन करने वाली प्राथमिक व्यवस्था के रूप में काम करता रहेगा. इन समझौतों पर जिस तेजी से हस्ताक्षर किया गया उससे यह साफ हो जाता है कि इसकी जमीनी कार्य काफी पहले ही पूरा किया गया था.

अमेरिकी साम्राज्यवाद की तरफ यह झुकाव एक ऐसी सरकार के सत्ता में होते हुए दिखाई दे रहा है जिसे तथाकथित वामपंथी भाकपा/माकपा का समर्थन हासिल है. वर्तमान यूपीए सरकार अमेरिका के सामने घुटने टेक देने में जिस हद तक गई हुई है वह पहले की एनडीए सरकार से अलग बिलकुल नहीं है - बावजूद इसके कि उसे सत्ताधारी संशोधनवादियों से नकली विरोध का सामना करना पड़ रहा है. एनडीए शासन के दौरान अमेरिकी जंगी जहाजों को कई बार पोर्टकाल्स तथा समुद्र में, हवा में और यहां तक कि जमीन पर संयुक्त अभ्यासों में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी हुई थी.

गंभीर दुष्प्रभाव

इस समझौते के गंभीर दुष्प्रभाव होंगे - 1) देश के अन्दर और दक्षिण एशिया के जन आन्दोलनों, खासकर माओवादियों के नेतृत्व में जारी आन्दोलनों को कुचलने में अमेरिका की परोक्ष और यहां तक कि प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ जाएगी; 2) दुनिया भर में, खासकर एशिया में अमेरिका के भू-राजनीतिक हितों को साधने के लिए भारतीय सैनिकों को बलि के बकरे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा; 3) इस समझौते का रणनीतिक परिणाम अमेरिकी दैत्य के सामने सम्पूर्ण जी-हुजूरी, यानी उसके आदेशों को लागू करना जिससे देश की जनता के जीवन पर भयानक प्रभाव पड़ता है.

अमेरिकी और भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के अन्दर, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में संयुक्त विद्रोह-विरोधी प्रशिक्षण अभियानों का सिलसिला पहले ही चलाया था. माओवादियों के खिलाफ वर्तमान सरकार की आक्रामक नीतियों को अमेरिकी प्रशासन का पूरा समर्थन हासिल है. दरअसल वह अमेरिका ही था जिसने माओवादियों की एकता को देखते हुए शासकों को यह चेताते हुए कि इससे देश में विदेशी निवेश पर प्रभाव पड़ेगा, कड़ा रुख अपनाने को प्रोत्साहित किया.

पुलिसिया गतिविधियों में अमेरिका के आंतरिक हस्तक्षेप के अलावा, ''ढांचा'' से यह साफ हो जाता है कि जी-हुजूरिया भारतीय रक्षा मंत्री ने दुनिया भर में अमेरिकी हितों को साधने के लिए भारतीय सैनिकों को बलि के बकरे के रूप में इस्तेमाल करने पर सहमति जताई. जबकि इराक में अब तक अमेरिका के 2,000 सैनिक मारे जा चुके हैं (अधीकृत आंकड़ा) और कई हजार घायल हो चुके हैं, अमेरिका पिछड़े देशों के सैनिकों के लिए हाथ-पैर मार रहा है जिन्हें कि अपने नए युद्धों में आगे के कतार में खड़े किया जा सके. हालांकि दोनों एनडीए और यूपीए सरकारों ने भारतीय सैनिकों को इराक भेजने की जी-तोड़ कोशिश की, लेकिन जनता के विरोधी तेवर के चलते वे ऐसा नहीं कर सकीं. लेकिन अब भविष्य में ऐसा करने के लिए इस ''ढांचा'' का इस्तेमाल किया जाएगा. भारत एक ऐसा देश है जिसके ''शांति रक्षक बल'' बड़ी तादाद में विदेशों में तैनात किए गए हैं. यह ''ढांचा'' बताता है कि ''बहुपक्षीय कार्रवाइयों, आपदा प्रतिक्रिया, 'शांति' स्थापना और दुनिया भर में 'लोकतंत्र' का विस्तार करने के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को गुणात्मक रूप से एक नया आयाम दिया जाएगा.'' दूसरे शब्दों में अब अमेरिका अपने कुछ राजनीतिक व फौजी कार्यभारों को आउटसोर्स करने की योजना में है. इस 'रक्षा समझौते'' के मुताबिक (दुनिया भर में चलने वाली) अमेरिका-नीत गोपनीय ''बहुपक्षीय कार्रवाइयों'' में भारतीय सैनिकों को तैनात किया जाएगा, चाहे उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वीकृति हो या न हो. दरअसल इस ''ढांचा'' के जिस खण्ड में ''सफल शांतिरक्षक कार्रवाइयां संचालित करने के लिए विश्व व्यापी क्षमता के निर्माण में मदद की सहमति'' का विवरण है, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का जिक्र तक नहीं है. इसलिए, यह ''ढांचा'' वास्तव में दुनिया भर में अमेरिकी आधिपत्य को मान्यता देता है और इस प्रक्रिया में सहायता का वादा करता है.

''सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने हेतु क्षमताएं बढ़ाने'' के लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में बहुपक्षीय कार्रवाइयों में सहयोग के समझौते का मतलब बदनाम अमेरिकी प्रसार सुरक्षा पहल (प्रॉलिफरेशन सेक्यूरिटी इनीशिएटिव - पीएसआइ) पर परोक्ष रूप से हस्ताक्षर करना है. पीएसआइ एक अमेरिका-नीत बहुराष्ट्रीय पहल है जिसमें बीच समन्दर में तीसरे देश के जहाजों पर हमला करना शामिल है. एशिया में पीएसआइ का विरोध करने वाले प्रमुख देश हैं चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और इरान. लेकिन अमेरिका अत्यधिक वफादार गुलाम भारत सरकार ने इस पर लगभग हस्ताक्षर कर दिया. हालांकि इस समझौते से पहले से ही भारतीय नौसेना रणनीतिक मलक्का जलडमरूमध्य में पुलिसिया काम में सहायता करती आ रही है.

इस ''ढांचा'' में यह भी कहा गया है कि मिसाइल रक्षा सम्बन्धी क्षेत्र में भारत और अमेरिका के सहयोग का दायरा बढ़ेगा. यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि 2001 में एनडीए के शासन में, भारत पहला देश था जिसने अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा योजना का समर्थन किया था, यहां तक कि नाटो (NATO) के सदस्य देशों से भी पहले.

इस ''ढांचा'' का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू फौजी सामग्रि की खरीद के लिए बड़े पैमाने पर भारत का अमेरिका की ओर मुड़ना है. अमेरिका पहले ही भारत को 120 एफ–16 लड़ाकू विमान देने की पेशकश कर चुका है (पाकिस्तान से भी यही पेशकश की गई). इससे न सिर्फ बोइंग जैसी संकटग्रस्त अमेरिकी कम्पनियों को नई जान मिलेगी, बल्कि फौजी साजोसामान के लिए अमेरिका पर भारत की निर्भरता में और बढ़ोत्तरी होगी. अमेरिका का कठपुतला मुखर्जी ने यहां तक कह डाला कि ''कई इलाकों में अमेरिकी रक्षा उद्योग के लिए भारत एक बढ़िया आधार बन सकता है.'' उसने जोड़ा, ''हमें एक अर्थपूर्ण और प्रगतिशील तरीके से उन तमाम बाधाओं को दूर करने की जरूरत है जो हमारे सहज गठबन्धन के रास्ते में पेश आ रही हैं, ताकि इस दुनिया को ज्यादा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध जगह में बदलने के लिए हाथ मिलाए जा सकें.'' एक द्विपक्षीय ''रक्षा संग्रहण और उत्पादन ग्रुप'' की स्थापना की गई ताकि व्यापार तथा सह–उत्पादन और तकनीकी सहयोग के लिए सहयोग की सम्भावनाओं को तलाशा जा सके.

यह रक्षा ''ढांचा'' भारतीय शासक वर्गों के अमेरिकी शिविर में पूरी तरह शामिल हो जाने की कोशिशों का हिस्सा है. एशिया में आगामी भू–राजनैतिक परिदृश्य में अमेरिकी साम्राज्यवादियों का सेवक औजार के रूप में काम करने को भारतीय शासक वर्ग उत्सुक हैं. वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एशिया में भारत के महत्व को पहचाना है. इस क्षेत्र में उदित हो रहे विशालकाय चीन को टक्कर दिलवाने का दूरगामी लक्ष्य भी अमेरिका को है. ज्यों ही इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, उसके तुरन्त बाद कैरनीजी संस्थान, जोकि अमेरिका की प्रमुख विशेषज्ञ संस्था है, ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अमेरिका की विश्वव्यापी योजनाओं के मद्देनजर भारत के महत्व पर रोशनी डाली गई.

कैरनीजी रिपोर्ट

''एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत : अमेरिका के लिए एक कार्य योजना'' शीर्षक इस रिपोर्ट को जे. टेल्रिस ने प्रस्तुत किया, जो रक्षा व परमाणु विशेषज्ञ तथा कैरनीजी एन्डोमेन्ट फर इंटरनेशनल पीस में वरिष्ठ सह सदस्य है. टेल्रिस एक मुख्य सलाहकार था जिसने बुश/वाजपेयी सरकारों के द्वारा आगे बढ़ाई गई रणनीतिक भागीदारी पर जोर दिया था. इस रिपोर्ट में यह आह्वान किया गया है कि इरान गैस पाइप लाइन का अमेरिका समर्थन करे और हाइ–टेक तकनीकी के प्रसार और रक्षा के क्षेत्र में भारत पर लगे तमाम प्रतिबन्ध हटा दे.

रक्षा के क्षेत्र में टेल्रिस के कई और विचार भी हैं. उसका प्रस्ताव है – ''एक समग्र रक्षा भागीदारी को अमल में लाया जाए जिसमें सेना के सम्बन्धों, रक्षा व्यापार और उत्पादन तथा संयुक्त अनुसंधान व कार्रवाइयों को एक दस्तावेज में शामिल किया जाएगा. हिन्द महासागर में कार्रवाइयों पर भारत और अमेरिका एक सहमति पत्र पर दस्तखत कर सकते हैं. भारत के रक्षा क्षेत्र में निवेश करने अमेरिकी कम्पनियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है.

टेल्रिस की रिपोर्ट भारत में विद्रोह–विरोधी कार्रवाइयों मे विस्तृत रूप से भागीदारी लेने का भी आह्वान करती है. भारत में ''उग्रवादी तंत्र के पैमाने, विविधता और अत्याधुनिकता'' पर चिन्ता जताई गई. टेल्रिस रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत को उभरते चीन के खिलाफ एक अड्डे के रूप में निर्मित किया जाए. चीन को अमेरिका अपने हितों के खिलाफ मानता है और उदीयमान चीन के खिलाफ भारत को एक बाड़ बनाना चाहता है.

दरअसल 2002 में पेन्टगान द्वारा तैयार एक रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि अमेरिका को एशिया में एक ऐसा सक्षम सैन्य सहयोगी चाहिए जो शांतिरक्षक कार्रवाइयां, तलाश और मदद, आदि निम्न व जोखिम भरे काम कर सके. इससे अमेरिका को बड़े–बड़े लड़ाकू कर्तव्यों पर ध्यान केन्द्रित करने का मौका मिलेगा. इसका सीधा सा मतलब है अमेरिका भारतीय सेना को अगुवा सिपाही के रूप में इस्तेमाल कर बलि का बकरा बनाएगा. ऐसे घटिया काम पूरे होने के बाद अमेरिकी फौजें आकर नियंत्रण कर लेंगी. इस रिपोर्ट में भी चीन से मिल रही रणनीतिक चुनौती से निपटने के लिए भारत के इस्तेमाल की बात की गई थी. ऐसी भूमिका से गंभीर दुष्परिणाम होंगे. इसका सीधा सा मतलब है अमेरिका जोखिम भरे कार्यों को भारत में आउटसोर्स करने वाला है.

इस रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट है कि अमेरिकी अधिकारी भारतीय अड्डों और फौजी सुविधाओं को इस्तेमाल करना चाहेंगे.

भारत का रणनीतिक महत्व

विश्व साम्राज्यवाद, खासकर एशिया में, की भू–राजनीति में भारत को महत्वपूर्ण स्थान है. यही वजह है कि प्रमुख साम्राज्यवादी शक्तियां इससे इतनी उम्मीद रखती हैं. 1980 के दशक से भारतीय शासक वर्ग एक मात्र महाशक्ति के रूप में मौजूद अमेरिकी कैम्प से करीब होते जा रहे हैं. सत्ता में चाहे जो भी पार्टी रहे, यहां तक कि भाकपा/माकपा भी रहे, इस रुझान में कोई खास फेरबदल नहीं हुआ है. 2000 के बाद, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच बढ़ रहे तनाव के बावजूद भारतीय शासक अमेरिका के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाते जा रहे हैं (इसके बावजूद भी कि अन्य शक्तियां – खासकर रूस और यूरोपीय यूनियन अपना प्रभाव बढ़ाने हेतु स्पर्धा कर रहे हैं).

साम्राज्यवादियों की रणनीतियों में भारत के महत्व के कई कारण हैं – पहला, यह एक बहुत बड़ा देश है जहां एक अरब से ज्यादा आबादी है. इसलिए यह एक बड़ा बाजार है और कच्चे मालों का स्रोत भी है. दूसरा, इसके पास बहुत बड़ी सेना और अर्ध–सैनिक बल हैं जिससे यह इस इलाके में प्रतिक्रियावाद और प्रति–क्रान्ति का एक गढ़ बन सकता है. नेपाल और भारत में बढ़ रहे माओवादी आन्दोलनों और बंग्लादेश में उसके बढ़ने की सम्भावनाओं को देखते हुए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है. दरअसल माओवादियों के नेतृत्व में चल रहे तीन प्रमुख जनयुद्ध एशिया में ही हैं – नेपाल, भारत और फिलिप्पीन्स. तीसरा, भारत को उभरते चीन के प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा जा रहा है. चौथा, चूंकि यहां विशाल आबादी और बहुत भारी सेना मौजूद है, इसलिए आगामी साम्राज्यवादी युद्धों में दुनिया भर में यहां के लोगों को बलि का बकरा बनाने की सम्भावनाएं प्रबल हैं. और आखिरी कारण है, भारत में ऐसे जी–हुजूरिया शासक वर्ग हैं जो इतिहास में दो सदियों से ज्यादा समय से साम्राज्यवादियों और उपनिवेशवादियों की धुनों पर नाचते आ रहे हैं – वे साम्राज्यवादी युद्धोन्मादियों के वफादार कुत्ते हैं.

भारत की जनता ही साम्राज्यवादियों और देश में उनके सेवक औजारों की साजिशों को मात दे सकती है. रक्षा समझौते के खिलाफ जन–विरोध ही उसके अमल को रोक सकता है. एक साम्राज्यवाद–विरोधी जन–उभार ही साम्राज्यवाद, खासकर अमेरिका के सामने देश के लगातार आत्मसमर्पण को रोक सकता है. फिलहाल देश की जनता के सामने बड़े खतरे हैं क्योंकि यहां के सत्ताधारी साम्राज्यवादी जकड़ में तेजी से फंसते जा रहे हैं. ★

प्रतिक्रियावादी शाही नेपाल सेना के खिलाफ माओवादी योद्धाओं का शानदार हमला

नेकपा (माओवादी) की अगुवाई में 1996 में जनयुद्ध की शुरूआत करने बाद से अब तक बीते 10 सालों में जन मुक्ति सेना (पीएलए) ने कई उपलब्धियां हासिल कीं. हाल में, 7 अगस्त 2005 को पश्चिमी नेपाल के कालिकोट स्थित सैन्य छावनी पर उन्होंने जो शूरतापूर्ण हमला किया वह अपने आपमें बेमिसाल है. उस सैन्य कैम्प में करीब 250 प्रतिक्रियावादी आरएनए (शाही नेपाल सेना) सैनिक तैनात थे. पीएलए के पश्चिमी डिवीजन ने 7 अगस्त को शाम के 5.40 बजे यह हमला शुरू किया था, अगली सुबह के 4 बजे तक विजय हासिल की गई. पीएलए ने इस कैम्प से बड़े पैमाने पर हथियार व गोलाबारूद जब्त किया.

जब्त की गई शस्त्रास्त्र सामग्रि इस प्रकार है – एक 81 मिमी बैरल और उसके 150 बम; एक जीपीएमजी और उसकी 5 हजार गोलियां; 20 एलएमजी और उनकी 12 हजार गोलियां; 70 इन्सास रायफलें और उनकी 30,000 गोलियां; 80 एसएलआर और उनकी 21,000 गोलियां; 2 एसएमजी और उनकी 3 हजार गोलियां; 2 ब्राउनिंग पिस्तौल और उनकी 2 हजार गोलियां; 2 दो इंच मोर्टार और उनके 200 बम; आदि. 250 सैनिकों में से 159 को मार डाला गया और 50 से ज्यादा सैनिकों को युद्ध बन्दी बनाया गया.

पीएलए की तरफ से इस हमले को सफल बनाने के लिए 26 योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया जिनमें बटालियन कमिस्सार कॉमरेड लोकेश (शरद अवस्थी) शामिल हैं. कुछ अन्य घायल हो गए. एक बयान में नेकपा (माओवादी) ने मारे गए तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की और इस हमले को सफल बनाने वाले तमाम कमाण्डरों, योद्धाओं और जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया. ✶

आतंकी सीआरपी बलों पर पीएलजीए के जबर्दस्त हमले में बारूदीसुरंग-रोधक गाड़ी ध्वस्त- 24 जवानों का सफाया

बस्तर के पश्चिमी हिस्से में पिछले जून महीने से जारी फासीवादी 'जन जागरण' अभियान के तहत गुण्डावाहिनी के साथ–साथ पुलिस, सीआरपीएफ और नगा पुलिस बल गांव–गांव में आतंक का ताण्डव मचा रहे थे. खासतौर पर बीजापुर पुलिस जिले में केन्द्रित इस अभियान में अब तक 100 से ज्यादा आम लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हो गए. दर्जनों गांवों को जलाकर राख कर दिया गया. महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाओं का कोई हिसाब नहीं है. ऐसी पाशविक कार्रवाइयों को 'ऑपरेशन ग्रीन हन्ट', 'ऑपारेशन रक्षक', आदि नाम दिए जा रहे थे. इस बर्बरतापूर्ण दमन के बीचोबीच ही जनता और जन मुक्ति छापामार सेना के योद्धा प्रतिरोध का परचम बुलन्द किए हुए थे. जनता और जन मिलिशिया की सक्रिय मदद से पीएलजीए सैनिकों ने बीजापुर से गंगलूर जाने वाली सड़क पर 3 सितम्बर 2004 को एक जबर्दस्त हमला कर दिया. दण्डकारण्य आन्दोलन के इतिहास में अब तक के इस बड़े घात हमले में कुल 24 जवान मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए. खास बात यह थी कि जिस गाड़ी को बारूदीसुरंग–रोधक गाड़ी (एन्टी लैण्डमाइन वेहिकिल) के रूप में बढ़ा–चढ़ाकर प्रचारित किया जा रहा था, उसे पीएलजीए ने जबर्दस्त धमाका कर उड़ा दिया जिससे उसके दो टुकड़े हो गए. इस गाड़ी में कुल 27 जवान तैनात थे. और एक खास बात यह थी कि छापामारों की जिस टुकड़ी ने इस हमले को अंजाम दिया उसकी संख्या पुलिस बलों से काफी कम थी. इसके बावजूद पीएलजीए सैनिकों ने अदम्य शूरता का प्रदर्शन करते हुए इसे सफल बनाया. घायल दुश्मनों की गोलीबारी के बीच ही लाल सैनिक आगे बढ़े और दुश्मन के तीन हथियार – दो इंसास रायफलें और एक एसएलआर उठा लाए थे. बाकी हथियार टूटकर दूर–दूर छिटक गए थे जिन्हें नहीं लाया जा सका.

पीएलजीए द्वारा छीनी गई रायफलें

इस हमले ने जहां दुश्मन को हिलाकर रख दिया, वहीं जनता को बेहद उत्साहित किया. बारूदीसुरंग–रोधी गाड़ी को लेकर भी पुलिस वाले बढ़ा–चढ़ाकर प्रचार करते थे. थाना–कस्बों में लोगों को इकट्ठे करके उस पर गोलियां चलाते थे और यह डींग मारते थे कि इसे न तो बन्दूक की गोलियों से भेदा जा सकता और न ही विस्फोट से उड़ाया जा सकता. लेकिन इस हमले ने इस गाड़ी को लेकर निर्मित सारे भ्रम एक झटके में बुरी तरह टूट गए. जनता का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया. ✶

बुरी तरह क्षतिग्रस्त बारूदीसुरंग–रोधी गाड़ी

महंगाई बढ़ाने वाली मूल्य संवर्धित कर (वैट) प्रणाली का विरोध करो !

हाल ही में सरकार ने भारत की जनता पर मूल्य संवर्धित कर (वैल्यू एडेड टैक्स – वैट) प्रणाली थोप दी. फिलहाल 21 राज्यों में इसे लागू किया गया. 1 अप्रैल से लागू इस प्रणाली को भाजपा–शासित राज्यों ने लागू करने से स्पष्ट मना किया. हालांकि उनका यह विरोध दिखावटी है क्योंकि इस प्रणाली से उन्हें कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है. सीआइआइ, एफआइसीसीआइ जैसे बड़े उद्योगपतियों के संगठनों ने इसे जल्दी लागू करने पर काफी जोर दिया. हाल ही में भारत के दौरे पर आए आइएमएफ (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) के प्रबन्ध निदेशक रोड्रिगो डि रैटो ने पत्रकारों से कहा, ''नई वैट प्रणाली को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूं.'' भारत में विश्व बैंक के निर्देशक मैकेल एफ. कार्टर ने कहा कि वैट को लागू करना भारत सरकार का ''एक बेहद सकारात्मक कदम'' है. दूसरी तरफ छोटे व्यापारियों, खासकर खुदरा व्यापारियों ने इसका विरोध किया और 21 फरवरी को देशव्यापी बन्द का भी आह्वान किया था. बन्द को मिली सफलता के बाद उनके संगठन अखिल भारतीय व्यापारियों के महासंघ (सीएआइटी) ने, जोकि इस विरोध का नेतृत्व कर रहा है, वैट के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी.

वैट प्रणाली साम्राज्यवादी आर्थिक सुधारों का हिस्सा है. साम्राज्यवादियों के हितों को पूरा करने के लिए ही इसे लागू किया गया है. इसे लागू करने से भारत का विशाल बाजार एक एकीकृत बाजार में बदल जाएगा. फिलहाल बिक्री कर राज्यों के दायरे में है. अलग–अलग राज्य अपने–अपने विशेष हालात को ध्यान में रखते हुए बिक्री कर तय करते हैं. यह एकीकृत बाजार के निर्माण के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है. इस रुकावट को हटाने की कोशिश ही वैट है. इससे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत के बाजार में अपने उत्पाद निर्बाध बेचने का मौका मिलेगा. भारतीय बाजार को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पूरी तरह सम्मिलित करने की दिशा में यह एक कदम है. इस प्रणाली को लागू करने से छोटे–छोटे दुकानदार हाशिए पर चले जाएंगे. इसीलिए वे इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं.

वैट या मूल्य–संवर्धित कर प्रणाली है क्या?

किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति उपभोक्ता को उसके मूल उत्पादक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि यह अनेक शृंखलाओं में से होकर अन्तिम उपभोक्ता तक पहुंचती है. पत्येक अवस्था में से होकर गुजर रहे उत्पाद एवं सेवा में उसे शृंखला से आगामी शृंखला में परिवर्तन के साथ ही उसके मूल्य में भी वृद्धि प्रकट होती है और इसी वृद्धि को मूल्य–संवर्धन के नाम से जाना जाता है. यह मूल्य–संवर्धन प्रत्येक शृंखला के उत्पादक तथा पूर्तिकर्ता व वितरक द्वारा अपने लाभ के अंश को सम्मिलित करने तथा कर की राशि जोड़ने एवं यातायात व अन्य खर्चों को जोड़ने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है. मूल्य–संवर्धित कर एक विशेष प्रकार का कर है जोकि उत्पाद व सेवाओं पर आरोपित किया जाता है (निर्यात व सरकारी सेवाओं के अतिरिक्त) जिसका विशिष्ट लक्षण है कि उसमें उत्पादन से लेकर खुदरा बिक्री तक की प्रत्येक अवस्था में वर्द्धित मूल्य पर लगाया जाता है.

उदाहरण के लिए क्षेत्रफल विधि से वैट की गणना इस प्रकार की जाती है –

पहला चरण : कच्चा माल उत्पादक
विक्रय मूल्य = 1000 रुपए
मूल्य वर्धन = 1000 रुपए
वैट – 10% की दर से = 100 रुपए

दूसरा चरण : निर्माता
विक्रय मूल्य = 2000 रुपए
मूल्य वर्धन = 2000–1000 = 1000 रुपए
वैट – 10% की दर से = 100 रुपए

तीसरा चरण : थोक विक्रेता
विक्रय मूल्य = 2500 रुपए
मूल्य वर्धन = 2500–2000 = 500 रुपए
वैट – 10% की दर से = 50 रुपए

चौथा चरण : खुदरा विक्रेता
विक्रय मूल्य = 3000 रुपए
मूल्य वर्धन = 3000–2500 = 500 रुपए
वैट – 10% की दर से = 50 रुपए

चारों चरणों में कुल संग्रहित वैट
= 100 + 100 + 50 + 50 = 300 रुपए
अन्तिम बिन्दु पर खुदरा मूल्य पर बिक्री दर @10% = 300 रुपए

वैट से क्या नुकसान होंगे?

सर्व प्रथम यह छोटे उद्योगपतियों पर कुठाराघात है. देश के कुल औद्योगिक निर्गत (आउटपुट) में छोटे उद्योगों का हिस्सा एक तिहाई है. 1999 में देश के कुल 408 करोड़ मजदूरों में से सिर्फ 66 लाख ही बड़े उद्योगों में काम कर रहे थे, बाकी मजदूर छोटे उद्योगों में कार्यरत थे. पुरानी बिक्री कर प्रणाली के तहत अत्यधिक वस्तुओं, यानी औद्योगिक आगतों (इनपुट्स) या तैयार की गई वस्तुओं पर कर लगता था, लेकिन छोटे उद्योगों को छूट मिल जाती थी. छोटे उद्योगों को कर छूट मिलने से उन्हें कच्चामाल खरीदने और ऋण लेने से पड़ने वाले बोझ से कुछ राहत मिलती थी और वे बड़े उद्योगों से भी मुकाबला कर सकते थे. अब वैट के तहत एक निश्चित टर्नोवर सीमा में छोटे उद्योगों को हालांकि कर छूट अभी भी मिलेगी, पर छोटे उद्योगों में बने उत्पादों को बेचने वाले थोक व्यापारी पर पूरी कर दर लग जाएगी. वहीं बड़े उद्योगों के उत्पादों को बेचने वाले थोक व्यापारी पर लगने वाले कर से पहले उद्योगपति द्वारा चुकाया गया कर काटा जाएगा. इससे दोनों उत्पादों को लगभग एक ही दाम पर बाजार में बेचना पड़ेगा. व्यापारी तो छोटे उद्योगों की बनिस्बत बड़े उद्योगों मं बनने वाले उत्पादों को बेचना चाहेगा जो उसे ज्यादा फायदेमंद होगा.

अगर वैट की मार से छोटे उद्योग चौपट हो जाते हैं तो आगामी चंद सालों में कई लाख लोग रोजगार से हाथ धो बैठेंगे. इससे उपभोक्ता वस्तुओं का 'घरेलू बाजार' और ज्यादा सिकुड़ जाएगा जिससे बेरोजगारी में और ज्यादा बढ़ोत्तरी होगी. दशकों से छोटे उद्योगों में बनी वस्तुओं की खुदरा कीमतें दुनिया में सबसे कम रहते आ रही हैं. पर आर्थिक सुधारों की मार छोटे उद्योगों पर पड़ी और उनके लिए आरक्षित वस्तुओं में कटौती की जाने लगी. पर जनता का दबाव इतना ज्यादा है कि बड़े पूंजीपतियों का हितपोषण करने वाली सरकारें चाहकर भी आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने में सफल

न हो सकीं. पर अब यह काम वैट पूरा कर देगा. जब एक बार छोटे उद्योग बैठ जाएंगे तो बाजार में बड़े उद्योगों का हिस्सा बढ़ जाएगा और उपभोक्ता कीमतें प्रायः 'वैश्विक स्तरों' तक पहुंच जाएंगी.

इतना ही नहीं. वैट की दरें लगभग सभी राज्यों में ''समान'' हैं. पर इससे उन राज्यों को नुकसान होगा जो कमजोर और पिछड़े हैं. मसलन उड़ीसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ जैसे औद्योगिक तौर पर पिछड़े राज्यों की प्रति व्यक्ति आयें तो कम हैं, पर वे लौह धातु, कोयला, बाक्साइट, आदि कीमती खनिजों से समृद्ध हैं. इन राज्यों को खनिजों पर वैट की दर 4% ही मिलेगी, चाहे उसका इस्तेमाल उन्हीं राज्यों में हो या बाहर. बाजार का उसूल है कि कारखाने उन्हीं इलाकों में लगेंगे जो ज्यादा विकसित और समृद्ध हैं.

वैट का सीधा प्रभाव व्यापारियों पर भले ही पड़ता हो, पर समूची जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा. वैट एक परोक्ष कर है जिसका भार पूरा उपभोक्ता पर ही लदेगा. इसलिए इसका दुष्प्रभाव अन्तिम रूप से उपभोक्ता पर ही पड़ेगा. अब तक कर से मुक्त रखी गई कई वस्तुएं, मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ अब वैट के दायरे में आने वाले हैं. फिलहाल वैट के मुताबिक कच्चेमाल पर कर 4% लगेगा और बाकी वस्तुओं पर 12.5% कर लगेगा, जबकि अब तक 8% बिक्री कर ही लगता था. इसका मतलब लगभग 50% कर बढ़ता है. इससे वस्तुओं की कीमतें निश्चित रूप से बढ़ेंगी. दवाओं और खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी से पहले ही कंगाल हो चुके लोगों पर अब महंगाई की गाज गिरना निश्चित है.

संविधान के तहत बिक्री कर राज्यों के दायरे में था. लेकिन अब देश भर में वैट लागू करने से राज्यों के अधिकारों का हनन होगा. वैट राज्यों की स्वायत्तता के खिलाफ है. अमेरिका समेत दुनिया के जिन-जिन देशों में संघीय प्रणाली लागू है उन देशों में वैट लागू नहीं किया गया. लेकिन भारतीय शासक वर्गों ने साम्राज्यवादी संगठनों की शह पर वैट लागू कर संघीय व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दीं.

वैट के लागू होने से उसकी गणना के लिए छोटे व्यापारियों व उद्योगपतियों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा. रिकार्ड तैयार करना अनिवार्य होता है. एक अनुमान है कि ब्रिटेन में वैट को लागू करने पर लेखा-जोखा रखने के लिए जहां छोटे उद्योगपतियों को अपने कुल टर्नोवर का 2% खर्च करना पड़ा, वहीं बड़े पूंजीपतियों को सिर्फ 0.01% का खर्च आया.

यही वजह है कि वैट को वाशिंगटन अधिवेशन ने आगे बढ़ाया और भारत के बड़े पूंजीपतियों ने इसका सिर पर उठाकर स्वागत किया. पर आश्चर्य इस बात का है कि वैट का विरोध सिर्फ व्यापारियों ने ही किया – मजदूरों और किसानों के संगठनों ने आमतौर पर चुप्पी ही साध ली. कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के नेतृत्व में काम करने वाले जन संगठनों का यह फर्ज बनता है कि वे वैट का दृढ़ता से विरोध करें और वैट का विरोध करने वाले सभी व्यापारियों को गोलबन्द कर साम्राज्यवाद के खिलाफ एक विशाल व ताकतवर संयुक्त मोर्चा खड़ा करें. ✶

तुर्की में हुई माओवादियों की जघन्य हत्याओं की निंदा करो !

कॉमरेड केफर कांगोज और अन्य लोक नायकों को लाल सलाम !

16-17 जून 2005 को फासीवादी तुर्की सरकार ने माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 17 क्रान्तिकारियों की हत्या की और अन्य तीन को घायल किया. यह घटना तुर्क-कुर्दिस्तान के देर्सिम क्षेत्र के मेरकान में हुई थी. शहीद हुए माओवादियों में पार्टी के महासचिव समेत केन्द्रीय कमेटी के 6 सदस्य शामिल हैं. यह हमला तब हुआ था जब माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी (एमकेपी) की दूसरी कांग्रेस के आयोजन के सिलसिले में प्रमुख नेता इकट्ठे हुए थे. उनकी रक्षा कर रहे छापामारों की एक छोटी टुकड़ी पर लगभग एक हजार सैनिकों ने तीन सैन्य हेलिकॉप्टरों की मदद से बेहद विनाशकारी हमला किया. हेलिकॉप्टर गनशिपों, बमों से किए गए इस हमले में पार्टी के महासचिव कॉमरेड केफर कांगोज, उप महासचिव आइदीन हनबयात के अलावा केन्द्रीय कमेटी सदस्य अली रिजा सबुर, केमैल कैकमेक, ओक्केप करोदलु और गुलनैज यीलडीज तथा अन्य 11 कॉमरेड शहीद हो गए. अपने साम्राज्यवादी आकाओं से लाए गए अत्याधुनिक हथियारों व इलेक्ट्रॉनिक साजोसामान के प्रयोग कर प्रतिक्रियावादी तुर्की सरकार ने इस जघन्य कार्रवाई को अंजाम दिया.

कॉमरेड कांगोज बेहद लोकप्रिय नेता थे जिन्होंने विश्व समाजवादी क्रान्ति के हिस्से के तौर पर तुर्की की जनता के मुक्ति के लिए दशकों से संघर्ष का परचम ऊंचा उठाए रखा था. तुर्की की काली कोठरियों में उन्होंने दस साल से ज्यादा समय बिताया. जेल में भी वह एक बहादुर व आदर्शवान नेता रहे जिनसे क्रान्तिकारी बन्दी बेहद प्यार करते थे और जेल अधिकारी बेहद नफरत. जेल में रहते हुए भी कॉमरेड केफर कांगोज ने तुर्की व विश्व के कम्युनिस्ट आन्दोलन की समस्याओं के प्रति पूरा ध्यान दिया था. 2002 में अपनी रिहाई के बाद कॉमरेड कांगोज ने एमकेपी की स्थापना कांग्रेस के आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कांग्रेस में सही लाइन तथा पार्टी के भीतर एक मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी समझदारी को विकसित करने में उनकी यादगार भूमिका रही. पहली कांग्रेस के बाद से कॉमरेड कांगोज पार्टी को पुनः संगठित व मजबूत बनाकर जनयुद्ध के संचालन में एक उछाल लाने की कोशिशों में सरगर्मी से जुटे हुए थे. कॉमरेड कांगोज और अन्य वरिष्ट कॉमरेडों की मौत तुर्की की क्रान्ति के साथ-साथ विश्व क्रान्ति के लिए एक बड़ा नुकसान है. लेकिन वे बेकार की मौत नहीं मरे. उनकी कुरबानियों की राह में लाखों तुर्कीवासी संघर्ष में आगे बढ़ेंगे – तुर्की की प्रतिक्रियावादी सरकार को दफना देंगे.

माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना नवम्बर 2003 में हुई थी, जिसे पहले टीकेपी (एमएल) के नाम से पुकारा जाता था. यह हमला तुर्की में माओवादियों के खिलाफ खासतौर पर पिछली सर्दियों से जारी व्यापक दमन की कड़ी है. पिछली सर्दियों में फासीवादी सरकार ने फौजी बलों और जन सेनाओं 'टिक्को' (जोकि एक और माओवादी पार्टी टीकेपी/एमएल के मातहत है) और पीएलए (एमकेपी की अगुवाई में काम करने वाली जन मुक्ति सेना) के बीच खासकर तुर्की-कुर्दिस्तान के देर्सिम इलाके में कई मुठभेड़ें हुई थीं. एमकेपी के करीब 20 छापामार शहीद हो गए. तुर्की की कम्युनिस्ट पार्टी/मार्क्सवादी-लेनिनवादी (टीकेपी/एमएल) के तीन छापामार – कॉमरेड केफर कारा, एपकीन ग्युनेल और मुहारेम इडिटसोय देर्सिम में हुई मुठभेड़ों में शहीद हो गए थे. समूची सर्दियों के दौरान तुर्की-कुर्दिस्तान के कई क्षेत्रों में हमले किए गए. हकारी में पीकेके के कई छापामारों की हत्या कर दी गई.

भाकपा (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी तुर्की में हुए इन हत्याकाण्डों की जमकर निंदा करती है. हम समूची जनता का आह्वान करते हैं कि तुर्की के इन बहादुराना शहीदों को याद करें और तुर्की सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करें. हम तुर्की की माओवादी पार्टियों, शहीदों के परिजनों और तुर्की की जनता, जिन्होंने अपने साथी खोए हैं, के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं. हम अपना संकल्प फिर एक बार दोहराते हैं कि फासीवादी सरकार के खिलाफ लड़ रही तुर्की की जनता के पक्ष में हम हमेशा मजबूती के साथ खड़ें रहेंगे. ✶

गुड़गांव में होंडा कम्पनी के मजदूरों पर पाशविक हमला

25 जुलाई को हरियाणा के गुड़गांव स्थित होंडा मोटारसायकिल्स एण्ड स्कूटर्स प्रा.लि. नामक जापान की बहुराष्ट्रीय कम्पनी के मजदूरों पर पुलिस बलों ने बेहद बर्बरतापूर्ण हमला किया. इसमें सैकड़ों मजदूर बुरी तरह घायल हो गए. एक विदेशी कम्पनी के मुनाफे के लिए साम्राज्यवाद–प्रेमी भारतीय शासक वर्ग किस हद तक क्रूरता बरत सकते हैं, इसका यह एक उदाहरण है.

भारत के मजदूर वर्ग समेत तमाम जन समुदायों ने इस हमले की कड़ी निंदा की. होंडा मजदूरों के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया. देश भर में आए विरोध से डरकर सरकार को मजदूरों की समस्याओं का हल करने पर बाध्य होना पड़ा.

आइए, इस पाशविक हमले के कारणों पर गौर करें –

जापान की इस होंडा कम्पनी में लगभग 3,000 मजदूर काम करते हैं. उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आइटीआइ व डिप्लोमा कोर्स पूरा कर इसमें शामिल हो गए हैं. वे इस आस में कड़ी मेहनत करते हैं कि कम्पनी अपने वादे के मुताबिक दो साल में उन्हें पर्मनेन्ट कर देगी. मजदूर रोजाना 8 घण्टे काम करते हैं जिसमें 10 मिनट का चाय विराम और आधे घण्टे का भोजन विराम मिलता है जोकि काफी कम है. मजदूरों को मालिकों द्वारा इतना तंग किया जाता है कि शौचालय के दरवाजे भी इसलिए हटा दिए गए ताकि मजदूरों पर हर पल नजर रखी जा सके. यहां तक कि महिला मजदूरों के शौचालयों के भी दरवाजे हटा दिए गए जिससे उन्हें बेहद अपमान सहना पड़ता है. थोड़ी सी गलती पर मजदूरों को थप्पड़ या घूंसा मारना यहां आम बात है. एक बार एक सिख मजदूर को मारा तो उसकी पगड़ी नीचे गिर गई थी. इस प्रकार कम्पनी प्रबन्धन मजदूरों के साथ गुलाम से भी बदतर बरताव कर रहा था, जिसकी कल्पना एक उपनिवेशी देश में ही की जा सकती है.

ऐसे हालात के बीच दिसम्बर 2004 में कम्पनी के मैनेजर और मजदूरों के बीच झगड़ा हुआ था. मैनेजर ने एक मजदूर को मारा तो तमाम मजदूरों ने उसका विरोध किया था. इससे उस अधिकारी को मजदूरों से माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा. लेकिन प्रबन्धन के खिलाफ मजदूरों के दिल में गुस्सा बरकरार था.

दरअसल यह संघर्ष कम वेतनों के कारण शुरू नहीं हुआ था. मजदूरों का सब्र का बांध तब टूटा था जब कम्पनी ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले 2,000 मजदूरों को पर्मनेन्ट न करते हुए दोबारा नई भर्ती के रूप में 2 साल और प्रशिक्षण लेने का आदेश जारी किया था. इस प्रकार कम्पनी मजदूरों को कम वेतन देकर ज्यादा काम करवाना चाहती थी. अगर उन्हें पर्मनेन्ट करेगी तो उसे पेन्शन व वेतनमान आदि देना होगा. यह मजदूरों की श्रमशक्ति से अत्यधिक मुनाफे लूटने की चालबाजी है. अत्यधिक मुनाफे के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बीच मची होड़ के चलते उत्पादन के खर्चों को कम करने की मंशा से मजदूरों को सबसे पहले निशाना बनाया जा रहा है. कम वेतन, छंटनी, अस्थाई नौकरी के साथ–साथ यूनियनों को अनुमति न देना तथा श्रम कानूनों के अमल को रोकना आदि हथकण्डे अपनाए जा रहे हैं.

प्रबन्धन द्वारा अपनाई जा रही मजदूर विरोधी नीतियों को संगठित रूप से मुकाबला करने हेतु मजदूरों ने यूनियन बनाने का फैसला किया. यह प्रबन्धन को बर्दाश्त नहीं था. यूनियन के पंजीकरण होने से पहले ही इस वर्ष 30 मई को प्रबन्धन ने 4 मजदूरों को नौकरी से हटाकर 13 मजदूरों को निलम्बित किया था. यह मजदूरों के साथ घोर अन्याय था.

इसके खिलाफ फैक्टरी गेट के सामने मजदूरों ने धरना दिया तो प्रबन्धन ने तालाबन्दी की घोषणा की. इस अवैध तालाबन्दी के खिलाफ 3,000 मजदूरों ने गुड़गांव के कमला नेहरू पार्क में रैली निकालने के इरादे से इकट्ठे हुए थे. इनकी मदद में गुड़गांव के आसपास स्थित कम्पनियों तथा पंजाब से भी सैकड़ों मजदूर आए हुए थे. रैली शांतिपूर्वक चल रही थी, फिर भी पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज शुरू किया. इससे कुछ प्रदर्शनकारी भाग गए, जबकि कुछ लोग घायल हो गए. मजदूरों को मजबूर होकर प्रतिरोध का रास्ता अपनाना पड़ा. उन्होंने जुल्मी पुलिस वालों से जमकर लोहा लिया. एक सरकारी वाहन को आग लगा दी और एक पुलिस अधिकारी को घायल किया.

चार घण्टे बाद गुड़गांव उप आयुक्त सुधीर राजपाल यूनियन नेताओं को चर्चा के बहाने मिनी सेक्रटेरियट में बुलाया. यूनियन के नेता जब मजदूरों के साथ वहां पहुंचे तो पुलिस ने सोची–समझी साजिश के तहत अचानक लाठीचार्ज शुरू कर बेहद क्रूरता से मारा. इसमें कुछ मजदूरों के सिर फूट गए तो कुछ लोगों के हाथ–पैर टूट गए. इस बर्बर कार्रवाई में हरियाणा रिजर्व पुलिस पोर्स, फायर ब्रिगेड, रैपिड एक्शन पोर्स और आसपास के थानों के पुलिस बलों ने भाग लिया. मजदूरों को जिस तरह घेरकर पाशविक तरीके से हमला किया गया, इसकी तुलना जलियांवाला बाग से ही की जा सकती थी. उलटे पुलिस ने मजदूरों पर यह आरोप लगाया कि यह कार्रवाई उसे इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मजदूरों ने बरछी, सलिया, आदि हथियारों से हमला करने की कोशिश की थी.

पुलिस ने कुल 400 लोगों को गिरफ्तार किया. घायल मजदूरों को अस्पतालों में भर्ती कराकर इलाज करवाने की बजाए हवालात में डाल दिया. परिवार जनों और कुछ राजनीतिकों के दबाव के चलते बाद में कुछ लोगों को आस्पताल में भर्ती करवाया गया. एक–एक बिस्तर पर दो–दो मरीजों को लिटाया गया. गिरफ्तार लोगों को दूर–दूर के थानों में रख दिया गया. कुछेक लोगों का कोई पता तक नहीं मिला. उनकी पतासाजी करने गए रिश्तेदारों की भी पुलिस ने पिटाई की. यह 'आजाद' भारत के इतिहास में अत्यंत पाशविक कार्रवाई है जिसे सरकार ने एक साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के हित में मजदूरों के खिलाफ अंजाम दिया.

इस घटना ने मजदूरों के प्रति व्यापक जन समर्थन जुटाया. आम जनता, रिश्तेदार और अन्य मजदूरों ने होंडा कम्पनी के मजदूरों के प्रति समर्थन प्रकट किया.

यह अचानक घटी घटना नहीं है. पूरे गुड़गांव क्षेत्र के मजदूरों के असन्तोष की यह एक अभिव्यक्ति थी. गुड़गांव और दलहेरा औद्योगिक गलियारे के इतिहास पर नजर डाली जाए तो ऐसी कई घटनाओं का पता चलता है जिसमें यूनियन के पंजीकरण के लिए दरख्वास्त करने वाले मजदूरों को काम से निकाल दिया गया हो. इतना ही नहीं. यूनियन की गतिविधियों में थोड़ी–बहुत दखल रखने पर भी किसी भी समय मजदूरों के घरों पर हमला कर परिवार जनों व मजदूरों की पिटाई करना, गैर–कानूनी तरीके से हफ्तों तक लॉकप में रखना, आदि घटनाएं यहां आम हैं. जब बंसीलाल मुख्यमंत्री था, तभी से हरियाणा को विदेशी पूंजी के लिए एक सुरक्षित जगह में तब्दील करने की कवायद शुरू हो

गई. यूनियन नहीं बनाना, मजदूर संघर्ष का नाम नहीं लेना – आदि नीतियों पर क्रूरता से अमल किया जाता रहा. विदेशी पूंजी के हित में मजदूरों के हितों की बलि दी जाने लगी. सरकारें विदेशी कम्पनियों के वफादार सेवक की भूमिका निभाती आ रही हैं. औद्योगिक विकास के नाम पर सरकारें पिछले 30 सालों से मजदूरों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग करते हुए खून बहाती आ रही हैं.

गुड़गांव घटना के बाद घायल मजदूरों से ज्यादा सरकार को विदेशी पूंजी के बहाव रुक जाने की चिन्ता सताने लगी. भारत में स्थित जापानी राजदूत ने तुरन्त ही यह चेतावनी दी कि गुड़गांव की घटना के बाद भारत में विदेशी निवेश पर बुरा असर पड़ेगा. उसने यह चेतावनी इसलिए दी ताकि सरकार मजदूरों का पक्ष लेकर कम्पनी के खिलाफ कोई कदम न उठा सके.

3 अगस्त को ट्रेड यूनियन नेताओं से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हिदायत दी – ''औद्योगिक शांति काफी महत्वपूर्ण विषय है. विदेशी कम्पनियों को मजदूरों की मांगों के सामने झुकने पर मजबूर नहीं करना चाहिए. ऐसा करने पर विदेशी निवेशकों को यह संदेश जाएगा कि भारत पूंजीनिवेश के लिए अस्थिर क्षेत्र है, अतः विदेशी निवेशक यहां पूंजी लगाने से हिचकिचाएंगे.'' उसके साम्राज्यवाद–अनुकूल चरित्र को समझने के लिए इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए?

वास्तव में जहां मुनाफा मिलने की गारन्टी रहेगी वहां विदेशी पूंजी जरूर बहकर आती है. भारत जैसे देश में लूटने के लिए अपार प्राकृतिक सम्पदाएं और सस्ती श्रमशक्ति हैं. इससे साम्राज्यवादी कम्पनियां बेहिसाब मुनाफा प्राप्त करना चाहती हैं. इस लूटखसोट को बेरोकटोक जारी रखा जा सके, इस हेतु भारत सरकार ने विश्व बैंक व विश्व व्यापार संगठन द्वारा थोपी गई तमाम शर्तों को मान लेते हुए कई प्रकार के वित्तीय जोन बनाए हैं. ऐसे जोनों में भारत सरकार का कोई भी कानून लागू नहीं होता. इसके अलावा देश में मौजूद मजदूर कानूनों में व्यापक फेरबदल कर मजदूरों को न्यूनतम अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है. मजदूरों को कुचलने हेतु सरकार ने कई किस्म के काले कानून लाए. अगर मजदूर अपने अधिकारों के लिए या अपनी जीवन स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आन्दोलन करते हैं तो सरकार उन्हें क्रूरता से कुचलने व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों की रक्षा करने की हामी भर रही है. मनमोहन की उपरोक्त हिदायत को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए.

भारत में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के नाम पर सरकार विदेशी कम्पनियों को तमाम नियम–कायदों का उल्लंघन करने की छूट दे रही है. देश की संप्रभुता के लिए यह एक कलंक है. विदेशी पूंजी के हित में सरकार काम करते हुए साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और दलाल पूंजीपतियों की इजारेदार कम्पनियों को फायदा पहुंचा रही है. विडम्बना यह है कि राज्य और पूंजी का यह गिरोह यह सब जनता और रोजगार के नाम पर कर रहा है.

''विदेशी पूंजी निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे – उसके रुक जाने से बेरोजगारी बढ़ेगी'' कहकर सरकारें विदेशी पूंजी का गुणगान करते नहीं थक रही हैं. लेकिन सचाई इसके बिलकुल उलट है. मिसाल के तौर पर जब हिन्दुस्तान लिवर कम्पनी का लक्मे कम्पनी में विलय हुआ तब करीब 3,500 कर्मचारियों का रोजगार छिन गया था. कई सार्वजनिक कम्पनियों का जब निजीकरण किया गया तब कई मजदूरों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा. छत्तीसगढ़ में बाल्को को एक निजी कम्पनी को कौड़ियों के दाम बेचने के बाद भी सैकड़ों मजदूरों को वीआरएस और छंटनी की योजनाओं के तहत छुट्टी दे दी गई. अत्यधिक मुनाफों के लिए उद्योगों का मशीनीकरण करने से भी कई मजदूरों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ रही है. इसके अलावा, कई बड़ी इजारेदार कम्पनियों की स्पर्धा के कारण कई छोटे उद्योग बन्द पड़ गए जिससे लाखों मजदूर बेरोजगार बन चुके हैं. यही वजह है कि आज अत्यधिक लोग साम्राज्यवाद–विरोधी संघर्षों में आगे आ रहे हैं. सरकार द्वारा लागू जन विरोधी नीतियों का मुकाबला करने हेतु वे रोज–ब–रोज वे ज्यादा जुझारू ढंग से संघर्षों में उतर रहे हैं.

दिल्ली के नजदीक होने के कारण गुड़गांव की घटना पर मीडिया का कवरेज अधिक रहा. इससे मजदूर अधिकारों का मामला देश भर में एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया. इसलिए 25 जुलाई को इसका सारा दोष मजदूरों के सिर मढ़ने वाले हरियाणा मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने बाद में जनता के विरोधी तेवर को देखकर अपना बयान बदला. बरखास्त किए गए तमाम मजदूरों को काम पर लेने को कहने के साथ–साथ यह भी कहा कि कानून अपना काम करेगा. क्या कानून को इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार कम्पनी प्रबन्धन व पुलिस–प्रशासन को सजा देने की कोई जरूरत नहीं है? पबन्धन की रक्षा करने वाली सरकार ऐसा नहीं कर सकती, बल्कि उसके अन्ततः मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई करने की सम्भावना अधिक है. बाद में हुए समझौते में मजदूरों को यह लिखित सहमति देनी पड़ी कि वे एक साल तक (अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी सही) अनुशासन का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा फैक्टरी में सामान्य उत्पादन को नुकसान पहुंचने नहीं देंगे.

हालांकि यह आन्दोलन फिलहाल विदेशी पूंजी के सामने सरकार की सेवक भूमिका का पर्दाफाश करने में तो कुछ हद तक सफल हुआ ही, पर इससे बढ़कर इसने मजदूरों के संगठित रूप से संघर्ष करने की जरूरत को रेखांकित किया है.

इस घटना के संदर्भ में संसदीय पार्टियों का दिवालियापन नंगे तौर पर सामने आया. हालांकि विपक्ष में रहकर सभी पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए सत्ता पक्ष को घेरने की नीति अपनाती हैं, पर सत्ता में आने के बाद सभी पार्टियां मजदूर विरोधी व साम्राज्यवाद अनुकूल नीतियों पर ही अमल करती हैं. भाकपा/माकपा संशोधनवादियों ने इस पर संसद में हंगामा तो मचाया, पर साम्राज्यवाद–परस्ती नीतियों के प्रति उनका रुख भाजपा–कांग्रेस से अलग नहीं है. पश्चिम बंगाल का 'मार्क्सवादी' मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने तो यह भी कह डाला कि जापान को अपनी पूंजी को लेकर चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है. वह गुड़गांव में केन्द्रित काल सेन्टरों और विदेशी पूंजी को पश्चिम बंगाल में आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है. यानी 'मार्क्सवादियों' को गुड़गांव की तर्ज पर पुलिसिया आतंक मचाने में कोई एतराज नहीं है. वे विदेशी पूंजी की वफादार कुत्तों की तरह सेवा करने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं.

गुड़गांव जैसी घटनाओं से भारत के मजदूरों और अन्य शोषित तबकों को यह शिक्षा मिलती है कि विदेशी पूंजी के हमले को परास्त करने तथा उसकी रक्षा करने वाली सरकारी नीतियों को रद्द करवाने हेतु एक व्यापक जन संघर्ष छेड़ने की जरूरत है. मजदूर वर्ग को अपने आन्दोलन को गद्दार नेतृत्व से बचाना चाहिए. उसे सम्पूर्ण मानवजाति की मुक्ति के लक्ष्य से अन्य तमाम शोषित तबकों को – खास तौर पर किसानों को साथ लेकर अपनी ऐतिहासिक कार्यभार पूरा करने की दिशा में नव जनवादी क्रान्ति के रास्ते पर कदम बढ़ाना चाहिए. ✶

छत्तीसगढ़ को दलाल व विदेशी पूंजीपतियों की लूट का चरागाह बनाने की साजिश

छत्तीसगढ़ प्रदेश असीम जल, वन व खनिज संपदाओं से भरपूर एक समृद्ध राज्य है. यहां पर देश का 99.93 प्रतिशत टिन अयस्क (देश में पहला स्थान), 16.10 प्रतिशत कोयला, 18.96 प्रतिशत लौह अयस्क (देश में तीसरा स्थान) और 50 प्रतिशत हीरा मौजूद हैं. देश के तमाम जंगलों का 12 प्रतिशत इसी राज्य में है – देश में इसका तीसरा स्थान है. 28 कीमती खनिजों की उपलब्धता से छत्तीसगढ़ की गिनती समृद्ध राज्यों में होती है. इसके अलावा यहां पर 46,600 करोड़ क्यूबिक मीटर जल संसाधनों का भण्डार तथा अपार मानव श्रमशक्ति मौजूद हैं.

यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पर बड़े उद्योगपतियों और विदेशी कम्पनियों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है. भाजपा मुख्यमंत्री रमन सिंह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में छत्तीसगढ़ में मौजूद सम्पदाओं की बेहद सस्ते में बोली लगाते हुए एक मंजे हुए दलाल या सेल्समैन की भूमिका निभा रहा है. प्रदेश में विदेशी पूंजी लगाने का न्यौता लेकर वह अमेरिका व कनाडा का दौरा कर आया. बाद में मंत्रीमण्डल की बैठक बुलाकर विदेशी पूंजी के आगमन को अपनी कामयाबी बताई.

अमेरिकी कम्पनी टेक्सास पावर जेनरेशन द्वारा राज्य में 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने वाला संयंत्र खोलने के लिए सहमति–पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया. अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित ग्लोबल वन इंकार्पोरेट कम्पनी ने 50 करोड़ रुपए की पूंजी से दवा फैक्यरी लगाने की इच्छा जताई.

छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड ने इफ्को (इंडियन फॉर्मर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड) के साथ मिलकर 4,500 करोड़ रुपए की पूंजी से सरगुजा में 1000 मेगावाट का बिजली संयंत्र लगाने का समझौता किया. इसमें इफ्को का हिस्सा 74% है जबकि राज्य बिजली बोर्ड का हिस्सा 26% है. अब जबकि राज्य बिजली बोर्ड का ही निजीकरण करने की तैयारियां चल रही हैं तो इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि बाद में इसे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बेचा जाएगा.

टाटा की स्टील कम्पनी – टिस्को विश्व बैंक की मदद से 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बस्तर में स्टील प्लान्ट स्थापित करने जा रही है. इसके लिए जगदलपुर के आसपास 4 स्थानों पर जमीन का आवंटन किया गया. कई गांवों को उजाड़कर ग्रामीणों को विस्थापित किया जाएगा. लोगों को अपनी खेत–जमीनों से हाथ धोना होगा. इस संयंत्र के लिए शबरी नदी पर बांध बनाकर वहां से पानी की आपूर्ति की जाने का प्रस्ताव है.

बस्तर में ही एक और स्टीलप्लान्ट की स्थापना एस्सार कम्पनी करने जा रही है. इसकी लागत 7 हजार करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है. इस स्टील प्लान्ट की उत्पादन क्षमता सालाना 30 लाख 20 हजार टन होने का अनुमान है. यह कम्पनी 4,000 करोड़ रुपए की पूंजी से कॉस्टिव पावर प्लान्ट की भी स्थापना करेगी.

प्रकाश स्पंज आयरन लिमिटेड के साथ कोरबा में कोयला खदान खोलने का सहमति–पत्र हस्ताक्षरित किया गया. इसी कम्पनी के चम्पा में स्थित स्टील प्लान्ट के लिए जरूरी कोयले की आपूर्ति इस खदान से का प्रस्ताव है. इसके लिए किसानों की 231 हेक्टेयर जमीन, 57 हेक्टेयर सरकारी जमीन और 806 हेक्टेयर वन भूमि सरकार ने आवंटित की. इससे कुल 6 गांव प्रभावित हो जाएंगे. 50 हजार पेड़ों की हत्या की जाएगी.

इसके अलावा कई अन्य सहमति–पत्रों को अन्तिम रूप देने की बात चल रही है. ये सभी करार राज्य को विकसित करने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के बहाने किए जा रहे हैं. इस तरह का औद्योगिक विकास जनता के विकास के लिए नहीं, बल्कि उसके विनाश के लिए ही है. किसानों की सैकड़ों–हजारों एकड़ जमीनें हड़पकर, कई गांव उजाड़कर, उन्हें सही व सम्मानजनक वैकल्पिक रोजगार मुहैया किए बिना ही सिर्फ बड़े व विदेशी पूंजीपतियों के फायदे के लिए ये सारे काम हो रहे हैं या होने जा रहे हैं. यहां के कीमती प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने वाले ये तमाम करार जनता के हित में कतई नहीं हैं. यह बात आए दिन साबित हो रही है.

2002 में नगरनार स्टील प्लान्ट के निर्माण के लिए सरकार ने लाठी और गोली के बल पर 303 किसानों की पट्टा जमीनें छीनी थीं. पर इसमें सिर्फ 100 किसानों को ही नौकरी मिली. (यह बात दीगर है कि ये तमाम

पानी की लूट से पलायन की मजबूरी

नगरनार स्टील प्लान्ट, टिस्को, एस्सार पाइपलाइन परियोजना (बैलाडीला से जापान को पानी के जरिए लौह चूर्ण भेजने वाली परियोजना) – इन सभी से बस्तर में मौजूद जल संपदा का अंधाधुंध दोहन किया जाएगा. जहां बस्तर की जनता सिंचाई सुविधाओं के अभाव से जूझ रही है, वहीं यहां की नदियों का पानी साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के फायदे के लिए बहाया जाने वाला है. सरकार यहां के किसानों के प्रति घोर लापरवाही बरत रही है. इससे फसलें चौपट हो रही हैं और कई किसान पेट पालने के लिए पलायन कर रहे हैं. दिल्ली जैसे शहरों में गगमचुम्बी इमारतों का निर्माण तथा जम्मू–कश्मीर में सड़क निर्माण, फरीदाबाद की ईंट भट्टियों में छत्तीसगढ़वासी अपनी श्रमशक्ति सस्ते में बेचकर जीने को मजबूर हैं. अब शासकों की इन दिवालिया नीतियों से पलायन की स्थिति और भी भयावह रूप धारण कर सकती है.

साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण का सिलसिला शुरू होने के बाद लघु उद्योगों की घोर उपेक्षा की जा रही है. सरकार ने बैंकों को इन उद्योगों को ऋण न देने का आदेश दिया है. छोटे व लघु उद्योगों के अखिल भारतीय महासंघ के अध्यक्ष सुदर्शन सरीन ने यूं कहा –

''देश में 1,18,000 लघु उद्योग मौजूद हैं. ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के बराबर हैं. इनसे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है. फिलहाल जितनी सुविधाएं बड़े उद्योगों को दी जा रही हैं उतनी लघु उद्योगों को देने से देश की काफी तरक्की हो सकती है.''

बैलाडीला की लूट

बैलाडीला खदानों से जो लोहा निकालता है उसे जापान को 160 रुपए प्रति टन (16 पैसे प्रति किलो) के भाव से बेचा जाता है. दूसरी तरफ बड़ी कम्पनियों (मुम्बई के उद्योगों) को 450 रुपए प्रति टन तथा छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों को 1600 रुपए प्रति टन के हिसाब से बेचा जाता है. जापान के भाव से 10 गुना अधिक भाव से बेचना सरकार के साम्राज्यवाद–प्रेम का एक उदाहरण भर है.

किसी भी प्रभुसत्ता सम्पन्न देश को चाहिए कि वह खासकर लोहा जैसे खनिज भण्डारों का संरक्षण करते हुए उनका सदुपयोग कर समाज की आर्थिक तरक्की की ओर कदम बढ़ाए. लेकिन यहां की 'लोकतांत्रिक' सरकारें साम्राज्यवादियों के मुनाफे के लिए इनकी खुल्लमखुल्ला लूट की छूट देकर देश के हितों के साथ गद्दारी कर रही हैं. खुद टिस्को के प्रबन्ध निदेशक मुत्तुरामन के ही शब्दों में, ''लोहे का निर्यात देश के हित में नहीं है. भारत में लौह खनिज का भण्डार सिर्फ 18 अरब टन का है. सालाना जरूरत 3 करोड़ टन की है. इस हिसाब से अगले 55 सालों में लोहा खत्म हो जाने की पूरी सम्भावना है. अगर निर्यात को न रोकेंगे तो 30–35 सालों में यह खत्म हो जाएगा. बाद में हमें उन्हीं देशों से लोहा आयातित करना पड़ेगा जिन्हें अब हम निर्यात कर रहे हैं.''

सचाई यह है कि जापान में लोहे के अपार भण्डार होने के बावजूद सस्ते में मिलने की वजह से यहां से लूटकर ले जा रहे हैं. जापान में इसे रखने की जगह ही नहीं है, इसलिए इसे समुद्र में डम्प किया जा रहा है. बैलाडीला से सालाना 1 करोड़ टन लोहा आयातित किया जाता है. पिछले साल 5 करोड़ टन का लोहा बेचा गया था. इस साल 10 करोड़ टन का लोहा बेचने का लक्ष्य रखा गया.

भिलाई स्टील प्लान्ट के लिए अब तक दल्ली–राजहरा की खदानों से लोहे की आपूर्ति की जाती रही. लेकिन शासकों की दिवालिया औद्योगिक नीतियों के चलते वे अब लगभग कंगाल हो चुकी हैं. अब इसके बदले में सरकार रावघाट और चारगांव के पास खदानें शुरू करके हजारों जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है. दूसरी तरफ बैलाडीला खदानों से जिस तेजी से और जितने सस्ते में जापान और दक्षिण कोरिया को लोहा बेचा जा रहा है, इससे अगले कुछ सालों में उनके भी कंगाल होने के पूरे आसार हैं. भिलाई स्टील प्लान्ट के लिए रावघाट व चारगांव में खदानें खोलने की जरूरत पर जोर देने वाले शासक और उनके सुर में सुर मिलाने वाले अन्य प्रबुद्ध लोग बैलाडीला से लोहे के निर्यात को बन्द करने की मांग क्यों नहीं करते? इससे क्या यह बात साफ नहीं हो जाती कि हमारे देश की सभी सरकारें साम्राज्यवादियों और दलाल पूंजीपतियों के तलवे चाटते हुए देश को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं?

नौकरियां कुली, कलासी, वाचमैन, चपरासी जैसी निम्न श्रेणी की ही होंगी). बाकी 203 किसानों को अंगूठा दिखाया गया. जब तक काम शुरू हो जाएगा तब तक ये नौकरियां रह पाएंगी, इसकी भी कोई गारन्टी नहीं है. अब तो स्टील प्लान्ट के निर्माण का काम लगभग ठप्प हो गया. सैकड़ों–हजारों लोगों की जिन्दगी तबाह करके उन्हें अपनी प्राकृतिक सम्पदाओं से हमेशा के लिए वंचित करके 'विकास' कैसे हासिल किया जाएगा – यह समझ से परे है.

अब चूंकि सरकार टिस्को कम्पनी के लिए कुल चार जगहों पर जमीन आवंटित की. इससे हजारों लोगों को बेघरबार होना पड़ सकता है. सरकार हर परिवार में एक को रोजगार व एक–एक मकान देने की बात कह रही है. कोरबा में भी कोयला खदान के चपेट में सैकड़ों एकड़ सरकारी व वन भूमि के अलावा किसानों की 231 हेक्टेयर जमीन व 6 गांव आने वाले हैं. सम्भव है कि इनमें से कुछ लोगों को खदानों में मजदूरी काम मिल जाए. पर क्या खेती पर निर्भर किसान का पूरा परिवार किसी एक व्यक्ति की नौकरी से पल सकता है? खेतीबाड़ी पर निर्भर कर जीने वाले अन्य पेशे के लोगों की खोई हुई जीविका की भरपाई सरकार कैसे करेगी?

दूसरी तरफ इन बड़ी कम्पनियों के कारण छोटे व मध्यम उद्योग चौपट हो रहे हैं. इससे हजारों–लाखों लोग नौकरी से हाथ धोने लगे हैं. भूमण्डलीकरण की नीतियों के लागू होने से पहले सरकार छोटे व मध्यम उद्योगों को 80% बैंक ऋण दिया करती थी. इसके अलावा इन उद्योगों में तैयार की जाने वाली वस्तुओं को बड़े उद्योगों में बनाने पर पाबन्दी थी. लेकिन अब साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण की नीतियों के तहत छोटे उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों को 10% कर दिया गया. छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी कम्पनियों के प्रवेश से छोटी फैक्टरियां बन्द होती जा रही हैं.

जहां एक तरफ टिस्को, एस्सार जैसी बड़ी कम्पनियों के लिए लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने बिजली की कीमतें बढ़ाकर 110 छोटे इस्पात संयंत्रों के लिए संकट की स्थिति पैदा कर दी. इन उद्योगों के मालिकों ने बढ़ी हुई दरों के मद्देनजर फैक्टरी चलाने में अपनी असमर्थता जाहिर कर उन्हें बन्द करने की चेतावनी दी. छोटे इस्पात कारखानों के लिए सरकार कच्चामाल की कीमतें

बिजली उत्पादन के क्षेत्र में रमन सरकार की नाकामी

छग राज्य के गठन के समय बिजली की मांग 900 मेगावाट थी, जबकि बिजली उत्पादन 1300 मेगावाट था. रमन सरकार के गठन के बाद अब मांग 2000 मेगावाट हुई है, जबकि उत्पादन 1000 मेगावाट तक घट गया.

बिजली की मांग पूरी करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के बजाए सरकार अब बड़े पूंजीपति जिन्दल की कम्पनी से बिजली खरीद रही है. सेन्ट्रल पूल से प्रति यूनिट 1.70 रू. के हिसाब से बिजली मिलती है जबकि रमन सरकार जिन्दल ग्रुप को प्रति यूनिट 2.32 रु. के हिसाब से भुगतान कर रही है. इससे जनता पर रोजाना 50 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है.

जिन्दल ग्रुप का मुखिया ओ.पी. जिन्दल की हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मौत होने के समय वह हरियाणा में बिजली मंत्री के पद पर था. देश भर में इस समूह के कई उद्योग हैं और अमेरिका में दो इस्पात संयंत्र हैं. इससे बड़े पूंजीपतियों के प्रति रमन सरकार का प्रेम साफ जाहिर होता है.

बढ़ाकर बाजार में उत्पादों की कीमतें बढ़ने का कारण बन रही है. इससे उनके अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगने लगा है.

देश में पेप्सी व कोकाकोला कम्पनियों के प्रवेश के बाद से देशीय शीतल पेय कम्पनियां लगभग खत्म हो चुकी हैं. नमक के उत्पादन के क्षेत्र में भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने घुसपैठ कर सरकार को अपनी मुट्ठी में रखकर नमक पैदा करने वाले छोटे उत्पादकों को भगा दिया. इसके लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने मीडिया का भी जमकर दुरुपयोग किया. जहां छोटे उत्पादक 50 पैसे में किलो नमक बेचा करते थे, वहीं आज टाटा जैसी बड़ी कम्पनियां 7 रुपए प्रति किलो नमक बेच रही हैं. किसी भी क्षेत्र में छोटे कारखानों के बन्द हो जाने से बेरोजगारी बढ़ती है. बड़े उद्योगों के आने से रोजगार के अवसर बढ़ने का दावा झूठा है, इसके कितने भी उदाहरण गिनाए जा सकते हैं.

देश का औद्योगिक विकास होना बहुत जरूरी है. लेकिन यह विकास आत्मनिर्भरता पर आधारित और यहां के हालात के अनुकूल होना चाहिए. अपार आबादी वाले इस देश में औद्योगीकरण ऐसा होना चाहिए जोकि सभी को रोजगार के अवसर दे. यह छोटे व मध्यम उद्योगों से ही सम्भव है – न कि बड़ी व विदेशी कम्पनियों से. अत्यधिक लोगों को रोजगार मिलने पर ही उनकी क्रयशक्ति बढ़ जाएगी. उससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. बड़ी व विदेशी कम्पनियां अत्याधुनिक तकनीकी पर निर्भर करती हैं. उसमें रोजगार के अवसर कम मिलते हैं. हमारा देश कृषि प्रधान देश है, अतः सामन्तवाद के बोलबाले के चलते अत्यधिक किसानों की क्रयशक्ति बेहद कम है. देश में जारी हथियारबन्द कृषि क्रान्तिकारी गुरिल्ला युद्ध ही इसका सफाया कर सकता है. वर्तमान सरकारें सामन्तवाद, साम्राज्यवाद और दलाल पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं. यही तीन वर्ग भारत के तमाम शोषित जन समुदायों के दुश्मन हैं. इन दुश्मनों को उखाड़ फेंकने हेतु जारी नव जनवादी क्रान्ति में देश के तमाम मजदूर–किसानों तथा छोटे व मध्यम पूंजीपतियों को एकजुट होकर लड़ना चाहिए.

आज देश तथा छत्तीसगढ़ में विदेशी पूंजी की घुसपैठ के खिलाफ जनता को पुरजोर आवाज उठाने की जरूरत है. खासकर छत्तीसगढ़ के जल, वन, खनिज सम्पदाओं की लूट तथा जनता के विस्थापन व पर्यावरण की क्षति को रोकना हर देशभक्त का अहम कर्तव्य है. इसके खिलाफ लड़ने वाले लोगों को 'विकास' विरोधी कहना एक बहुत बड़ी साजिश है. 'विकास' की अवधारणा से उनका मतलब है बड़े पूंजीपतियों का विकास. इस तथाकथित व ढोंगी 'विकास' के खिलाफ लड़ने वालों पर सरकारें काले कानूनों का प्रयोग कर रही हैं. बस्तर में क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ 'जन जागरण' अभियान के नाम पर छेड़ा गया पासीवादी दमन अभियान भी इसी की कड़ी है. बस्तर को बड़ी व विदेशी कम्पनियों की लूट का चरागाह बनाने की राह में यहां पर जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन को देश के दलाल शासक वर्ग बहुत बड़ी बाधा के रूप में देख रहे हैं. इसलिए लुटेरे शासक वर्गों के तमाम हथकण्डों को नाकाम बनाते हुए देश में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की नींव डालने की ओर हमें कदम बढ़ाना चाहिए, जोकि नव जनवादी व्यवस्था के तहत ही सम्भव है. ✶

(..... पेज 39 का शेष)

पश्चिम बस्तर डिवीजन

पश्चिम बस्तर डिवीजन में 'जन जागरण' अभियान के नाम से जारी फासीवादी हमले के बीचोबीच ही जनता ने जन संगठनों के नेतृत्व में कई जगहों पर सभाओं का आयोजन किया. मद्देड़ इलाके के पुन्नूर में आयोजित सभा में 200 लोगों ने भाग लिया. पटनम इलाके के चिर्राकुंटा, गोरुगोंडा, मूंजालकांकेर, बंडारुपल्ली, भीमनपल्ली, पूसूगुडा में आयोजित सभाओं में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया. स्मारकों का अनावरण किया गया.

दक्षिण बस्तर डिवीजन

जेगुरुगोंडा और बासागूडेम इलाके में पोस्टर और पर्चों के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया. पूरे इलाके में चार जगहों पर बड़ी सभाएं हुईं. इनके आयोजन के लिए पहले ही आयोजन कमेटियों और वलन्टियर टोलियों का निर्माण किया गया.

– बिलिंगेर में आयोजित एक सभा में 15 गांवों के 1500 लोगों ने भाग लिया. इसे केएएमएस अध्यक्ष ने सम्बोधित किया.

– 30 जुलाई को लिंगगिरी में शहीद भीमन्ना के स्मारक के पास एक सभा आयोजित की गई. इसमें 25 गांवों से 2,780 लोगों ने भाग लिया. इस सभा को स्थानीय डीएकेएमएस नेता ने सम्बोधित किया.

– 31 जुलाई को शहीद मल्लेश के स्मारक के पास एक सभा हुई जिसमें 16 गांवों से 1300 लोगों ने भाग लिया. केएएमएस नेता ने इसकी अध्यक्षता की.

– 1 अगस्त को पेद्दाबोड़िकेल में कॉमरेड सुखदेव के स्मारक के पास एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया. इसमें 25 गांवों से 4,000 लोगों ने भाग लिया.

इन सभी सभाओं में लोगों ने शहीदों के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया, नारेबाजी की. सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए. पीएलजीए के आधार और माध्यमिक बलों ने इन सभाओं की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया.

किष्टारण इलाके के सिंगनमडुगु गांव में दोरनापाल में शहीद हुए कॉमरेड नंदाल का स्मारक बनाया गया. वह उसी गांव का निवासी था. 30 तारीख को वहां स्मारक का अनावरण किया गया और शहीद सभा आयोजित की गई. इसमें 2,300 लोगों ने भाग लिया. इस सभा को शहीद नंदाल के पिता ने सम्बोधित किया. उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वर्तमान लुटेरी व्यवस्था के खिलाफ लड़कर उसे ध्वस्त करना ही उसके बेटे के प्रति सच्चा सम्मान है. उन्होंने नौजवानों का आह्वान किया कि वे जनयुद्ध में बड़ी संख्या में भाग लें और जनता की राजसत्ता का निर्माण करने में योगदान करें. इस सभा को पार्टी नेताओं ने भी सम्बोधित किया.

एलमगुण्डा में आयोजित एक सभा में 1500 लोगों ने भाग लिया. गोल्लापल्ली इलाके में 700, दोरनापाल इलाके में 800 लोगोंने भाग लिया. जेगुरगोण्डा इलाके में 6,000 और बासागूड़ा इलाके में 5,000 लोगों ने सभाओं में भाग लिया. ✶

शहीदों को श्रद्धांजली देती जनता

गांव–गांव में क्रान्तिकारी जोशोखरोश के साथ मना शहीद सप्ताह

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के गठन के बाद आयोजित पहला शहीद सप्ताह दण्डकारण्य के कोने–कोने में क्रान्तिकारी उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया. खास बात यह है कि एक तरफ पश्चिम बस्तर डिवीजन में लुटेरे शासक वर्गों द्वारा छेड़े गए फासीवादी दमन अभियानों के बीच ही हजारों लोगों ने सभाओं और प्रदर्शनों में भाग लेकर अपने प्यारे शहीदों को श्रद्धांजली पेश की. हमारे पार्टी के संस्थापक नेता और पथ–प्रदर्शक कॉमरेड चारु मजुमदार और कॉमरेड कन्नाई चटर्जी समेत हजारों शहीदों को जनता ने इस मौके पर याद किया. गांव–गांव में पोस्टर, पर्चे, बैनर और दीवार लेखन के जरिए शहीदों के आदर्शों का प्रचार किया गया. खासतौर पर इस मौके पर हमारे संस्थापक नेता द्वय कॉमरेड्स चारु मजुमदार और कन्नाई चटर्जी के संघर्ष इतिहास के बारे में लोगों में बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया. इस एक साल के दौरान दण्डकारण्य में शहीद हुए एसजेडसी सदस्य कॉमरेड मंगतू के अलावा कॉमरेड्स करुणा, विनोद, सोमारी, भूमन्ना, विज्ञाल, सरिता, पूसू, नंदाल आदि सभी कॉमरेडों को श्रद्धांजली पेश की गई. आइए, इस मौके पर विभिन्न डिवीजनों में आयोजित कार्यक्रमों पर नजर डालें.

उत्तर बस्तर डिवीजन

रावघाट इलाके के चारगांव में धौड़ाई शहीदों की याद में एक स्मारक बनाया गया जिसका अनावरण 28 जुलाई को किया गया. इस मौके पर आयोजित सभा को स्थानीय पार्टी व जन संगठन कॉमरेडों ने सम्बोधित किया. नारे लगाए.

केसकोड़ी गांव में भी एक स्मारक का निर्माण किया गया. इसका अनावरण 28 जुलाई को किया गया. इस मौके पर आयोजित सभा में 250 स्त्री–पुरुषों ने भाग लिया.

केसकाल इलाके में एक सप्ताह पहले सीएनएम की पांच प्रचार टोलियों ने गांव–गांव में शहीद सप्ताह का प्रचार किया. केएमएस की चार प्रचार टोलियों तथा बाल संगठन के 2 दलों ने भी प्रचार अभियान में भाग लिया.

माड़ डिवीजन के ग्राम चिनारी में निर्मित शहीद स्मारक

इलाके में कुल 10 जगहों पर सभाओं का आयोजन किया गया. किसकोड्डो में 330, मंडानार में 360, कोटकोडो में 180, कातुलवेड़ा में 191, कुम्महानार में 191, नीब्रा में 129, कोर्रावेड़ा में 300, बुड्डालकुर्सो में 1,384, दम्सा में 2,000 और पेननार में 500 स्त्री–पुरुषों ने सभाओं में भाग लेकर शहीदों को श्रद्धांजली पेश की.

गड़चिरोली डिवीजन

अहेरी इलाके में शहीद सप्ताह का प्रचार चलाया गया. बैनर और पोस्टर लगाए गए. दीवार लेखन की गई. कई गांवों में जनता ने 28 जुलाई के दिन अपने सारे काम–धाम बन्द करके शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट किया, ऐसी उनकी परम्परा बन गई है. अहेरी इलाके में कुल दो सभाएं हुई जिनमें कुल 198 लोगों ने भाग लिया. जिम्मलगट्टा इलाके में कुल चार सभाएं हुईं जिनमें 8 गांवों के 390 लोगों ने भाग लिया.

भामरागड़ इलाके में कुल 6 जगहों पर सभाएं आयोजित की गईं जिनमें 390 लोगों ने भाग लिया. इन सभाओं को स्थानीय जन संगठन नेताओं और पीएलजीए कमाण्डरों ने सम्बोधित किया. उन्होंने कहा कि अमर शहीदों के मकसद को पूरा करने के लिए जनयुद्ध को तेज करने की जरूरत है.

एटापल्ली इलाके के इरपानार गांव में जनता ने शहीदों की यादगार में स्मारक का निर्माण किया तो पुलिस ने उसे तोड़ दिया. उसके तीन दिन बाद पीएलजीए सैनिकों ने उसी जगह पर कपड़े से एक स्मारक बनाकर शहीदों को श्रद्धांजली पेश की. उस मौके पर करीब 1500 लोगों ने सभा में भाग लिया. इसके अलावा इलाके में कुल 16 स्मारक बनाए गए. शहीद कॉमरेड्स सरिता और कारु की याद में निर्मित स्मारकों का अनावरण किया गया. कॉमरेड सरिता की मां और कॉमरेड कारू के पिता ने इनका अनावरण किया. इस मौके पर आयोजित सभा में कुल 700 लोगों ने भाग लिया. इसके पहले पूरे इलाके में पोस्टर और बैनर लगाकर प्रचार चलाया गया.

माड़ डिवीजन

इंद्रावती इलाके में कुल चार जगहों पर शहीद सप्ताह मनाया गया. 28 जुलाई के दिन जाड़का और बेलनार गांवों में सभाएं हुईं जिनमें क्रमशः 400 और 300 लोगों ने भाग लिया. सभा को स्थानीय पार्टी, मिलिशिया और जनताना सरकार नेताओं ने सम्बोधित किया. उन्होंने कॉमरेड्स चारु मजुमदार और कन्नाई चटर्जी से लेकर डौला शहीदों तक भारतीय क्रान्ति व विश्व क्रान्ति के तमाम शहीदों को श्रद्धांजली पेश की.

माड़ डिवीजन के डौला इलाके के इतुलवाड़ा, राजुवेड़ा, बड़को, छिनारी, कड़हागांव, मुंडपाल, फरसगांव, माड़ोकी, ओगनार, कल्लेपाल, अड़ेपाल, वड़ेनहोड़, कापसी और मलेचुर गांवों में स्मारकों का निर्माण किया गया. इसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया. शहीद सप्ताह के मौके पर पूरे इलाके में पोस्टर, बैनर और पर्चों के जरिए व्यापक प्रचार किया गया. धौड़ाई शहीदों पर छपी किताबों के साथ–साथ शहीद वीरों की तस्वीरों वाले कैलेन्डर आदि पूरे इलाके में बांटे गए. एक सप्ताह पहले ही प्रचार अभियान शुरू किया गया था.

शहीद सप्ताह में इस इलाके में कुल 24 सभाएं आयोजित की गईं. छिनारी में 6,000, ओगनार में 1500, इतुलवाड़ा में 1000, मुंडपाल में 4,000, बोत्ता में 200, कल्लेपाल में 400, अड़ेगपाल में 150, माड़ोकी में 200, वडेनहोड़ में 500, मलेचुर मं 500, कड़हागांव में 200, बेद्या में 150, फरसगांव में 1000 और छोटे फरसगांव में 200 लोगों ने सभाओं में भाग लिया.

नेलनार इलाके के मोहनार में शहीद स्मारक बनाया गया. वहां पर आयोजित सभा में 200 जनता ने भाग लिया. पोकनार में आयोजित एक और सभा में 100 लोगों ने भाग लिया.

करेलघाट इलाके में दीवरलेखन, पोस्टरिंग के जरिए व्यापक प्रचार चलाया गया. 1 अगस्त को कोड़कानार में शहीद सभा आयोजित की गई जिसमें 400 स्त्री–पुरुषों ने भाग लिया. इस सभा में सीएनएम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए.

(शेष पेज 38 पर ....)

सभा-सम्मेलन

केएएमएस का माड़ डिवीजन प्रथम अधिवेशन सम्पन्न

अगस्त 2005 में केएएमएस का माड़ डिवीजन प्रथम अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ. केएएमएस का झण्डा फहराकर अधिवेशन का आरंभ किया गया. पहले दिन केएएमएस के घोषणा-पत्र पर चर्चा हुई जिसमें सभी प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. स्थानीय समस्याओं को लेकर भी चर्चा हुई. बाद में पितृसत्ता, महिलाओं पर जारी राजकीय हिंसा, हिन्दू मनुवादी संस्कृति की घुसपैठ आदि मुद्दों पर बहस हुई. सरकारी सुधार कार्यक्रमों पर चर्चा के बाद अधिवेशन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये सब जनता को क्रान्तिकारी आन्दोलन से अलग करने के लिए ही किए जा रहे हैं. लोगों में शराब, लंदा आदि नशीले पदार्थों का सेवन करने की आदत पर चर्चा के बाद अधिवेशन ने तय किया इसके खिलाफ प्रचार किया जाए. दण्डकारण्य को आधार इलाके में बदलने के लक्ष्य के तहत एक मजबूत महिला आन्दोलन खड़ा करने की जरूरत पर सारी प्रतिनिधियों ने जोर दिया. संगठन को मजबूत बनाने और गांव-गांव में महिलाओं को बड़े पैमाने पर गोलबन्द करने के लक्ष्य के साथ अधिवेशन सम्पन्न हुआ.

डीएकेएमएस का एटपल्ली एरिया चौथा अधिवेशन सम्पन्न

गड़चिरोली डिवीजन के एटापल्ली इलाके में डीएकेएमएस का चौथा एरिया अधिवेशन 22-23 अगस्त को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ. कॉमरेड मंगतू हाल में आयोजित इस अधिवेशन में कुल 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. कम्यून में कई शहीदों के नाम पर द्वार, ग्राउण्ड आदि निर्मित किए गए. कॉमरेड रामदास ने झण्डा फहराकर अधिवेशन का उद्घाटन किया. शहीदों की याद में प्रतिनिधियों ने दो मिनट का मौन रखा. पहले दिन संगठन के घोषणा-पत्र और संविधान पर चर्चा हुई. बाद में अधिवेशन ने प्रस्ताव किया कि सूर्जागढ़ पहाड़ में लोहा खदान खोलने की सरकारी नीति के खिलाफ संघर्ष किया जाए. सरकार के झूठे सुधार कार्यक्रमों का विरोध करने का भी अधिवेशन ने एक प्रस्ताव किया. आदिवासी संस्कृति पर हिन्दू मनुवादी संस्कृति के हमले के खिलाफ भी अधिवेशन ने प्रस्ताव किया. अन्त में 7 सदस्यों की कमेटी का चुनाव किया गया. नारेबाजी और गीतों के साथ अधिवेशन सम्पन्न हुआ.

डीएकेएमएस का पेरिमिलि एरिया तीसरा अधिवेशन सफल

18 अगस्त की सुबह लाल झण्डा की फड़फड़ाहट के साथ ही डीएकेएमएस का पेरिमिलि एरिया का तीसरा अधिवेशन शुरू हुआ. डीएकेएमएस अध्यक्ष ने झण्डा फहराया था. बाद में शहीद स्मारक का अनावरण किया गया. संगठन को मजबूत बनाने और सरकारी दमन को हराने के संकल्प के साथ अधिवेशन समाप्त हुआ.

8 मार्च - अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

माड़ डिवीजन डौला इलाके में 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया. इलाके के चार रेंजों वेडमाकोट, दण्डवन, बयानार और कड़ेनार में प्रचार अभियान चलाया गया. पोस्टर, पर्चा बांटा गया. महिलाओं पर हिन्दू फासीवादियों के हमले के खिलाफ मुख्य रूप से प्रचार किया गया. इस मौके पर 8 मार्च को वेड़माकोट में आयोजित सभा में 3,000 महिलाओं ने भाग लिया. बयानार में आयोजित सभा में 400 लोगों ने भाग लिया. मढ़ोनार गांव में इस मौके पर महिला शहीदों का स्मारक बनाया गया और उसका अनावरण किया गया. कड़ेनार में आयोजित सभा में 4,000 लोगों ने भाग लिया. इस तरह इस इलाके में कुल 7,400 लोगों ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया.

दक्षिण बस्तर डिवीजन के पामेड़ और ऊसूर इलाकों में 8 मार्च के मौके पर सेमिनार का आयोजन किया गया. पामेड़ सेमिनार में कुल 27 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. केएएमएस नेताओं ने इस मौके पर आदिवासियों पर सरकारी हिंसा के विषय पर चर्चा चलाई. इसके बाद रैली निकाली गई जिसमें 200 महिलाओं के अलावा 80 पुरुषों ने भाग लिया. इसी प्रकार ऊसूर सेमिनार में 28 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. उसमें भी इसी मुद्दे पर चर्चा हुई. महिला आन्दोलन में क्लारा जेटकिन की भूमिका के विषय पर कक्षा ली गई.

इस मौके पर बिडियाबट्टम, मंगेल और ऊसर में आमसभाएं भी आयोजित की गईं. पोस्टर-पर्चे बांटे गए. जगह-जगह पर बैनर लगाए गए. इस प्रकार 8 मार्च का संदेश इलाके के सैकड़ों मेहनतकश महिलाओं तक पहुंचाया गया.

21 सितम्बर को पार्टी का स्थापना दिवस

भाकपा (माओवादी) के गठन के बाद इस वर्ष 21 सितम्बर को पार्टी की पहली वर्षगांठ मनाई गई. इस मौके पर माड़ डिवीजन के नेलनार इलाके में एक सभा हुई जिसमें 200 लोगों ने भाग लिया. करेलघाट इलाके मं आयोजित एक सभा में 1,000 लोगों ने भाग लिया. ''कॉमरेड चारु मजुमदार व कॉमरेड कन्नाई चटर्जी अमर रहें'', ''पीएलजीए को पीएलए में बदल डालो'', आदि नारे जोर शोर से लगाए गए. *(इस मौके पर दण्डकारण्य के सभी डिवीजनों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया. पर इसकी विस्तृत रिपोर्टें हमें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं. - सम्पादकमण्डल)* ✶

'प्रभात' के लिए रिपोर्टें लिखने वाले साथियों से अपील

- **जिस घटना या कार्यक्रम के सम्बन्ध में आप रिपोर्ट लिखते हैं, उसकी तारीख, स्थान (गांव, तहसील, जिला, आदि) जरूर लिखिएगा.**
- **रिपोर्ट कागज की एक ही तरफ साफ-साफ अक्षरों में लिखिएगा. अलग-अलग रिपोर्टों को अलग-अलग कागजों पर लिखिएगा.**
- **सरकारी दमन के सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखते समय तारीख लिखना बहुत जरूरी है. गिरफ्तार लोगों की संख्या, आदि तफसील जरूर लिखिएगा.**
- **खासतौर पर गांवों और व्यक्तियों के नाम साफ-साफ लिखिएगा.**
- **पीएलजीए की कार्रवाइयों के सम्बन्ध में रिपोर्टें जितना जल्दी सम्भव हो लिख भेजते रहिएगा.**
- **'प्रभात' के हर अंक पर अपने विचार - सुझाव जरूर लिख भेजिएगा.**

- सम्पादकमण्डल

दण्डकारण्य आन्दोलन पर जारी फासीवादी सरकारी दमन

माड़ डिवीजन के डौला इलाके में पुलिस ने मई से अगस्त तक एक भारी दमन अभियान चलाया. गांवों में गश्त लगाते हुए जो भी आदमी मिलता है तो उसे पकड़कर बुरी यातनाएं देना तथा इनामी नक्सली घोषित करना आम हो गया. बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में ठूंसा जा रहा है. संगठन सदस्यों के घरों पर छापेमारी करके घर का सारा सामान लूट रहे हैं. मुरगा, बकरा, पैसा, जेवर, नगदी सब लूटकर ले जा रहे हैं. हाल में छिनारी गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस व अर्ध सैनिक बलों ने जुगरू के घर से 10 मुरगे, नेगी के घर से 4 मुरगे, मोहन के घर से 7 हजार रुपए की नगदी लूट ली. तथा एक दुकान में तोड़फोड़ की. राजवेड़ा गांव में जोलमा के घर से 350 रुपए की नगदी चोरी की. केंजग गांव में एक आंगनवाड़ी शिक्षिका के घर से 1500 रुपए और गहनों की चोरी की. बयनार गांव में संगठन नेता के घर से 4,000 रुपए की नगदी की चोरी की. उसी गांव के एक निजी डॉक्टर लालाराम के घर से 2 हजार रुपए उठा ले गए. गश्त पर आते समय घरों से जबर्दस्ती चोरी करने की घटनाओं का हिसाब नहीं है. दुरबेड़ा एवं परपा गांवों से एक–एक बकरा ले गए. मढ़ोनार गांव में दलसाय और घस्सू के घरों में पुलिस ने तोड़फोड़ की.

करेनारगांव में 15 लोगों को निर्मम तरीके से पीटा गया जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए. महिमा गवाड़ी और गायतापारा के तीन व्यक्तियों धोबी, नगसाय और बीरसिंह की भी बुरी तरह पिटाई की. पिटाई से ये लोग बेहोश हुए थे. बावड़ी गांव में त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए लोगों पर पुलिस ने धावा बोलकर 6–7 लोगों की बुरी तरह पिटाई की. बेनूर कुरुसनार के पास बैल चरा रही एक महिला के साथ पुलिस ने बलात्कार किया.

डौला पुलिस कैम्प पर पीएलजीए के हमले के बाद पुलिस ने दुड़मी, पल्ली, कोशलनार, बुड़गलकोट्टुम, महिमा गवाड़ी, गायतापारा, मुड़पाल गांवों में कम से कम 25 लोगों की बुरी तरह पिटाई की. पिटाई से वे बेहोश हुए थे. एक गाड़ी मालिक पर नक्सलवादियों को गाड़ी देने का निराधार आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार किया और उसकी गाड़ी जब्त की. दण्डवन, राजुवेड़ा, केंजग गांवों में निर्मित शहीद स्मारकों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया. पुलिसिया आतंक इतना ज्यादा बढ़ा है कि लोग अपने खेत पर जाकर जुताई करने से भी कतरा रहे हैं. दूर के गांवों में जाकर पढ़ने वाले बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं. लोगों को जहां–तहां पकड़ने और अंधाधुंध पिटाई करने से दहशत का माहौल बना हुआ है.

गिरफ्तारियां

2 अगस्त को डीएकेएमएस बयानार रेंज कमेटी का सदस्य कॉमरेड लच्छिन्दर को बयानार बाजार में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में कैद कर दिया. उस पर 22 झूठे मामले दर्ज किए. मढ़ोनार गांव के बाल संगठन अध्यक्ष कॉमरेड चमरा (14 साल) को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. तोड़मा गांव के तीन संगठन सदस्यों को बारसूर बाजार में सब्जी–बाजी खरीदते समय गिरफ्तार कर उन्हें इनामी नक्सली घोषित किया. पुलिस ने वटेकल गांव का संगठन सदस्य जग्गू को बारसूर बाजार में गिरफ्तार किया है जिसका अब तक कोई अता–पता नहीं है. हाट बाजार जाने वाले लोगों को मुखबिरों की सहायता से पुलिस गिरफ्तार कर रही है. उन्हें बुरी यातनाएं देने के बाद इनामी नक्सली बताते हुए झूठे केस लगाकर जेल भेज रही है.

करेलघाट इलाके के कुकड़ाजोर गांव में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनमें कई लोग संगठन सदस्य भी नहीं हैं. बागडोंगरी में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया. कुरसनार में घसिया नामक गांव के मुखिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया. जीवलापारा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. नेलनार इलाके के धानोरा गांव में पांच लोगों को गिरफ्तार किया.

गड़चिरोली डिवीजन में जनता को सुबह–शाम पुलिस के लोहे के जूतों की दनदनाहट सुनाई पड़ती है. खासकर कमाण्डो पुलिस बल आतंक का पर्याय बनी है. अहेरी इलाके के वेंकटापुर गांव के शंकर

(शेष पेज 45 पर ....)

दण्डकारण्य में 15 अगस्त को मना 'काला दिवस'

हर वर्ष की तरह इस साल भी दण्डकारण्य की जनता ने 15 अगस्त को झूठी आजादी की जश्न का विरोध करते हुए 'काला दिवस' मनाया. इसके सम्बन्ध में गांव–गांव में पोस्टर लगाकर प्रचार किया गया. 15 अगस्त की गद्दारी के बारे में जनता में बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया. लोगों को असली आजादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी गई.

माड़ डिवजन के नेलनार इलाके के धनोरा गांव में जनता ने 'काला दिवस' मनाया जिसमें स्कूली छात्रों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया. इस मौके पर जन संगठनों ने एक सभा आयोजित की जिसमें वक्ताओं ने झूठी आजादी का पर्दाफाश करते हुए जनता का आह्वान किया कि असली आजादी के लिए जनयुद्ध को जारी रखा जाए.

बयानार गांव में भी इस मौके पर एक रैली निकाली गई. 'यह आजादी झूठी है – देश की जनता भूखी है', आदि नारे जोर शोर से लगाए गए. प्रदर्शन के बाद जनता ने जॉर्ज बुश, मनमोहन सिंह और रमन सिंह के पुतले जलाए और साम्राज्यवाद–शासित भूमण्डलीकरण की नीतियों का जमकर विरोध किया. इस विशाल रैली में करीब 40 गांवों से 2,500 लोगों ने भाग लिया.

इंद्रावती इलाके के आदेर गांव में जनता ने 15 अगस्त को 'काला दिवस' दिवस मनाया. इस मौके पर आयोजित सभा में 150 लोगों ने भाग लिया. इस मौके पर जनता ने पश्चिम बस्तर में जारी फासीवादी 'जन जागरण' अभियान की भर्त्सना करते हुए नारे लगाए और महेन्द्र कर्मा व रमन सिंह के पुतले जला दिए.

उत्तर बस्तर डिवीजन के केसकाल इलाके में कुल 235 पोस्टर लगाकर प्रचार किया गया. किसकोड्डो गांव में काला दिवस मनाया गया जिसमें कम से कम 10 गावों से 300 लोगों ने भाग लिया. कोड़ियूर गांव में भी 'काला दिवस' मनाया गया जहां कुल 600 लोगों ने भाग लिया. जुंगनार में आयोजित 'काला दिवस' में करीब 700 लोगों ने शिरकत की.

गड़चिरोली डिवीजन के अहेरी इलाके में दो गांवों की जनता ने 'काला दिवस' दिवस मनाया. सभा को स्थानीय पार्टी नेताओं ने सम्बोधित किया. ✶

संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ता दण्डकारण्य का शोषित अवाम

दण्डकारण्य की जनता सरकारी दमन को धता बताते हुए कई संघर्ष कर रही है. दिन ब दिन जनता की संघर्ष चेतना बढ़ती ही जा रही है. राजनीतिक मसलों के साथ-साथ अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर जनता लगातार संघर्ष कर रही है. इसके अलावा यहां पर गांव-गांव में निर्मित हो रही जनता की नई राजसत्ता के अंगों, यानी जनताना सरकारों की अगुवाई में कई विकास कार्यक्रम चलाए गए. जनता अपने विकास का फैसला खुद करने लगी है. ये जन संघर्ष पिछले 58 सालों से लोक लुभावन योजनाओं और विशेष पैकेजों से आदिवासियों का विकास करने का ढिंढ़ोरा पीटते हुए छलते आ रहे शासकों के मुंह पर करारा तमाचा हैं. पेश हैं – पिछले 6-7 महीनों के दौरान किए गए कुछ जन संघर्षों का ब्यौरा.

'ग्राम सुराज' अभियान का विरोध

छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने मई 2005 में 'ग्राम सुराज' अभियान के नाम से एक जन संपर्क अभियान शुरू किया. ग्रामीण जनता की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल कर उनके निराकरण करना इसका उद्देश्य बताया गया. जबसे रमन सरकार सत्ता में आई थी तबसे प्रदेश भर में जनता की समस्याएं और ज्यादा बढ़ी हैं. 25 पैसे में किलो नमक की सस्ती योजना शुरू करने का ढिंढ़ोरा पीटने वाली रमन सिंह सरकार संघर्ष इलाकों में हाट बाजार बन्द करवाकर लोगों को नमक तक नहीं मिलने दे रही है. 5 रुपए में दाल-भात का प्रचार करने वाली भाजपा सरकार के डेढ़ साल के शासन में लोगों को अपने पेट की आग बुझाने के लिए दूर-दूर के इलाकों में पलायन करने की मजबूरी से कोई मुक्ति नहीं मिली है. पुलिस दमन न सिर्फ संघर्ष इलाकों में, बल्कि पूरे प्रदेश में बढ़ गया. कम से कम दो दर्जन गरीब व दलित-आदिवासी युवकों को थानों के अन्दर पीट-पीट कर मार डाला गया. संघर्ष इलाकों में तैनात सीआरपी बल आए दिन गांवों में आदिवासी मां-बहनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं और हत्या व आतंक मचा रहे हैं. नेता-अफसर भ्रष्टाचार-घोटालों में लिप्त होकर करोड़ों रुपए हड़प रहे हैं. 'काम के बदले अनाज' योजना का चावल पूरा विधायक, मंत्री, अफसर ही खा रहे हैं. एक तरफ गांवों को कब्रगाहों में तब्दील करते हुए दूसरी तरफ 'ग्राम सुराज' के नाम से गांवों में आने वाले अफसरों व नेताओं को कड़ा सबक सिखाकर इस अभियान का बहिष्कार करने का निर्णय पार्टी द्वारा लिया गया.

इसके अनुसार दक्षिण बस्तर डिवीजन के ऊसूर इलाके के पूजारीकांकेर गांव में आए अधिकारियों को पीएलजीए सैनिकों ने जनता के साथ मिलकर गिरफ्तार कर बाद में छोड़ दिया. उनका एक दुपहिया वाहन जला दिया. पश्चिम बस्तर के मद्देड़ इलाके में एसआर गुप्ता नामक बदनाम भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा गया, जिसे जन अदालत में पेश करके हल्की सजा देकर छोड़ दिया गया. कोंटा इलाके में कलेक्टर की अगुवाई में इस अभियान को चलाने की योजना थी. इसका बहिष्कार करने की अपील करते हुए जन संगठनों ने जगह-जगह पोस्टर चस्पा किया. इससे यह योजना नाकाम हो गई. इस प्रकार दक्षिण बस्तर डिवीजन में जनता ने 'ग्राम सुराज' अभियान का सम्पूर्ण बहिष्कार किया.

'गांवबंदी' कराने वाले पटेल-पूजारी को सजा

पाठकों को मालूम ही है कि गड़चिरोली में पुलिस अमले ने क्रान्तिकारी आन्दोलन का उन्मूलन करने की मंशा से 'गांवबंदी' के नाम से एक षडयंत्रपूर्ण योजना सामने लाई. गांव के दुष्ट मुखियाओं को इकट्ठे करके उन्हें पैसे का लालच देकर या दबाव डालकर 'गांवबन्दी' की घोषणा करवाई जा रही है. ऐसे ही टिप्रागढ़ इलाके के मुरुमगांव रेंज के कुलभट्टी गांव के पुलिस पटेल और पूजारी ने भी पुलिस के साथ सांठगांठ कर 'गांवबंदी' करवा दी. गांव के लोगों को दबाकर रख दिया. लेकिन आसपास के गांवों के जन संगठन कार्यकर्ताओं और जनता ने इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पटेल का सफाया कर दिया और पूजारी को आर्थिक दण्ड सुनाया.

मजदूरी बढ़ाने के लिए जन संघर्ष

सिरोंचा इलाके में जनता ने जन संगठनों की अगुवाई में मजदूरी दामों को बढ़ा लिया. फसल की बोआई, निंदाई, कटाई आदि कामों के लिए 10 रुपए से 20 रुपए तक मजदूरी बढ़ गई. यह संघर्ष 3-4 गांवों में किया गया. बाकी गांवों में इस हेतु प्रचार किया गया.

भ्रष्ट नेता के खिलाफ जनता का संघर्ष

गड़चिरोली डिवीजन के सिरोंचा इलाके के मेडारम गांव का उप सरपंच मधुकर शेंडे और जिल्लापल्ली मधुनय्या पर 20 जुलाई को जन अदालत में सुनवाई हुई. मधुकर और मधुनय्या दोनों ने लोगों को सरकार से घर दिलवाने के नाम पर 5 हजार रुपए, नलकूप लगवाने के नाम से 10 हजार तथा हॉस्टल में हर बच्चे के लिए मंजूर 1200 रुपए में से 500 रुपए के हिसाब से भारी लूटपाट की थी. घर बनाने या नलकूप लगवाने का ठेका भी यही लोग लेते थे और मोटी रकम हड़प लेते थे. गांव की शिक्षा कमेटी के लोगों ने स्कूल फंड से भी पैसा खा लिया. इन सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सुनवाई के बाद जन अदालत ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी तथा पैसा वापस देने को कहा.

जनता ने उठाए खुद के विकास के कदम

गड़चिरोली डिवीजन के अहेरी इलाके के 5 गांवों में लोगों ने लगभग 50 दिनों तक सामूहिक रूप से काम किया. अकाल की समस्या से जूझ रहे लोगों ने इस काम के जरिए अपने खेतों व तालाबों की मरम्मत की गई. इसमें कुल मिलाकर 1448 लोगों ने भाग लिया. गांव के सामूहिक कोश से पैसे निकाल कर काम करने वाले लोगों को रोजाना डेढ़ किलो चावल बांटा गया. इस प्रकार लोगों ने अपनी मर्जी से अपने विकास के लिए काम किए, साथ-साथ अकाल की समस्या से उन्हें राहत भी मिली.

9 गांवों के 135 परिवारों को बीज वितरित किए गए. हर परिवार को 40 किलो बीज बांटे गए. गरीब परिवारों की परेशानी को देखते हुए जन संगठनों ने धनी किसानों को समझा-बुझाकर उनसे 16 क्विंटल धान वसूल कर बांटा. जिम्मला गांव में लोगों ने 6 दिन सामूहिक श्रमदान करके एक तालाब का निर्माण किया.

माड़ डिवीजन के डौला इलाके में जनता ने सरकार के झूठे विकास कार्यक्रमों को धता बताते हुए अपने विकास का फैसला खुद ही लिया है. जन संगठनों की अगुवाई में जनता ने इस इलाके में इस वर्ष कई कार्य किए. 180 घर, 25 तालाब, 16 कुंए, रात पढ़ाई की 13 शालाएं, भूमकाल (सामूहिक) कृषि के लिए 4 मुण्डा और 4 तालाबों का निर्माण किया गया. इनमें से घरों को छोड़कर बाकी सब सामूहिक उपयोग के हैं. खास बात यह है कि इन कामों को जनता ने सामूहिक श्रमदान से पूरा किया. पैसा बहुत कम खर्च हुआ है, अपने ही संसाधनों के भरोसे लोगों ने इन्हें अंजाम दिया

है. इससे लोगों में उत्साह और आत्मनिर्भरता की भावना का संचार हुआ. उनका विश्वास बढ़ा है कि वे अपने भाग्य का फैसला खुद कर सकते हैं.

तेन्दुपत्ता मजदूरी बढ़ाने के लिए जन संघर्ष

दक्षिण बस्तर डिवीजन के कोंटा तहसील मुख्यालय में 27 मार्च 2005 को किष्टारम, गोल्लापल्ली, कोंटा और दोरनापाल इलाकों की जनता ने तेन्दुपत्ता मजदूरी बढ़ाने की मांग करते हुए रैली निकाली. जनता ने 90 पैसा प्रति गड्डी की मांग की. इसके अलावा फड़ मुंशी के लिए 4,000 रुपए, आदि मांगें भी कीं. पोस्टर-बैनर हाथों में लेकर 15 हजार लोगों ने इसमें भाग लिया. 28 मार्च को जेगुरगोंडा में एक रैली निकाली गई जिसमें 3,000 लोगों ने भाग लिया. बाद में 30 मार्च को आवापल्ली में रैली निकाली गई जिसमें 3 हजार लोगों ने शिरकत की. अपनी मांगों से अवगत कराते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकारी अधिकारियों को मांगपत्र सौंप दिए. लेकिन सरकार ने अपने अड़ियल रवैए पर बने रहते हुए मजदूरी नहीं बढ़ाई. उलटा सरकार यह प्रचारित कर रही है कि अब मजदूरों को मालिक बनाया गया है, इसलिए मजदूरी बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है. अपनी लूटखसोट पर परदा डालने का उसका यह एक नायाब तरीका है. तेन्दुपत्ता ठेकेदारों से नक्सलवादी लाखों रुपए वसूल रहे हैं कहकर गला फाड़कर चिल्लाने वाली सरकार मजदूरों को ठेकेदारों से भी बहुत कम दर क्यों दे रही है, इसका जवाब उसके पास नहीं है. सच्चाई यह है कि मजदूरों को लूटने के मामले में सरकार ठेकेदारों से भी एक कदम आगे है. इस संघर्ष ने जनता को यह शिक्षा दी कि लुटेरी सरकार के खिलाफ जन संघर्ष तेज किए बिना उसे झुका नहीं सकते.

लोगों ने की भ्रष्टाचारियों से चावल की जब्ती

माड़ डिवीजन के डौला इलाके के दण्डवन रेंज के नेतानार गांव के पंचायत सचिव ने 'काम के बदले अनाज' के नाम से सरकार से मिले 200 क्विन्टल चावल का गबन कर लिया. उसने सारे चावल रातोंरात निकालकर एक गुप्त जगह पर रख लिया. और वहीं से गुपचुप तरीके से बेचने लगा था. इसका पता डीएकेएमएस को मिला. आसपास के 22 गांवों के लोग इकट्ठे होकर सारे चावल जब्त कर लिए. इस मौके पर जन अदालत लगाकर सचिव के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करके उसे कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. इस मौके पर जन संगठन नेताओं ने लोगों को बताया कि किस तरह सरकार जनता के नाम से पैसे, अनाज आवंटित कर लुटेरों को फायदा पहुंचा रही है और चुपचाप तमाशा देख रही है.

उत्तर बस्तर डिवीजन के केशकाल इलाके के चिंगनार रेंज गेड़मा गांव में भी इसी तरह लोगों ने 12 मई को 36 क्विन्टल चावल जब्त किया. इस चावल को जन संगठनों ने गरीब लोगों में बांटा. अन्तागढ़ रेंज के चिपोंडी गांव में 16 क्विन्टल चावल को जब्त कर गरीब लोगों को बांट दिया गया.

टिप्रागढ़ इलाके में अकाल रैली

अकाल की समस्या को लेकर गड़चिरोली के आदिवासी किसानों ने आवाज उठाई. सरकारों की घोर लापरवाही के कारण ही अकाल की स्थिति निर्मित हुई है. अनेक जीवनदियों की मौजूदगी के बावजूद जिले की जनता को पानी के लिए बादलों की तरफ देखना पड़ता है. सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने का सरकार ने कोई सार्थक प्रयास नहीं किया. खासकर इस साल किसानों को अकाल की मार से बुरी तरह परेशान होना पड़ा. इसके खिलाफ जनता ने जहां-तहां संगठित होकर संघर्ष का बिगुल बजाया. 28 जुलाई के दिन धनोरा तहसील मुख्यालय में करीब 8,000 किसानों ने एक विशाल रैली निकाली और वहां उपस्थित सरकारी अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए मांग पत्र सौंप दिया.

15 से 21 मई तक दमन विरोधी सप्ताह मना

देश भर में बढ़ रहे क्रान्तिकारी आन्दोलनों पर जारी सरकारी दमन के खिलाफ पार्टी ने 15 से 21 मई तक 'दमन विरोधी सप्ताह' मनाने का आहवान किया था.

दक्षिण बस्तर डिवीजन में जन संगठनों ने इस आहवान को पाकर कई कार्यक्रम चलाए. डीएकेएमएस और केएएमएस के 200 से ज्यादा प्रचार दलों ने प्रचार अभियान चलाया. 5-6 जगहों पर जनता ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया. ऊसूर ब्लॉक में बासागुड़ा, ऊसूर, पूजारीकांकेर तथा कोंटा तहसील में जगुरगोंडा में जनता ने रोड को खोदकर दमन के प्रति विरोध जताया. इसके अलावा 10 गांव की जनता ने एक आमसभा आयोजित की जिसे डीएकेएमएस के नेताओं ने सम्बोधित किया.

माड़ डिवीजन के डौला इलाके में दमन के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया गया. इलाके में लगने वाले सभी हाट बाजारों में दमन के खिलाफ रैलियां निकाली. वेड़माकोट में 500, बयानार में 300, कड़ेनार में 2,000, महिमा गवाड़ी में 3,000 लोगों ने रैलियों में भाग लिया. नेलनार इलाके के नुलबटी बाजार में 350, कुस्तुरमेट्टा में 200, जमरी बाजार में 300 लोगों ने रैलियां निकालीं. इन रैलियों में केन्द्र-राज्य सरकारों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.

गड़चिरोली डिवीजन में दमन विरोधी सप्ताह के दौरान 17 मई को सिरोंचा इलाके के पेटा ग्राम पंचायत भवन को ध्वस्त किया गया. इसके अलावा इलाके में पोस्टर चस्पा कर सरकार की दमन नीति का पर्दाफाश किया गया. कुछेक गांवों में इस मौके पर सभाएं आयोजित की गईं.

पश्चिम बस्तर डिवीजन के मद्देड़ इलाके में जन संगठनों ने पोस्टर व पर्चों के जरिए सरकारी दमन के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाया गया. बीजापुर-आवापल्ली रोड, बीजापुर-पटनम रोड पर कई जगहों पर अवरोध खड़े करके यातायात को रोक दिया गया. आवापल्ली में बीडीओ के दफ्तर को जला दिया गया. दमन के खिलाफ लगभग 2-3 हजार लोगों ने रैली निकालने की कोशिश की पर कलेक्टर की अनुमति नहीं है बताकर अधिकारियों ने उसे रोक दिया.

बीआरओ की गाड़ी ध्वस्त

जन संगठनों द्वारा मना करने के बावजूद अहेरी इलाके के कोड़सेपल्ली के पास रोड के काम में जुटे बीआरओ की एक गाड़ी को जनता ने 16 जुलाई को जला दिया. वहां काम करवा रहे दो मेटों की पिटाई कर दी. ज्ञात हो कि संघर्ष इलाकों में सरकार कई सालों से सड़कें बनवा रही है ताकि पुलिस बलों को बड़े पैमाने पर भेजकर क्रान्तिकारी आन्दोलन का सफाया किया जा सके. लेकिन क्रान्तिकारी राजनीतिक चेतना से लैस जनता इसका विरोध कर रही है.

'जन जागरण' अभियान के खिलाफ माड़ डिवीजन में 'भूमकाल अभियान'

पश्चिम बस्तर में जारी फासीवादी 'जन जागरण' अभियान के खिलाफ माड़ के लोगों ने 'भूमकाल अभियान' शुरू किया. इसके तहत लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे कर न सिर्फ संघर्षरत पश्चिम बस्तर की जनता के प्रति समर्थन प्रकट किया, बल्कि 'जन जागरण' अभियान का पर्दाफाश किया. इसमें डीएकेएमएस और केएएमएस ने अहम भूमिका

निभाई. डौला इलाके के गांव बयानार में 1500, महिमा गवाड़ी में 1500, छिनारी में 300, वेड़माकोट में 2,000 लोगों ने इन प्रदर्शनों में भाग लिया. इस दौरान महेन्द्र कर्मा, रमन सिंह और मनमोहन सिंह के पुतले फूंक दिए गए.

इंद्रावती इलाके में कुल 20 जगहों पर सभाएं हुईं. 'जन जागरण' के खिलाफ जगह-जगह पर पोस्टर, पर्चे, बैनर लगाए गए. इस मौके पर कुछ जन विरोधी तत्वों को चेतावनियां व आर्थिक सजाएं दी गईं.

'जन जागरण' अभियान के खिलाफ जन सभाएं

दक्षिण बस्तर के कोंटा और दोरनापाल इलाकों में 'जन जागरण' अभियान के खिलाफ जनता को बड़े पैमाने पर गोलबन्द करके दो बड़ी सभाएं आयोजित की गईं. कोर्रापाड़ गांव में आयोजित सभा में 31 गांवों के करीब 3,000 लोगों ने भाग लिया. गोंदुम गांव में आयोजित सभा में करीब 4,000 जनता ने भाग लिया. खास बात यह है इस इलाके के सरपंच-सचिवों और पटेल, पूजारी, आदि मुखियाओं को बुलाकर 'जन जागरण' का पक्ष न लेने की हिदायत दी गई. अगर 'जन जागरण' में शामिल होंगे तो जनता के हाथों सजा भुगतनी पड़ेगी, उन्हें ऐसी चेतावनी दी गई. जनता ने 'जन जागरण' के खिलाफ तथा महेन्द्र कर्मा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. सीएनएम के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए.

जालिम नेताओं के घरों पर हमला

माड़ डिवीजन के डौला इलाके के बुड़तुम गांव का कांग्रेसी सरपंच दियारू और गुपागांव का कांग्रेसी नेता मोहन दोनों मिलकर आसपास की जनता को 'जन जागरण' के लिए तैयार कर रहे थे. लोगों को धमकी दे रहे थे कि जो 'जन जागरण' मीटिंग में नहीं आएंगे उन्हें जुर्माना देना होगा. इन्होंने घर-घर से 15-15 रुपए इकट्ठे किए थे. डीएकेएमएस के नेतृत्व में इनके घरों पर हमला कर 150 खंडी धान और अन्य सामान जब्त करके गरीब लोगों में बांट दिया गया. उन्हें जन अदालत में चेतावनी देकर छोड़ दिया गया.

इंद्रावती इलाके के ईदवाड़ा के कोसाल वेको और उसका बाप दोनों 'जन जागरण' में शामिल होकर क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ खड़े हो गए. ये लोग पहले से ही जन विरोधी थे, इन्होंने जनता का जीना दूभर कर रखा था. जब संगठन हावी हो गए तब ये दबकर रहा करते थे. अब जबकि 'जन जागरण' शुरू हुआ, तो इन्हें जैसे नई जान मिल गई. आसपास के लोगों को बुलाकर इन्होंने मीटिंग कर छापामार दस्तों के खिलाफ उकसाया था. तुरन्त ही जन संगठनों की अगुवाई में जनता ने इन दोनों को पकड़कर कोसा को मार डाला, बाप को छोड़ दिया. इसी प्रकार जनता ने कोड़का गांव के चमरू पटेल के घर पर हमला करके सम्पत्ति जब्त कर ली. वह भी 'जन जागरण' से जुड़ गया था. 'जन जागरण' अभियान में शामिल होने वाले झारामरका गांव के चैतू तथा टेकला गांव के कोंदा को जनता ने मौत के घाट उतार दिया.

पुलिस मुखबिर की सम्पत्ति जब्त

माड़ डिवीजन के नेलनार इलाके के धनोरा गांव का निवासी कृष्ण हल्बा 6-7 सालों से पुलिस मुखबिरी कर रहा था. गांव में जनता को दबाकर रखा करता था. छोटेडोंगर के थानेदार से इसका सीधा सम्बन्ध था. एक बार संगठन सदस्यों ने इसे समझाइश दी थी पर वह नहीं सुधरा. बाद में इसका बेटा पुलिस में भर्ती हो गया. तबसे वह और ज्यादा घमण्ड दिखाने लगा. इसे सबक सिखाने के लिए जन संगठनों की अगुवाई में जनता ने इसके घर पर हमला कर सारी सम्पत्ति जब्त कर उसे गरीबों में बांट दिया गया.

गड़चिरोली डिवीजन में पीएलजीए का एम्बुश

पांच कमाण्डो जवानों का सफाया

गड़चिरोली जिले के सी-60 क्रैक कमाण्डो पुलिस बल क्रूरता और आतंक का पर्याय हैं. अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये कमाण्डो जनता पर बर्बरतापूर्वक हमले करते हैं. हाल ही में 3 अप्रैल को जप्पी गांव के पास पीएलजीए के योद्धाओं ने इन पर जोरदार हमला - अपार्चुनिटी एम्बुश किया. इस हमले में चार कमाण्डो वहीं मारे गए जबकि एक ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया. बाकी पुलिस वाले फायरिंग करते हुए भाग खड़े हुए. इस घटना के बाद जनता में खुशी की लहर दौड़ गई. उधर दुश्मन वर्गों में खलबली मच गई. पुलिस ने बारूदीसुरंग-रोधक गाड़ियों की मांग की. इस हमले से यह बात फिर एक बार साबित हो गई कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस शत्रु बलों को भी जनता के सहयोग से सूझबूझ व साहस के साथ लड़कर धूल चटाया जा सकता है.

पुराना मुखबिर बोतसाय एक्का का सफाया

1994 में गड़चिरोली जिले के मुरुमगांव रेंज के सिंदेसूर गांव में बोतसाय एक्का की मुखबिरी से पुलिस ने छापामार दस्ते पर कातिलाना हमला किया था. उस हमले में पार्टी का एक वरिष्ठ साथी कॉमरेड आजाद (आनन्द) शहीद हुए थे. तबसे बोतसाय ने गांव छोड़ दिया और मुरुमगांव में रहने लगा. बोतसाय दरअसल जमीन की तलाश में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से यहां आकर बसा था. बाद में पैसे के लालच में पुलिस का खबरिया बन गया. पुलिस ने इसे मोटार सायकिल, रिवाल्वर दिया. यह गोपनीय सैनिक के रूप में काम करने लगा था. 7 मई 2005 को, यानी 11 साल बाद पीएलजीए के सैनिकों ने जनता के सक्रिय सहयोग से इस पुराने दुश्मन को पकड़कर मार डाला. इस कार्रवाई से पीएलजीए ने जन दुश्मनों को यह चेतावनी दी कि जनता के खिलाफ काम कर क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ गद्दारी करने वाले भले ही कुछ साल ऐश कर सकते हों पर आखिरकार अपनी मौत से बच नहीं सकते.

मानेवारा मुठभेड़ के लिए जिम्मेदार मुखबिरों का सफाया

पिछले साल 2 नवम्बर को गड़चिरोली डिवीजन के मानेवारा के पास पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दो कॉमरेड - सेक्षन कमाण्डर भूमन्ना और सदस्या सरिता शहीद हुए थे. इसके लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाया तो तानू और उसका काका सरपंच दोनों के नाम सामने आए. तानू दरअसल डीएकेएमएस का नेता हुआ करता था. लेकिन सरकार ने उसे पैसे का लालच देकर अपनी तरफ रिझा लिया. बाद में उसमें स्वार्थ की भावना बढ़ी थी. इससे इसे संगठन से बाहर निकाल दिया गया. बाद में तानू ने पुलिस के साथ सांठगांठ कर पूरे दस्ते का सफाया करने की साजिश रची थी. इस साजिश में सरपंच का भी हाथ था जो उसका काका था. मुठभेड़ के दिन इन लोगों ने जानबूझकर दस्ते के लिए खाना लाने में देरी की थी ताकि पुलिस पहुंच सके. ज्यों ही खाना खाना पूरा हुआ, दस्ते पर पुलिस ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की थी. बाद में इसकी पूरी छानबीन की गई और 1 अगस्त की रात इस साजिश शामिल दोनों मुखबिरों का सफाया कर दिया गया.

पुलिस मुखबिरों व जन दुश्मनों को सजाएं

गड़चिरोली डिवीजन के सिरोंचा इलाके के गरकापेटा का गुण्डा और पुलिस मुखबिर कुम्मरी बापू को पीएलजीए ने मौत के घाट उतार दिया. यह बदनाम गुण्डा था जो गांव में जनता पर कई प्रकार के जुल्म करता था. पुलिस की मुखबिरी करता था. इसकी मुखबिरी से छापामार दस्ते पर पुलिस का हमला होते-होते रह गया. बाद में जनता और पार्टी ने चर्चा करके इसका सफाया करने का फैसला लिया. मिलिशिया के सदस्यों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

टिप्रागढ़ इलाके के कोसमी गांव का मुखिया सितल मोकासी को 19 मई को जन अदालत के फैसले के मुताबिक मार डाला गया. पुरानी जमींदारी खानदान का यह मुखिया कई सालों से क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ काम करता रहा. जनता ने एकमत से इसका सफाया करने का फैसला सुनाया. अहेरी इलाके के देचली गांव का सीताराम मड़ावी पुलिस के साथ मिला हुआ था. 2003 से ही यह वन विभाग में वाचर का काम करते हुए गुप्त रूप से पुलिस को छापामार दस्तों की खबर पहुंचाया करता था. इसे गर्मियों में टीसीओसी के दौरान खत्म कर दिया गया.

एटपल्ली के कसनसूर के पास कासुलएर गांव का रैनू गोटा पुलिस मुखबिर था. कमाण्डो दरोगा देवजी का यह भाड़े का टट्टू था. बहुत पहले इसकी मुखबिरी से छापामार दस्ते पर इस गांव में दुश्मन ने हमला किया था. बाद में 2005 की गर्मियों में इसने फिर एक बार दस्ते पर पुलिस को लाकर हमला करवाने की नाकाम कोशिश की. इसके बाद जनता के सहयोग से इसे पकड़कर जन अदालत में पेश की गई. जनता ने इसे मार डालने को कहा. पीएलजीए कॉमरेडों ने उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया.

अहेरी इलाके के चलेवाड़ा गांव के दुर्गम बाबू कई सालों से मुखबिरी करता रहा. कई बार चेतावनी देने से भी उसमें सुधार नहीं आया था. जनता की मांग पर बाबू का सफाया कर दिया गया.

उत्तर बस्तर डिवीजन के दूरघाट इलाके के चारभट्टी गांव के मंड़ावी केशव 2-3 साल से पुलिस मुखबिरी कर रहा था. कांकेर एसपी के साथ इसका सम्बन्ध था. इसे पुलिस से बाकायदा 2 हजार रुपए प्रति माह तनख्वाह मिलती थी. जनता के सहयोग से इसे पीएलजीए दस्ते ने गिरफ्तार कर जनता के साथ चर्चा कर, उसकी सहमति से केशव को मौत के घाट उतार दिया.

केसकाल इलाके के अंतागढ़ रेंज मातला गांव में बांडा लोहार नामक नकली नक्सलवादी का सफाया किया गया. यह गांव में गुण्डागर्दी करता था. कई महिलाओं के साथ इसने बलात्कार किया था. बाद में नकली नक्सली बनकर व्यापारियों और धनी किसानों से पैसा वसूल लेता था. इसके अत्याचारों से तंग आकर जनता ने इसे पकड़ लिया और जन अदालत में सुनवाई की गई. जनता की सहमति से इसे मौत के घाट उतार दिया गया. इसी इलाके के कोड़ियूर रेंज उमला गांव के टमकू पटेल पुलिस मुखबिरी के साथ-साथ गांव में दादागिरी करता था. इसके घर पर जनता ने आर्थिक हमला कर सारी सम्पत्ति जब्त की.

माड़ डिवीजन के करेलघाट इलाके के बागडोंगरी में 12 अगस्त को छापामार दस्ता जनता को संगठित करने के काम में गया हुआ था. इसकी सूचना पुलिस को दी थी बाजूराम ने. बाजूराम 8वीं कक्षा तक पढ़ा एक आवारागर्द युवक था. चोरी, गुण्डागर्दी और पुलिस मुखबिरी करना उसका पेशा था. पुलिस का वह गोपनीय सैनिक था. तीन गाड़ियों में आई पुलिस ने दस्ते पर हमला किया, पर दस्ता मुकाबला करते हुए बच निकलने में कामयाब हो गया. इसके तुरन्त बाद इस नीचतापूर्ण कार्रवाई के लिए जिम्मेदार बाजूराम को जनता के सहयोग से पकड़ कर जन अदालत बुलाई गई. 8 गांवों से आए 400 लोगों के समक्ष पंचायत ने उसे मार डालने का फैसला सुनाया. उस पर तत्काल ही अमल किया गया. ✶

खूंखार कमाण्डो दरोगा धर्मा सूर्जागड़े का पीएलजीए के हाथों सफाया

गड़चिरोली जिला, एटापल्ली तहसील के देवदा गांव का निवासी धर्मा सूर्जागड़े को एक खूंखार जानवर कहना उचित है. 1990 में महाराष्ट्र सरकार ने सी-60 क्रैक कमाण्डो बल के नाम से बदनाम आतंकी बल का गठन किया था, उसमें सूर्जागड़े एक दरोगा था. 1992-94 के दमन दौरान गड़चिरोली जिले में झूठी मुठभेड़ों में कम से कम 40 आदिवासियों की हत्या की गई थी, जिसमें सूर्जागड़े का हाथ भी था. एक समय में साल भर के अन्दर भामरागड़ दस्ते का सफाया करने की डींग मारते हुए कई आतंकी हमले करने वाले इस जुल्मी अधिकारी को पीएलजीए ने आखिरकार 31 अक्टूबर 2005 को सही ठिकाने पहुंचा दिया. इसने जनता पर अनगिनत अत्याचार किए. कई क्रान्तिकारियों के परिवारों पर दबाव डालकर आत्मसमर्पण करवाने की नाकाम कोशिश की. इसके नेतृत्व में कमाण्डों ने कई महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया था. इस दरिंदे व कातिल की मौत पर गड़चिरोली जिले की जनता ने खुशियां मनाईं - पीएलजीए योद्धाओं का अभिनन्दन किया. ✶

(..... पेज 41का शेष)

पेरकेवार नामक एक मासूम व्यक्ति की पुलिस ने निर्मम हत्या कर उसे नक्सली घोषित किया. उसका कसूर यही था कि उसने उसकी पत्नी के साथ अवैध सम्बन्ध स्थापित करने वाले पुलिस थानेदार का विरोध किया था. इसके अलावा टिप्रागढ़ इलाके में तीन महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद गोली मारकर हत्या की. बाद में मुठभेड़ की कहानी गढ़ दी. अहेरी और सिरोंचा तहसीलों में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया. खेतों में काम करने वाले लोगों को पकड़कर झूठे केसों में फंसाकर जेलों में भेजने की घटनाएं बढ़ी हैं. इससे किसानों की खेती-बाड़ी बुरी तरह प्रभावित हो रही है. अहेरी क्षेत्र के चलेवाड़ा गांव पर हर दो दिन एक बार पुलिस छापेमारी करती है. एक-एक बार तो 150 पुलिस वाले पूरे गांव की घेराबन्दी कर धावा बोलते हैं. गांवों पर छापेमारी करने के लिए जाते समय पुलिस वालों का काफिला 16 वाहनों का होता है, मानों वे किसी दुश्मन देश पर सशस्त्र हमला बोलने जा रहे हों. इसके अलावा दमन की आड़ में लोगों से रिश्वत वसूलने की घटनाएं भी बढ़ी हैं. चेलवाड़ा के एक निजी आरएमपी डॉक्टर को यह धमकी देकर कि उसे नक्सलियों के साथ सम्बन्ध होने के बहाने गिरफ्तार करेंगे, 5 हजार रुपए ऐंठ लिए. सुद्दागुण्डम गांव के पास बारूदीसुरंग बिछाने में शामिल होने का झूठा आरोप लगाकर सात लोगों से एक-एक हजार रुपए ऐंठ लिए. इस तरह लोगों को शारीरक, आर्थिक व मानसिक यातनाएं बड़े पैमाने पर दी जा रही हैं.

गड़चिरोली डिवीजन के टिप्रागढ़ इलाके में दमन के विरोध में जनता ने 3 गांवों में मशाल जुलूस निकाले. तीन जगहों में मिलाकर कुल 600 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया. जुलूसों के अन्त में सभाएं हुईं जिन्हें पार्टी और जन संगठन नेताओं ने सम्बोधित किया.

दण्डकारण्य की संघर्षशील जनता ने पाशविक दमन के बीचोबीच भी संघर्ष का परचम ऊंचा उठाए रखा है. जनता अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर लुटेरी सरकार के खिलाफ कई संघर्ष कर रही है. वर्तमान जनयुद्ध में बड़ी संख्या में नौजवान शामिल हो रहे हैं और दुगुनी नफरत से लुटेरे शासक वर्गों के खिलाफ लड़ रहे हैं. जनता के संगठित संघर्ष ही सरकारी दमन को मात दे सकते हैं. ✶

उत्तरी रीजनल ब्यूरो का संदेश

भारतीय जनता की आशा-भरोसा के एक केन्द्र - दण्डकारण्य के ऐतिहासिक क्रान्तिकारी आन्दोलन की 25वीं वर्षगांठ जिन्दाबाद !

दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन की 25वीं वर्षगांठ सामने है। नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम की महान क्रांतिकारी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए आज से 25 वर्ष पहले भारत के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन की एक शानदार धारा – एम-एल धारा के एक सर्वप्रमुख प्रतिनिधि सी.पी.आई.(एम-एल)(पी.डब्लु.) के कामरेडों ने दण्डकारण्य में जिस क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात किया था, उसने आज उतार-चढ़ावों के दौर से गुजरते हुए पूरे भारत को रौशन करने वाले एक विशाल प्रकाश-पूंज का रूप ले लिया है।

ऐसे में याद आता है 1980 का साल। हमारी प्रिय मातृभूमि – भारतवर्ष की मुक्ति के फौलादी संकल्पों से लैस गिने-चुने, पर सर्वस्वत्यागी छात्र-युवाओं का जत्था निकल पड़ा था दण्डकारण्य के घनघोर जंगलों में। नई अनजानी जगह, अनजाने लोग, अनजाना परिवेश। पर दिलों में जनता पर अगाध भरोसा, उतना ही भरोसा मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद पर, खुद पर और पार्टी पर। सारी अपनी ऊर्जा, क्षमता, प्रतिभा को झोंक दिया था तेलंगाना और श्रीकाकूलम की झंडाबरदार इस नयी पीढ़ी ने। इनके खून-पसीने से तर हो गई थी दण्डकारण्य की महान धरती। सदियों से घनघोर अंधेरे का सीना चीरकर दण्डकारण्य की जनता को दिखा पाये ये लोग मुक्ति का सपना, क्रांति का सपना, इस यातनाप्रद जिन्दगी को बदलकर एक खुशहाल और सम्मानित जिन्दगी जीने का सपना। इस तरह इस पीढ़ी ने दण्डकारण्य की महान क्रांतिकारी जनता के दिलों में मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद का जो बीज डाला था और जिन्हें सालों-साल अपने सैकड़ो महान शहीदों के खून से सींचती रही, वही बीज आज वहां की जनता के बीच उर्वर भूमि पाकर विशाल वटवृक्षों में बदल गये हैं।

सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी संघर्षों के विकास-विस्तार के जरिए इलाके के आधार पर नव जनवादी राजसत्ता के निर्माण का सपना अब महज सपना नहीं रह गया है। आज सचमुच ही जनता की अपनी सेना पी.एल.जी.ए. की बहादुराना लड़ाइयों और वहां की महान क्रांतिकारी जनता की विशाल गोलबंदी व सक्रिय पहलकदमी के बल पर दण्डकारण्य की धरती पर सामंती-साम्राज्यवादी राजसत्ता और उसकी राजमशीनरी को चकनाचूर करते हुए वास्तविक रूप ले रही है नव जनवादी राजनीतिक सत्ता, गठित हो रही है 'जनताना सरकार'। सदियों से शोषित-उत्पीड़ित और निपट व गंवार समझी जाने वाली दण्डकारण्य की जनता अपनी बुद्धि व ताकत के भरोसे चला रही है भरी-पूरी सुव्यवस्थित विभिन्न विभागों वाली एक बाजाप्ता जन सरकार। इसके जरिए वे भूमि-सुधार कर रहे है, विकास-कार्य कर रहे हैं, शिक्षा-अभियान चला रहे हैं, कृषि व सिंचाई के साथ-साथ अन्यान्य निर्माण-कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य व सफाई कार्यक्रम चला रहे हैं तथा चला रहे हैं सहकारी संस्थाएं और परस्पर सहायता टीम। इससे लोकयुद्ध में भी एक नई गति का संचार हो रहा है। इस तरह साम्राज्यवाद, सामंतवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के चंगुल में फंसे एक पराधीन और निरंकुश भारत की प्रतिक्रियावादी राजसत्ता और सरकार के एक सच्चे, क्रांतिकारी व जनपक्षीय विकल्प के रूप में उभर रहा है दण्डकारण्य। अठखेलियां कर रहा है स्वाधीन व जनवादी भारतवर्ष की क्रांतिकारी राजसत्ता और जनता की सच्ची सरकार का एक गर्भस्थ शिशु।

दण्डकारण्य, झारखण्ड, आन्ध्र, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत समूचे भारतवर्ष में पांव पसारती जा रही इस नई जनवादी राजसत्ता ने आज प्रतिक्रियावादी राजसत्ता के होश उड़ा दिये हैं। बदहवास होकर वे उसे कुचल डालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। सुधार-कार्यक्रमों, सलवा जुडुम, सेंदरा, ग्राम सुरक्षा दल और जन-जागरण अभियान जैसे अभियानों तथा एक-पर-एक क्रूर व हिंस्र घेरा डालो और विनाश करो की मुहिमों के जरिए वे संघर्षशील जनता को, उसकी 'जनताना सरकार' को, पी.एल.जी.ए. को तथा उसकी नेतृत्व कर रही हमारी पार्टी को विनष्ट करने पर पूरी तरह उतारू हो गये हैं। पर उनके इन तमाम दमन व षड़यंत्रों को परास्त करती इस वैकल्पिक सत्ता के नये सूरज की सुनहली किरणों से जगमगाती जा रही है हमारी प्रिय मातृभूमि।

हम अपने उत्तरी रिजनल ब्युरो के सभी पार्टी संगठनों, पी.एल.जी.ए. की सभी शक्तियों के कमांडरों व सहायक कमांडरों और योद्धाओं, जनसंगठनों व मोर्चा संगठनों तथा अपने कार्यक्षेत्र की करोड़ों-करोड़ महान क्रांतिकारी जनता की ओर से दण्डकारण्य की इस उभरती व विस्तृत होती जा रही 'जनताना सरकार' का स्वागत करते हैं और इस महान क्रांतिकारी आंदोलन, जो आज भारत की करोड़-करोड़ जनता की आशा-भरोसा का एक केन्द्र बन गया है, की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर उसे हार्दिक शुभकामना भेजते हैं। साथ ही हम इस आंदोलन की तथा इसके जरिए उभर रही 'जनताना सरकार' की रक्षा करने के लिए और इसे पूरे भारत में फैला देने के लिए सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी छापामार लड़ाई को उत्तर-भारत के कोने-कोने में विस्तृत करने और उसमें करोड़ों-करोड़ जनता को शामिल कर एक ऐसे सच्चे दीर्घकालीन लोकयुद्ध का निर्माण करने का संकल्प लेते हैं जो मुक्त, स्वाधीन और जनवादी भारतवर्ष को एक नये भारतवर्ष का निर्माण करेगा।

क्रांतिकारीअभिवादनकेसाथ,

सचिव

उत्तरी रीजनल ब्युरो

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

8-10-2005

गिरीडीह और जहानाबाद में पीएलजीए के शानदार हमले प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों के होश उड़े

महान रूसी क्रान्ति की 88वीं वर्षगांठ को बिहार–झारखण्ड में जन मुक्ति छापामार सेना के लाल योद्धाओं, बहादुर कमाण्डरों, पार्टी कतारों, क्रान्तिकारी जन संगठनों तथा शोषित अवाम ने एक अनोखे व जबर्दस्त अंदाज में मनाया. झारखण्ड के गिरीडीह और बिहार के जहानाबाद जिला मुख्यालयों में पीएलजीए ने क्रमशः 11 और 13 नवम्बर को जबर्दस्त हमले किए. कोरापुट और मधुबन के बाद पीएलजीए के शूरतापूर्वक कारनामों के दास्तान में अब दो नाम और जुड़ गए हैं – गिरीडीह और जहानाबाद. ये दोनों ही हमले राजनीतिक व फौजी तौर पर काफी महत्वपूर्ण थे. कुछ समय पहले झारखण्ड में और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में क्रमशः 'सेन्देरा' और 'सलवा जुडूम' के नाम से चलाए जा रहे जुल्मी दमन अभियानों को लेकर प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों के तलवे चाटने वाली मीडिया तरह–तरह की झूठी खबरें परोस रही थीं. भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में देश के अनेक हिस्सों में जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन का सफाया करने की मंशा से कई योजनाएं तैयार की जा रही थीं. केन्द्रीय गृह मंत्रालय की अगुवाई में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और आला पुलिस–प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही थीं. और पुलिस व अर्ध सैनिक बल जनता पर हत्या, बलात्कार और आतंक का ताण्डव मचा रहे हैं. इस पृष्ठभूमि में पीएलजीए के लाल योद्धाओं के द्वारा सुनियोजित तरीके से किए गए इन हमलों ने जहां भारत के तमाम शोषित अवाम को बेहद उत्साहित किया, वहीं दूसरी तरफ लुटेरे शासक वर्गों की नींदें उड़ा दीं. ये दोनों ही स्थान जिला मुख्यालय थे. इससे खासकर 21 सितम्बर 2004 को भाकपा (माओवादी) के गठन के बाद से पीएलजीए की बढ़ी हुई ताकत व आत्मविश्वास की झलक मिल जाती है. इन सफल व शानदार हमलों को अंजाम देने वाले पीएलजीए के बहादुर कमाण्डरों, लाल योद्धाओं और बिहार–झारखण्ड की लड़ाकू जनता का 'प्रभात' लाल अभिनन्दन करती है. पीएलजीए की इस शानदार कार्रवाई के बदौलत जहानाबाद जेल से रिहा हुए तमाम क्रान्तिकारियों को हमारी शुभकामनाएं !

गिरीडीह हमले की सफलताएं

- ✶ 185 हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त
- ✶ 5 जवानों का सफाया – डेढ़ दर्जन घायल
- ✶ हजारों कारतूस और विस्फोटक सामग्री पर पीएलजीए का कब्जा

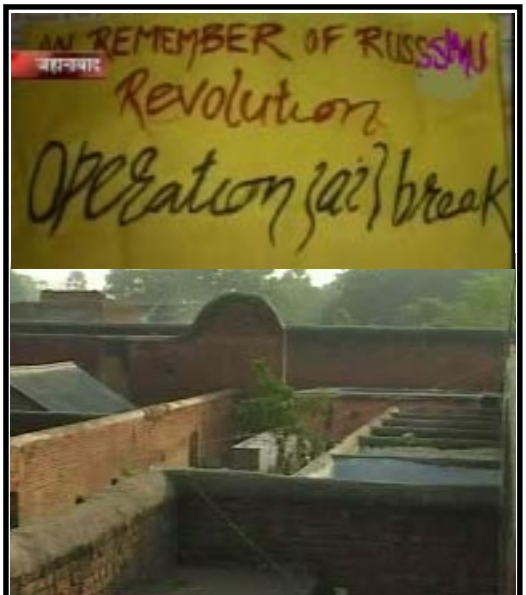

जहानाबाद हमले के बाद छोड़े गए पोस्टर (ऊपर); जहानाबाद का जेल (नीचे)

मिली खबरों के मुताबिक 11 नवम्बर की शाम के 4 बजे सैकड़ों पीएलजीए सैनिकों और लड़ाकू जनता ने गिरीडीह जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पचंबा होमगॉर्ड प्रशिक्षण केन्द्र पर धावा बोला जहां 300 होमगॉर्ड तैनात थे. बिजली की तेजी से उन्होंने वहां 5 जवानों का सफाया कर, कुछ को घायल कर बाकी लोगों को काबू कर लिया. वहां से पीएलजीए ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया. ठीक उसी समय पीएलजीए के एक और जत्थे ने सेंट्रल कोल फील्ड्स के बारूद डिपो पर भी हमला किया और वहां से काफी मात्रा में विस्फोटक सामग्रि जब्त कर ली. कुछ ही घण्टों में यह हमला कामयाबी के साथ सम्पन्न हो गया. हालांकि पुलिस वाले रात भर हवा में गोलियां चलाते रहे.

जहानाबाद हमले की सफलताएं

- ✶ वरिष्ठ माओवादी नेता कॉमरेड अजय कानू समेत 341 बन्दियों की रिहाई
- ✶ प्रतिक्रियावादी रणवीर सेना का खूंखार नेता बड़ा शर्मा का सफाया
- ✶ पुलिस के 8 हथियार और सैकड़ों गोलियां जब्त

गिरीडीह लड़ाई की सफलता के दो दिन बाद ही पीएलजीए की एक और सफलता की खबर ने क्रान्तिकारी कतारों व मेहनतकश जनता को खुशी से गद्गद कर दिया. 13 नवम्बर की रात के सवा नौ बजे सैकड़ों पीएलजीए सैनिकों ने जहानाबाद में एक साथ जेल, पुलिस लाइन और थाने पर धावा बोल दिया. पीएलजीए के कमाण्डरों ने लाउड स्पीकरों में ऐलान किया कि 'हमारी लड़ाई पुलिस–प्रशासन तथा प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों के खिलाफ है.' इस हमले का मुख्य उद्देश्य जेल में कैद माओवादी क्रान्तिकारियों को आजाद कराना और रणवीर सेना के कुछ कट्टर गुण्डों को दण्डित करना था. इस कार्रवाई का नाम 'आपरेशन जेल ब्रेक' रखा गया. इसमें जेल में तैनात पुलिस कर्मियों से 8 रायफलें छीन ली गईं और एक का सफाया किया गया. पीएलजीए सैनिकों ने जेल के अन्दर घुसकर वरिष्ठ माओवादी नेता कॉमरेड अजय कानू समेत 341 बन्दियों को रिहा कराया. प्रतिक्रियावादी रणवीर सेना का एक खूंखार सरगना बड़ा शर्मा को वहीं गोली मार दी.

जहानाबाद का हमला भारत में कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों द्वारा किसी जेल पर किया गया प्रथम व भारी हमला है. यह भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. ✶

2 दिसम्बर – पीएलजीए की 5वीं वर्षगांठ जोरदार ढंग से मनाओ !

चंदौली, मधुबन, पोंजेरा, गिरीडीह, जहानाबाद, आदि
बहादुराना लड़ाइयों की दास्तान गांव–गांव और घर–घर सुनाओ !!

लुटेरे शासक वर्गों के अव्वल नम्बर दलाल व फासीवादी नेता महेन्द्र कर्मा की अगुवाई में

'जन जागरण' के नाम पर जारी 'जन संहरण' अभियान को शक्तिशाली जन प्रतिरोध के जरिए परास्त करो !

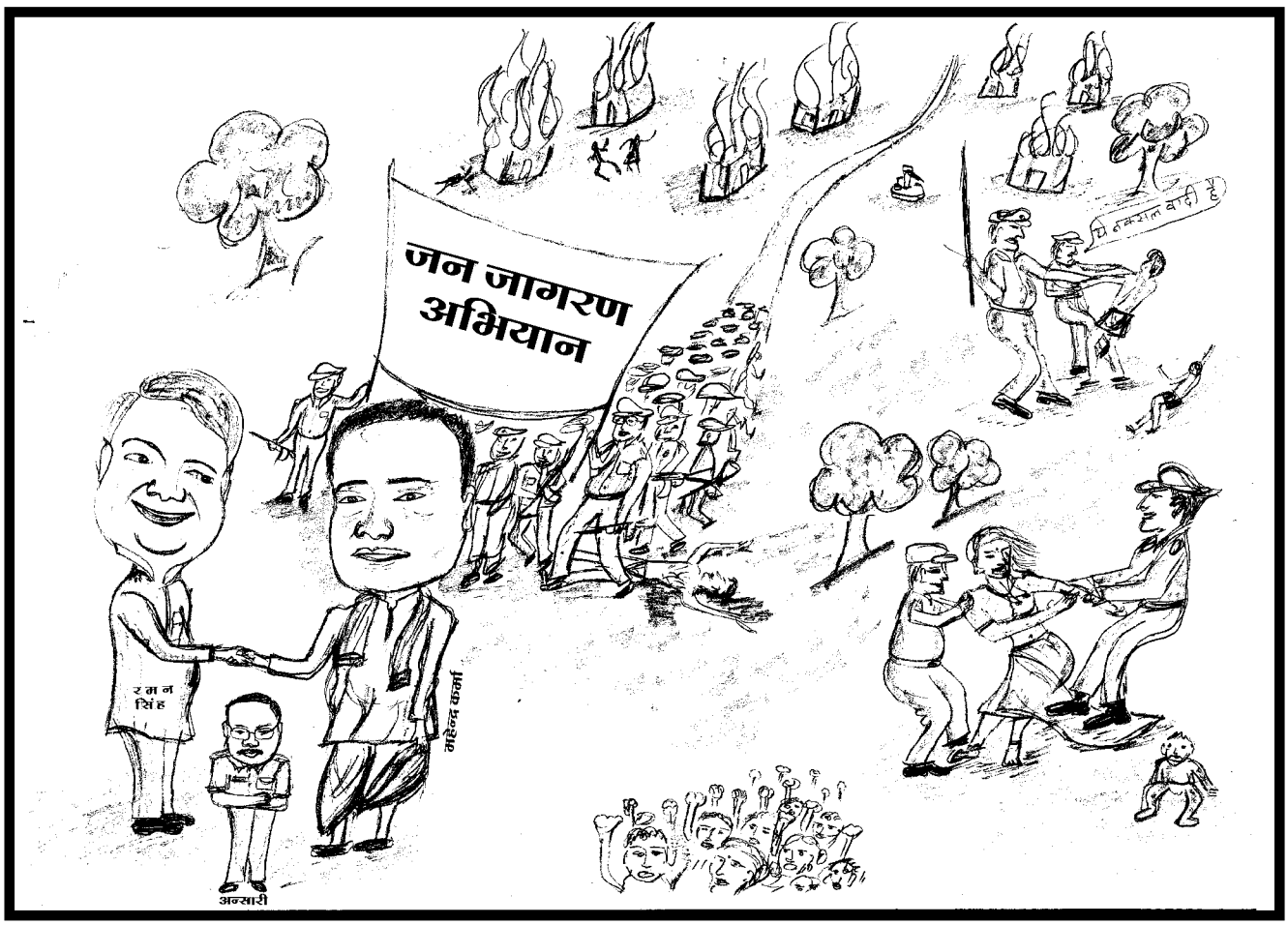

हत्या, बलात्कार, लूट, आगजनी व आतंक का पर्याय बने 'सलवा जुडूम' के गुण्डों, पुलिस व अर्ध सैनिक बलों को मार मार के बस्तर से बाहर भगा दो !